RNI No.: UTTHIN/2004/24305

वर्ष: 22, अंक: 7, जुलाई 2026

जन जन तक

www.janjantak.com

मूल्य - ₹15

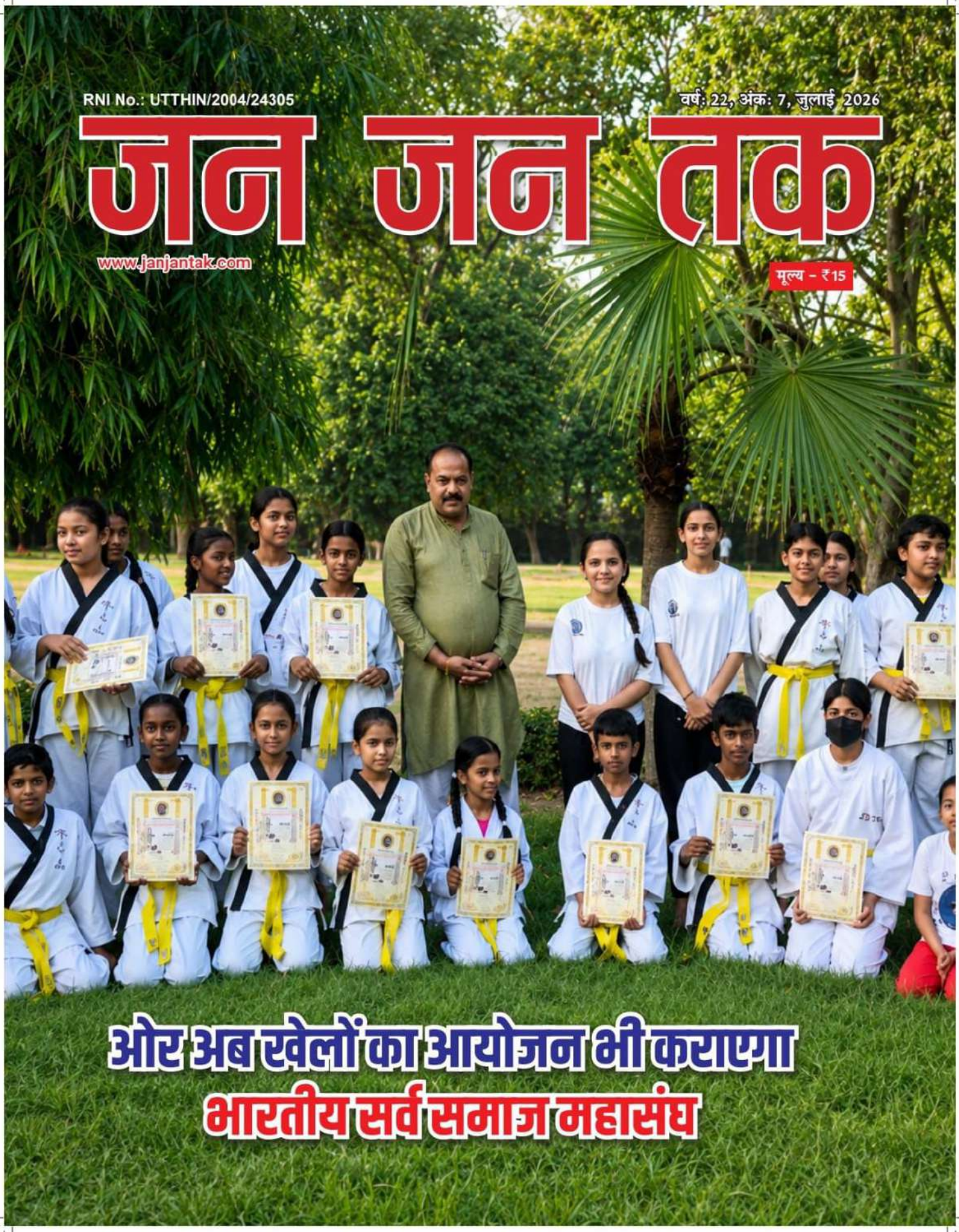

ओर अब खेलों का आयोजन भी कराएगा भारतीय सर्व समाज महासंघ

तुरंत खबरें जानने हेतु,
मनोरंजक पोस्ट पाने हेतु,
मजाकिया वीडियो, प्रेरणात्मक
पोस्ट, एक से एक फोटो, कहानियां,
किस्से व अन्य बहुत कुछ
अपने फेसबुक में रोज पाने हेतु
आज ही लाईक करें, लोकप्रिय पेज

जन जन तक

12,000,00

बारह लाख

हमें पसंद करते हैं। धन्यवाद्।
हम भी आपको बहुत पसंद करते हैं।

www.facebook.com/janjantakmagazine

बिजनेस जन जन तक

आपका जन मीडिया आपके लिए आपके द्वार आपके ही अपने बिजनेस/प्रोडक्ट्स के प्रचार प्रसार हेतु
मीडिया कंस्लटिंग तथा जन जन तक
मगजीन की यो सोशल मीडिया के माध्यम से आपके बहुत से प्रॉडक्ट्स बहुत कम दामों पर लाखों के बीच पहुंचाने हेतु तत्पर हैं। आप जन जन तक के फेसबुक पेज व यूटयूब चैनल से जुड़कर लाखों तक पहुंच सकते हैं।

For promotions contact +91 9958558079
or email at janjantakmagazine@gmail.com

चढ़ावे की चोरी... >>03

कानून का चकमा देने का... >> 08

किरदार को ऑब्जेक्टिफाई... >>46

सनातन व नारी सम्मान... 10
चिन्ताजनक है महंगी होती... 12
युवा की आवाज... 14
पंजाब के सरकारी स्कूलों में... 18
मेक इन इंडिया का... 20
अब 62 वर्ष में होगी सेवानिवृत्ति... 24
एमपी में यूसीसी ड्राफ्ट की... 38
दोबारा लौट रहे लोग लकड़ी... 40
1 जुलाई 2026 से पासपोट... 42
राशिफल... 48

पत्रिका के सदस्य बनें घर बैठे पत्रिका पायें नियमित लाभ कमायें

पत्रिका द्वारा अपने नियमित सदस्यों/ग्राहकों के लिए अनेक लाभकारी योजनाएं चलाई हुई हैं जिसके अंतर्गत सदस्यों को नियमित नकद पुरस्कार एवं अन्य भेंट दी जाती है। अतः ₹400 का चैक भेजकर पत्रिका के नियमित सदस्य बनें लेख सुझाव कहानी भेजें, चयनित होने पर नकद पुरस्कार पायें तथा लाभ उठाएं।

जन जन तक पत्रिका की बढ़ती लोकप्रियता

जन जन तक पत्रिका की लोकप्रियता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वर्तमान में देश-विदेश के राजनेता हों, अधिकारी वर्ग हों, व्यापारी हों, बुद्धिजिवी हों या वह आम जनमानस हों सभी पत्रिका की सराहना कर रहे हैं तथा देश-विदेश में भी पत्रिका की मांग बढ़ती जा रही है।

धीरे-धीरे मोदी सरकार ने तीन साल पूरे कर लिए हैं। इस दौरान दो बातें हुईं। पहली ये कि भ्रष्टाचार का कोई बड़ा मामला सामने नहीं आया है। दूसरे वैश्विक स्तर पर भारत एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है और पीएम मोदी के कारण इसे व्यापकता मिली है। लेकिन प्रशासनिक भ्रष्टाचार में कमी आई हो, बेराजगारी दूर हुई हो, महंगाई में कमी आई हो, आर्थिक विकास की दर में कोई सुधार हुआ हो, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई क्रांतिकारी काम हुआ हो, आतंकवाद या नक्सली वारदात में कोई कमी आई हो ऐसा भी नहीं हुआ तो फिर पीएम मोदी और उनकी सरकार अच्छे दिन का हल्ला क्यों मचा रही है। मोदी सरकार अपनी नाकामी को इस यह तर्क देकर बरगलाने की कोशिश नहीं कर सकती कि पिछले सत्तर सालों में देश बदहाल हो गया था जिससे उभरने में उसे वक्त लगेगा। क्योंकि आज देश में जितना भी विकास हुआ है वो कांग्रेस के शासन में ही हुआ है। क्योंकि अभी तक एक भी ऐसा बड़ा काम नहीं हुआ जिससे देश की जनता या दुनिया में मोदी सरकार की उपलब्धि के रूप में गिनाया जा सके। कांग्रेस सरकार में शुरू हुए काम के फीते काटकर या उनकी बनाई योजनाओं के शिलान्यास करके मोदी सरकार अपने किए हुए वायदों से मुकर नहीं सकती।

पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, बुराड़ी (दिल्ली)

जन जन तक पत्रिका के पिछले अंक की भी लोगों ने काफी सराहना की है। देश की मुख्य हस्तियों से लेकर आम जनमानस तक के हमारे कार्यालय में सैंकड़ों पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ को हमने प्रकाशित भी किया है। सभी पत्रों को प्रकाशित करना सम्भव नहीं है। यदि आप भी कोई सुझाव, लेख हमें लिखना चाहते हैं तो लिख भेजिए। पसंदीदा लेख को हम पत्रिका में प्रकाशित भी करते हैं। हमने इस पत्रिका के माध्यम से समाज में जन जागरूकता लाने का बीड़ा उठाया है, आईए आप भी इस नेक कार्य में हमारे सहयोगी बनें। —संपादक

आर. के वालिया - मुख्य संपादक / चैयरमेन
(09868347267)
प्रमिला देवी - संपादक
(011-26197882)
आकाश कुमार (MBA) - प्र. वितरण
(09910522496)
वैभव (MBA) - प्र. प्रकाशन/प्रशासन/विज्ञा0
(09958558079)
स्वाति (MBA) - प्र. प्रकाशन/प्रशासन/विज्ञा0
(09958558079)
श्याम बाबू - डिजाइनर एवं ग्राफिक्स
(09560680773)
आशीष कुमार- दिल्ली (08423322673)
पंकज गुप्ता का. सलाहकार (09897772270)
मो. अमीनुद्दीन - प. बंगाल (09831094955)
अवधेष चैधरी-कोलकाता (09477317030)
सतीष खण्डेलवाल चण्डीगढ़ (9888136488)
विवेक गुप्ता- मुम्बई (07738744327)
विजय राठौड़- दिल्ली (7827147921)
अनु वालिया- हरिद्वार (9760981160)
आजाद हुसैन - गोरखपुर (09506574923)
पार्थसारथी मल्लिक - भुवनेश्वर (09938160802)
बृजेष पांडे - रायपुर (09893782571)
पंकज सैनी - देहरादून (0135-2628137)

प्रतिनिधि/संवाददाता

दिल्ली - मनोज पुण्डीर, यषपाल विजय राठौड, अमित कुमार
जयपुर- गीता ठाकुर
पटना - बुद्धिदेव झा
लखनउ- संदीप सैनी
भोपाल- कमल शर्मा
हैदराबाद - फईम मुईस
सिवान, बिहार - रणजीत प्रसाद रजक
ढांका- जूवेदा खातून
षिमला - विजय बहादुर सिंह मेहरा हिमाचल प्रभारी
देहरादून - राजीव अग्रवाल
हरिद्वर - अनुराग कुमार
ऋषिकेष- टी.एन. तिवारी
नैनीताल/कु.म. - डी.एन.बडोला
बिलासपुर- विपिन श्रीवास्तव

कॉर्पोरेट कार्यालय

डी 191 अर्जुन नगर, ऑपोजिट बड़ा गुरूद्वारा सफदरजंग एनक्लेव
नई दिल्ली - 110029 फोन/फैक्स- 011-26197882, 65161922
मो.- 9868347267, 9958558079

प्रधान कार्यालय देहरादून

क्षे. का. प्रभारी, जन जन तक पत्रिका-48 इंद्रापुरम, जीएमएस रोड,
देहरादून, उत्तराखंड फोन/फैक्स - 0135-2628127 मो- 9760639920
क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता- क्षे. का. प्रभारी, जन जन तक 48/बी/एच 29
कार्ल मार्क्स सरानी, कोलकाता - 23
क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ - 237/2 सेक्टर 41-ए, चण्डीगढ़
क्षेत्रीय कार्यालय हरिद्वार - दूधाधारी चैक ऋषिकेष रोड हरिद्वार
Email- janjantakmagazine@gmail.com

"जन जन तक" के स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक श्रीमती प्रमिला देवी द्वारा प्रकाशन स्थल 48, इंदिरापुरम, शक्तिएंक्लेव, जीएमएस रोड, देहरादून से प्रकाशित एवं मुद्रण स्थल सरस्वती प्रेस, 02, ग्रीन पार्क, निरंजनपुर, जिला-देहरादून, उत्तराखंड-248001 से मुद्रित।

© सर्वाधिकार सुरक्षित

इथेनॉल का मोल

खाड़ी युद्ध के चलते उपजे ईंधन संकट ने भारत समेत पूरी दुनिया को सबक दिए हैं कि देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिये नये विकल्प तलाशे जाएं। भारत जैसे देश के लिये तो यह बड़ी चुनौती है क्योंकि हम पूरी तरह कच्चे तेल व गैस के लिये विदेशी संसाधनों पर ही निर्भर हैं। जिससे संकटपूर्ण स्थितियों में न केवल महंगाई बढ़ती है बल्कि हमारी दुर्लभ विदेशी मुद्रा भी दांव पर लगती है। ऐसे ही संकट से जूझने के लिये देश ने इथेनॉल के विकल्प पर गंभीरता से विचार किया। देश में पहले ही सामान्य पेट्रोल में बीस फीसदी इथेनॉल मिलाया जा रहा है। देश में विदेशी मुद्रा की बचत व आत्मनिर्भरता की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है। हाल ही में फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों के लिये ज्यादा इथेनॉल वाले ई-85 फ्यूल उपलब्ध कराया गया। लेकिन अभी भी उपभोक्ताओं और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के बीच कई मुद्दों को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। दरअसल,ये वाहन ई-85 यानी 85 फीसदी इथेनॉल और 15 फीसदी पेट्रोल तथा ई-100 यानी शुद्ध इथेनॉल वाले मिश्रण पर चलने के लिये डिजाइन किये गए हैं। जबकि पेट्रोल से चलने वाली सामान्य गाड़ियां ई-20 यानी बीस फीसदी इथेनॉल और 80 फीसदी पेट्रोल के अनुकूल होती हैं। दरअसल, चुनिंदा आउटलेट्स पर ई-85 उपलब्ध कराने का निर्णय आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने के मकसद से लिया गया है। यह एक हकीकत है कि आज भी देश का नब्बे फीसदी कच्चा तेल आयातित किया जा रहा है। दुनियाभर में गाहे-बगाहे पैदा होने वाले भू-राजनीतिक संकटों ने बार-बार देश के ऊर्जा इकोसिस्टम की खामियों को ही उजागर किया है। इसमें दो राय नहीं है कि फ्लेक्स-फ्यूल गाड़ियों के लिये इथेनॉल को मुख्य ईंधन के रूप से बढ़ावा देने का मकसद ऊर्जा जरूरतों में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में बढ़ना है। वहीं दूसरी ओर इसके उपयोग से हम ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कमी ला सकते हैं। निश्चय ही वाहनों में इथेनॉल को बढ़ावा देना देश में आयातित कच्चे तेल के दबाव को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। लेकिन इस बदलाव को सिरे चढ़ाने के लिए बहुत सोच-समझकर आगे बढ़ना चाहिए, जिससे लोगों की आशंकाएं दूर हो सकें। जरूरत लोगों का भरोसा हासिल करने की है। भारत में इथेनॉल मिले तेल के उपयोग ने इससे होने वाले तमाम फायदों को साबित किया है। इससे काफी विदेशी मुद्रा की बचत भी हुई है। साथ ही देश में इथेनॉल का सशक्त उद्योग विकसित हुआ है। यदि बाजार में इथेनॉल पर लोगों का भरोसा बढ़ता है और इसकी मांग बढ़ती है तो इससे किसानों को कमाई के नये अवसर मिल सकते हैं। इथेनॉल की ज्यादा मांग होने पर गन्ने और मक्का का बाजार विस्तार लेगा। वहीं दूसरी ओर ई-85 की कीमत पारंपरिक पेट्रोल के मुकाबले कम रखने के फैसले से, उन उपभोक्ताओं को फायदा हो सकता है, जिनके पास इसके अनुकूल गाड़ियां है। भले ही इस फ्यूल की ईंधन दक्षता कम हो, लेकिन यह कदम देश की अर्थव्यवस्था को संबल देगा। बहरहाल, इस उम्मीद के साथ ही, हमें हकीकत का भी ध्यान रखना है। दरअसल, ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनियों ने इंजन की क्षमता, जंग लगने, ईंधन सिस्टम पर प्रभाव और इसकी दीर्घकालिक क्षमता को लेकर चिंताएं जतायी हैं।

चढ़ावे की चोरी

बीजेपी बोली एसआईटी पर भरोसा रखें, जवाब का पलटवार-असली चेहरा बेनकाब

अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला सामने आने के बाद दान के प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। ट्रस्ट ने पहले इनकार किया, लेकिन अब विशेष जांच दल गठित किया गया है ताकि दोषियों को पकड़ा जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। अयोध्या में श्रीराम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का मामला करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला है। सदियों के संघर्ष और प्रतीक्षा के बाद बना यह मंदिर विश्व भर के हिंदुओं की श्रद्धा का केंद्र है। ऐसे मंदिर में चढ़ावे की चोरी की घटना को बहुत ही गंभीरता से लेने की आवश्यकता थी, लेकिन कोई नहीं जानता कि दान की राशि में हेराफेरी की बात सामने आते ही उच्चस्तरीय जांच का निर्णय क्यों नहीं लिया गया? इस मामले में जिस प्रकार एफआईआर दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं समझी गई, उससे अनेक सवाल खड़े होते हैं। यह विचित्र है कि राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी की भनक सबसे पहले विपक्षी नेताओं को लगी और उनकी ओर से आवाज उठाने के बाद ही मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों का ध्यान इस ओर गया। इससे तो यही इंगित होता है कि दान में मिले धन के प्रबंधन की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। कम से कम अब तो ऐसा अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। यह समझना कठिन है कि चढ़ावे की चोरी का मामला सामने आने के बाद ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने इससे इन्कार क्यों किया कि इस तरह की कहीं कोई घटना हुई है? इसके उपरांत जब दान राशि की गिनती से जुड़े लोगों के ठिकानों से लाखों रुपये मिले, तब जाकर इस मामले में थोड़ी गंभीरता दिखाई गई। इनमें से कुछ व्यक्ति तो ऐसे हैं, जिन्होंने महंगी संपत्ति खरीदी और अपने वैभव का सार्वजनिक प्रदर्शन करने में लगे हुए थे। इस सबको देखते हुए यह कहना कठिन है कि दान की राशि में हेराफेरी का सिलसिला पिछले कितने समय से चला आ रहा था। यह ठीक है कि अंततः ट्रस्ट के आग्रह पर एक विशेष जांच दल का गठन कर दिया गया है। यह जांच दल दानपात्रों के सुरक्षा प्रबंध के साथ राशि गिनने और उसे बैंक में जमा करने की प्रक्रिया जांचेगा, लेकिन उचित यह होगा कि यह दल उन कारणों की तह तक भी जाए, जिनके चलते आरंभ में ही चढ़ावे की राशि में हेराफेरी का पता नहीं चल सका। किसी के लिए भी यह समझना कठिन है कि इतने प्रतिष्ठित मंदिर में पहले दिन से ही ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की गई कि दान में मिली पाई-पाई का रखरखाव सही तरीके से हो? किसी को इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए कि प्रारंभ में ही उस कक्ष में सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगाए गए, जिसमें दानपात्रों को खोला जाता था और फिर राशि की गिनती होती थी। उचित यह होगा कि विशेष जांच दल अपनी छानबीन इस तरह करे कि सभी दोषी पकड़े जाएं और ट्रस्ट के जिन भी लोगों ने अपेक्षित जिम्मेदारी का परिचय नहीं दिया, उन्हें भी जवाबदेह बनाया जाए। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि श्रद्धा का कोई भी केंद्र हो, वहां यदि भक्तों के दान की राशि के साथ किसी भी तरह की हेराफेरी होती है तो उनकी आस्था को गहरी चोट पहुंचती है।

मोदी युग के बारह वर्ष
विकास या विनाश?

मोदी युग को भारत की गुम होती सांस्कृतिक अस्मिता की पुनर्स्थापना के लिए भी याद किया जाएगा। सदियों से उपेक्षित राष्ट्रीय प्रतीकों, तीर्थस्थलों और सांस्कृतिक विरासत को नई गरिमा मिली। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण केवल एक धार्मिक घटना नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की सांस्कृतिक चेतना के सम्मान का प्रतीक बना। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में कुछ कालखंड केवल शासन परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चेतना के पुनर्जागरण के लिए याद किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते बारह वर्षों का दौर ऐसा ही एक कालखंड है। यह केवल एक प्रधानमंत्री के लंबे कार्यकाल की कहानी नहीं है, बल्कि उस भारत की कहानी है जिसने स्वयं को नए आत्मविश्वास, नई ऊर्जा और नई वैश्विक पहचान के साथ स्वयं को स्थापित किया है। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। यह उपलब्धि केवल राजनीतिक सफलता नहीं है, बल्कि जनता के उस विश्वास का प्रमाण है जो बार-बार लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्त हुआ है। भारत जैसा विशाल, बहुभाषी, बहुधार्मिक और सांस्कृतिक विविधताओं से भरा देश किसी नेतृत्व को लगातार तीन बार राष्ट्रीय जनादेश दे, यह अपने आप में असाधारण एवं ऐतिहासिक घटना है। मोदी युग की सबसे बड़ी विशेषता केवल विकास नहीं, बल्कि विकास और विश्वास का समन्वय है। नेहरू युग को आधुनिक भारत के निर्माण का काल कहा गया, तो मोदी युग को उस भारत के आत्मविश्वास के पुनर्जागरण का काल कहा जा सकता है। मोदी ने केवल सड़कों, पुलों, हवाई अड्डों और डिजिटल नेटवर्क का निर्माण नहीं किया, बल्कि करोड़ों भारतीयों के मन में यह विश्वास भी जगाया कि भारत किसी से कम नहीं है और वह विश्व मंच पर नेतृत्वकारी भूमिका निभा सकता है। मोदी की सबसे विलक्षण विशेषता यह रही कि उन्होंने राजनीति को केवल सत्ता संचालन का माध्यम नहीं माना, बल्कि उसे जनभावनाओं और राष्ट्रीय आकांक्षाओं से जोड़ा। वे उन विरले नेताओं में हैं जिन्होंने सरकारी योजनाओं को केवल प्रशासनिक दस्तावेज नहीं रहने दिया, बल्कि उन्हें जनआंदोलन का स्वरूप दिया। स्वच्छ भारत अभियान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सफाई का विषय जो कभी सरकारी विभागों तक सीमित था, उसे राष्ट्रीय चरित्र और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ दिया गया। मोदी युग को भारत की गुम होती सांस्कृतिक अस्मिता की पुनर्स्थापना के लिए भी याद किया जाएगा। सदियों से उपेक्षित राष्ट्रीय प्रतीकों, तीर्थस्थलों और सांस्कृतिक विरासत को नई गरिमा मिली। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण केवल एक धार्मिक घटना नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की सांस्कृतिक चेतना के सम्मान का प्रतीक

बना। काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक, केदारनाथ पुनर्निर्माण और सोमनाथ जैसे तीर्थों का विकास यह संकेत देता है कि आधुनिकता और परंपरा एक-दूसरे की विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हो सकती हैं। मोदी की एक और विशेषता यह है कि उन्होंने भारत की विदेश नीति को आत्मविश्वास का नया आयाम दिया। कभी विश्व शक्तियों के बीच संतुलन साधने वाला भारत आज वैश्विक विमर्श को प्रभावित करने वाला राष्ट्र बनकर उभरा है। रूस-यूक्रेन युद्ध हो, पश्चिम एशिया का संकट हो, जी-20 का नेतृत्व हो अथवा वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) की आवाज उठाने का प्रश्न- भारत ने निर्णायक भूमिका निभाई है। यह वही भारत है जिसे कभी विकासशील देशों की कतार में खड़ा माना जाता था, लेकिन आज दुनिया उसकी ओर समाधान प्रदाता राष्ट्र के रूप में देख रही है। इन बारह वर्षों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह भी है कि शासन के केंद्र में पहली बार अंतिम व्यक्ति को रखने का गंभीर प्रयास दिखाई दिया। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, मुफ्त राशन योजना तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैसी योजनाओं ने करोड़ों गरीबों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया। शासन की पारदर्शिता बढ़ी और बिचौलियों की भूमिका सीमित हुई। डिजिटल इंडिया अभियान ने तकनीक को केवल महानगरों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि गांव-गांव तक पहुंचाया। नरेंद्र मोदी की नेतृत्व शैली का एक विशिष्ट पक्ष उनका संकल्पबोध है। वे बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन्हें राष्ट्रीय अभियान का स्वरूप देते हैं। चाहे 370 का उन्मूलन हो, तीन तलाक पर रोक हो, जीएसटी लागू करना हो, महिला आरक्षण विधेयक हो अथवा नक्सलवाद और आतंकवाद के विरुद्ध कठोर नीति-इन सभी निर्णयों में राजनीतिक जोखिम था, लेकिन उन्होंने जोखिम उठाने का साहस दिखाया। यही साहस उन्हें सामान्य राजनेताओं से अलग करता है। हालांकि, किसी भी लोकतांत्रिक शासन की तरह चुनौतियां भी कम नहीं हैं। बेरोजगारी, महंगाई, कृषि संकट, शिक्षा और स्वास्थ्य की बढ़ती लागत, सामाजिक विषमताएं तथा आर्थिक अवसरों का असमान वितरण ऐसे प्रश्न हैं जिनका समाधान अभी अपेक्षित है। भारत यदि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो केवल आर्थिक वृद्धि पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुलभ चिकित्सा, रोजगार सृजन और भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन को भी समान प्राथमिकता देनी होगी। मोदी सरकार के आगामी वर्षों से सबसे बड़ी अपेक्षा यही है कि वह भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपने अभियान को और अधिक प्रभावी बनाए। भारत को ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जहां ईमानदारी अपवाद नहीं, सामान्य व्यवहार बने। शिक्षा और स्वास्थ्य को व्यावसायिक माफियाओं के प्रभाव से मुक्त कर आम नागरिक की पहुंच में लाना भी समय की मांग है। साथ ही उद्यमिता को बड़े औद्योगिक घरानों तक सीमित रखने के बजाय गांवों, युवाओं और महिलाओं तक पहुंचाना होगा ताकि प्रत्येक नागरिक रोजगार खोजने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बन सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुझे अनेक अवसरों पर मिलने और उन्हें निकट से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वर्ष 2007 में, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब गुजरात के आदिवासी अंचल कवांट में पूज्य आदिवासी जैन संत गणि राजेंद्र विजयजी के सान्निध्य में आयोजित एक विराट आदिवासी सम्मेलन में उनसे विस्तृत संवाद का अवसर मिला। उस सम्मेलन में वे केवल औपचारिक अतिथि के रूप में नहीं आए थे, बल्कि अपने संपूर्ण मंत्रिमंडल के साथ उपस्थित होकर आदिवासी समाज के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया था। उसी अवसर पर उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों के शैक्षिक उत्थान हेतु एकलव्य मॉडल

आवासीय विद्यालय को हमारे सुखी परिवार फाउंडेशन को संचालित करने के लिए प्रदान किया तथा आदिवासी विकास की दिशा में ऐतिहासिक 15,000 करोड़ रुपये की वनबंधु कल्याण योजना की घोषणा की। यह उनकी दूरदृष्टि और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की सोच का प्रमाण था। इसी सम्मेलन के दौरान एक अत्यंत रोचक और ऐतिहासिक प्रसंग भी सामने आया। गणि राजेंद्र विजयजी ने नरेंद्र मोदी से कहा-ह्लअब आपको दिल्ली जाना चाहिए और देश की बागडोर संभालनी चाहिए।ह्व उस समय मोदीजी ने सहज मुस्कान के साथ उत्तर दिया-ह्लमुझे दिल्ली कौन ले जाएगा? अपने छोटे-छोटे कार्य स्वयं करना, अनावश्यक तामझाम से दूर रहना, समय का सदुपयोग करना और जिम्मेदारी को सर्वोपरि मानना वहां की प्रशासनिक संस्कृति का हिस्सा बन चुका था। स्पष्ट महसूस होता था कि यह कार्यशैली शीर्ष नेतृत्व की प्रेरणा से विकसित हुई है। नरेंद्र मोदी केवल आदेश देने वाले प्रशासक नहीं हैं, बल्कि अपने आचरण से व्यवस्था को दिशा देने वाले नेतृत्वकर्ता हैं। भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी युवा आबादी है। यदि इस ऊर्जा को कौशल, नवाचार और उद्यमिता से जोड़ा गया तो भारत केवल विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो सकता है।

एनडीए से मिल रहे झटकों से उबरने के लिए कांग्रेस में लौटेंगे

शरद पवार, ममता बनर्जी, जगन मोहन रेड्डी !

दरअसल ममता बनर्जी की स्थिति पहली बार इतनी कमजोर नजर आ रही है। पंद्रह साल तक बंगाल की राजनीति पर एकछत्र राज करने वाली ममता की पार्टी विधानसभा चुनाव में महज अस्सी सीटों पर सिमट गई और भाजपा ने राज्य में पहली बार सरकार बना ली। भारतीय राजनीति इन दिनों एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां पुराने रिश्तों, टूटी महत्वाकांक्षाओं और सत्ता की नई हकीकतों ने विपक्ष की राजनीति को गहरे सवालों के सामने ला खड़ा किया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की करारी हार, महाराष्ट्र में शरद पवार की कमजोर होती पकड़ और उद्धव ठाकरे के सामने खड़ा राजनीतिक संकट अब केवल क्षेत्रीय दलों की परेशानी नहीं रह गया है, बल्कि यह पूरे विपक्ष की दिशा तय करने वाला मुद्दा बन चुका है। इसी पृष्ठभूमि में कांग्रेस में ह्घर वापसीह्व की बहस ने अचानक जोर पकड़ लिया है। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के विलय की अटकलों ने तब तेजी पकड़ी जब ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से मुलाकात की और उसके बाद अभिषेक बनर्जी की राहुल गांधी के साथ लंबी बैठक हुई। हालांकि दोनों दलों ने इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन इस बहस ने एक बड़ा राजनीतिक सवाल खड़ा कर दिया कि क्या भाजपा के खिलाफ मजबूत मोर्चा बनाने के लिए कांग्रेस से अलग हुए नेताओं को अब फिर उसी छतरी के नीचे लौट आना चाहिए। दरअसल ममता बनर्जी की स्थिति पहली बार इतनी कमजोर नजर आ रही है। पंद्रह साल तक बंगाल की राजनीति पर एकछत्र राज करने वाली ममता की पार्टी विधानसभा चुनाव में महज अस्सी सीटों पर सिमट गई और भाजपा ने राज्य में पहली बार सरकार बना ली। चुनावी हार के बाद संकट और गहरा गया। कई विधायक और करीबी सहयोगी भाजपा के संपर्क में चले गए। पार्टी के भीतर अभिषेक बनर्जी को लेकर असंतोष खुलकर सामने आया। पुराने नेताओं ने आरोप लगाया कि जिन्होंने वर्षों तक पार्टी को खड़ा किया, उन्हें किनारे कर दिया गया। कभी कांग्रेस को तुच्छ समझने वाली ममता बनर्जी को आखिरकार उसी कांग्रेस के दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ी। कुछ ऐसी ही कहानी शरद पवार की भी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाकर कांग्रेस से अलग रास्ता चुनने वाले पवार आज अपनी ही पार्टी और चुनाव चिन्ह पर नियंत्रण खो चुके हैं। अजित पवार के विद्रोह ने उनकी राजनीतिक ताकत को बुरी तरह झटका दिया था। उद्धव ठाकरे की हालत भी अलग नहीं है। शिवसेना पर नियंत्रण गंवाने के बाद अब उनके सांसदों में भी टूट हो गयी है। इन घटनाओं ने यह साफ कर दिया है कि जिन क्षेत्रीय दलों को कभी अपने राज्यों में अजेय माना जाता था, वह अब भाजपा के आक्रामक विस्तार और अंदरूनी बिखराव के सामने कमजोर पड़ रहे हैं। इसी माहौल में शिवसेना नेता संजय राउत ने यह विचार उछाला कि कांग्रेस से निकले दलों को फिर से मूल पार्टी में लौट आना चाहिए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले

ने भी इस सोच का समर्थन किया। पहली नजर में यह तर्क मजबूत लगता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भाजपा आज देश की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक ताकत बन चुकी है। कभी केवल सात राज्यों तक सीमित रहने वाली पार्टी अब 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सत्ता का हिस्सा है। विपक्ष बिखरा हुआ है और कई क्षेत्रीय दल कमजोर पड़ चुके हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि ये नेता कांग्रेस छोड़कर गए ही क्यों थे? ममता बनर्जी ने वैचारिक मतभेदों के कारण कांग्रेस नहीं छोड़ी थी। उन्हें लगता था कि कांग्रेस बंगाल में वाम मोर्चे को हराने में नाकाम हो चुकी है। उन्होंने आक्रामक राजनीति का रास्ता चुना और तृणमूल कांग्रेस बनाई। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने चौंतीस साल पुरानी वाम सत्ता को उखाड़ फेंका। शरद पवार ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाकर अलग पार्टी बनाई और महाराष्ट्र में अपनी अलग पहचान कायम की। जगन मोहन रेड्डी ने भी कांग्रेस नेतृत्व से उपेक्षा महसूस करने के बाद नई पार्टी बनाई और कुछ ही वर्षों में आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को लगभग समाप्त कर दिया। आज हालात बदले हैं तो उसकी वजह कांग्रेस की मजबूती नहीं, बल्कि भाजपा का विस्फोटक उभार है। पहले क्षेत्रीय दल कांग्रेस की खाली होती जमीन पर फैलते थे, लेकिन अब उन्हें भाजपा से सीधी टक्कर लेनी पड़ रही है। भाजपा न केवल चुनाव जीत रही है, बल्कि नेताओं, कार्यकताओं और संगठन को भी अपने पक्ष में खींच रही है। यही वजह है कि क्षेत्रीय दलों की जमीन लगातार सिकुड़ रही है। फिर भी सवाल बना हुआ है कि क्या कांग्रेस में वापसी वास्तव में संभव है? क्या ममता बनर्जी या शरद पवार जैसे नेता दशकों तक अपनी पार्टी चलाने के बाद राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खरगे के नेतृत्व में काम करना स्वीकार करेंगे? क्या उनके समर्थक इसे पचा पाएंगे। साथ ही पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी को एक मंच पर साथ काम करते देखना लगभग असंभव लगता है, क्योंकि दोनों की राजनीति ही एक दूसरे के विरोध पर खड़ी रही है। इसके अलावा विपक्षी दल पहले से ही इंडिया गठबंधन के जरिए साथ काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, तृणमूल, समाजवादी पार्टी, द्रमुक, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अलग पहचान बनाए रखते हुए भाजपा को कड़ी चुनौती दी थी। इससे साबित हुआ कि भाजपा के खिलाफ एकजुटता के लिए औपचारिक विलय जरूरी नहीं है। असली समस्या क्षेत्रीय दलों में आपसी प्रतिस्पर्धा की है, जो केवल विलय से खत्म नहीं होने वाली। सच्चाई यह है कि कांग्रेस को केवल बड़े चेहरे नहीं, बल्कि मजबूत संगठन और जमीनी कार्यकताओं की जरूरत है। वहीं ममता बनर्जी, शरद पवार और जगन मोहन रेड्डी जैसे नेताओं की असली ताकत उनकी क्षेत्रीय पहचान और जनता से सीधा जुड़ाव रहा है। इसलिए उनके लिए कांग्रेस में लौटना शायद राजनीतिक आत्मसमर्पण जैसा होगा। विपक्ष की राजनीति का भविष्य किसी औपचारिक विलय में नहीं, बल्कि साझा रणनीति और मजबूत तालमेल में छिपा दिखाई देता है। बहरहाल, फिलहाल इतना तय नजर आता है कि भाजपा के खिलाफ लड़ाई में विपक्षी दलों को साथ चलना ही होगा, लेकिन अपनी अलग पहचान खत्म कर कांग्रेस में समा जाना कई क्षेत्रीय नेताओं के लिए राजनीतिक आत्मघाती साबित हो सकता है। वजह साफ है, कांग्रेस में आखिरकार निर्णय की धुरी एक ही परिवार के इर्दगिर्द घूमती दिखाई देती है। ऐसे में वर्षों की मेहनत से अपनी जमीन तैयार करने वाले क्षेत्रीय क्षत्रप बाद में खुद को हाशिये पर पाकर पछता सकते हैं। जिस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे तक को हर बड़े फैसले पर ह्लहाईकमान से पूछना पड़ेगाह्व कहना पड़ता हो, वहां आंतरिक लोकतंत्र की वास्तविक स्थिति का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है।

संघ, हिंदुत्व व सनातन पर सुनियोजित हमले

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष पुराना सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन है। यदि केरल के तीन विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने संघ की किसी व्याख्यान माला, बौद्धिक चर्चा या सार्वजनिक कार्यक्रम में श्रोता के रूप में भाग ले लिया तो इसे अपराध या पद की गरिमा के विरुद्ध कैसे माना जा सकता है? इसके लिए उन्हें माफी मांगने को क्यों कहा जा रहा है? बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम देखने के बाद संघ, हिंदू तथा सनातन विरोधी ताकतें पुनः पूरी आक्रामकता के साथ सक्रिय हो गयी हैं। जिन जिन राज्यों में विरोधी दलों की सरकारें हैं, उन-उन राज्यों संघ, हिंदुत्व व सनातन के विरुद्ध षड्यंत्र प्रारंभ हो गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बड़ा हमला कर्नाटक से आया जहां कांग्रेसी गृहमंत्री प्रियांक खरगे ने संघ के पंजीकरण व फंडिग पर प्रश्न उठाते हुए, इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलने पर संघ पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी। केरल के नए-नवेले मुख्यमंत्री वी. डी. सतीशन ने केरल के तीन कुलपतियों द्वारा संघ के कार्यक्रम में भाग लेने पर घोर आपत्ति जताते हुए उन्हे नोटिस थमा दी है और तीनों कुलपतियों से माफी मांगने को कहा जा रहा है। इसी बीच सपा के राज्यसभा सांसद जावेद अली ने बयान दिया कि देश का बहुसंख्यक समाज काफी हद तक जहरीला हो गया है। जावेद अली ने कहा कि बीजेपी की वजह से हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच दूरी बढ़ी है। धर्म के आधार पर लोगों का एक दूसरे पर भरोसा टूट गया है। उत्तर प्रदेश में बकरीद के अवसर पर दोस्ती के बहाने असद ने सूर्या को बुलाया और पूरे परिवार ने मिलकर उसकी नृशंस हत्या कर दी तब ये लोग चुप्पी बांधे सूर्या के हत्यारे असद के साथ खड़े हो गए। जब असद का एनकाउंटर हुआ था तब ये मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए असद के लिए फातिहा पढ़ रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष पुराना सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन है। यदि केरल के तीन विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने संघ की किसी व्याख्यान माला, बौद्धिक चर्चा या सार्वजनिक कार्यक्रम में श्रोता के रूप में भाग ले लिया तो इसे अपराध या पद की गरिमा के विरुद्ध कैसे माना जा सकता है? इसके लिए उन्हें माफी मांगने को क्यों कहा जा रहा है? जब कुलपति वामपंथी विचारकों, गांधीवादी या अम्बेडकरवादी कार्यक्रमों में भाग लेते हैं या अन्य सामाजिक संगठनों के कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो उसे ह्लबौद्धिक संवादह्व कहा जाता है किन्तु यदि वही कुलपति संघ प्रमुख का व्याख्यान सुन ले तो उससे माफी मांगने को कहा जाता है। यह दोहरा मापदंड है। विश्वविद्यालय ज्ञान, संवाद और विचार-विमर्श के केंद्र होते हैं, वैचारिक बहिष्कार के नहीं। यदि किसी कुलपति ने मंच से कोई राजनीतिक घोषणा नहीं की, किसी दल का प्रचार नहीं किया, किसी प्रशासनिक निर्णय को प्रभावित नहीं किया, वरन मात्र एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लिया, तो उसे ह्लसंघ कार्यकर्ता के स्तर तक गिर जानाह्व कहना उच्च शिक्षा संस्थानों और कुलपति की गरिमा का अपमान है। लोकतंत्र में असहमति का अधिकार है, लेकिन विचारों से असहमति और व्यक्तियों के बहिष्कार में अंतर होता है। यदि संघ से वैचारिक मतभेद हैं, तो उसका उत्तर विचार से दिया जाना चाहिए, न कि लोगों को कार्यक्रम में जाने से रोककर प्रताड़ित करके। विडंबना यह है कि जो लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और वैचारिक बहुलता की बात करते हैं, वही आज यह तय करना चाहते हैं कि कुलपति किसका व्याख्यान सुन सकते हैं और किसका नहीं। क्या भारत में अब किसी शिक्षाविद् को कोई व्याख्यान सुनने के लिए राजनीतिक अनुमति लेनी होगी? सर्वविदित है कि संघ सौ साल से काम कर रहा है। सब जानते हैं कि संघ क्या करता है। जो सोया है उसे जगाया जा सकता है जो सोने का नाटक करता है उसे नहीं जगाया जा सकता है। संघ की समाज में निश्चित छवि है। संघ अपनी छवि सुधारने के लिए नहीं अपितु समाज के हित में काम करता है। आरोपों का उत्तर देने में संघ समय नहीं व्यर्थ करता है। संघ के स्वयंसेवक समाज में काम करते हैं। संघ बढ़ रहा है तो हर जगह दिख रहा है। संघ की छवि बिगाड़ने वालों का प्रयास करने वालों की अपनी कोई विश्वसनीयता नहीं है। समाज के हर वर्ग के लोग संघ को प्रेम दे रहे हैं। संघ के काम को समाज आशीर्वाद देता है। वर्तमान कांग्रेस जो आज संघ व भाजपा पर प्रतिबंध लगाने का सपना देख रही है उसको ध्यान रखना चाहिए कि यही काम नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी और सोनिया जी तक करने का प्रयास करती रही हैं। प्रियांक जैसा दुस्साहस नेहरू जी ने किया था। वो अपने पत्रों में संघ को खतरा बताते थे और जिन्ना की

कानून का चकमा देने का अनैतिक खेल है दल बदल

शिवसेना यूबीटी के नौ लोकसभा सांसदों में से छह ने एकनाथ शिंदे गुट का दामन थाम लिया। इन सभी सांसदों ने दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से पहले मुलाकात की और फिर शिवसेना में विलय की घोषणा की। उद्धव ठाकरे की शिवसेना में यह दूसरी बार टूट हुई है। इससे पहले 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पार्टी दोफाड़ हो गई थी। अरस्तू का मानना था कि राजनीति और नैतिकता एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब राजनीति व्यक्तिगत स्वार्थ या भ्रष्टाचार से ग्रसित हो जाती है, तो समाज का नैतिक पतन होता है, जो लोकतंत्र के मूल उद्देश्य–ह्वसामान्य कल्याणह्व को कमजोर कर देता है। देश में विपक्षी दलों के सांसदों में मची भगदड़ से अरस्तू का यह कथन आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। सांसदों का एक दल से दूसरे दल में जाना केवल एक राजनीतिक घटना नहीं है; यह उस गहरी प्रवृत्ति का संकेत है जिसे संस्थागत अवसरवाद कहा जा सकता है। आज दल-बदल अपवाद नहीं रहा, बल्कि एक सामान्यीकृत राजनीतिक व्यवहार बनता जा रहा है, जहाँ जनादेश, विचारधारा और नैतिकता–तीनों क्रमशः हाशिए पर खिसकते प्रतीत होते हैं। शिवसेना यूबीटी के नौ लोकसभा सांसदों में से छह ने एकनाथ शिंदे गुट का दामन थाम लिया। इन सभी सांसदों ने दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से पहले मुलाकात की और फिर शिवसेना में विलय की घोषणा की। उद्धव ठाकरे की शिवसेना में यह दूसरी बार टूट हुई है। इससे पहले 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पार्टी दोफाड़ हो गई थी। फिर चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे के गुट को भी मूल शिवसेना का दर्जा मिल गया। तब उद्धव ठाकरे ने अपने गुट का नाम शिवसेना यूबीटी रख लिया। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के 22 सांसदों ने भी पार्टी तोड़कर एनसीपीआई का दामन थाम लिया था। एनसीपीआई एनडीए की एक बेहद छोटी पार्टी है। शिवसेना यूबीटी में टूट का सीधा फायदा केंद्र में सत्ताधारी एनडीए को मिलने वाला है। इससे एनडीए का संख्या बल और बढ़ जाएगा। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार लोकसभा में दो तिहाई बहुमत के जुगाड़ में लगी है ताकि आने वाले दिनों में वह कुछ अहम संविधान संशोधन विधेयकों को पास करवा सके। शिवसेना उद्धव गुट के सांसदों के शिवसेना में शामिल होने के बाद लोकसभा में एनडीए का कुनबा 320 के करीब पहुंच गया है। सांसदों और विधायकों की ऐसी ही टूटफूट से ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस हाशिए पर आ चुकी है। टीएमसी के 80 विधायकों में से 58 ने ममता से विद्रोह कर दिया था। ममता बनर्जी इस झटके से उबर भी नहीं पाई कि तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने बागी होने की घोषणा कर दी। टीएमसी के पास लोकसभा की 28 सीटें होने के कारण, बागी गुट को दो-तिहाई बहुमत हासिल करने के लिए कम से कम 19 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता थी। एक ऐसी राजनीतिक पार्टी, जिसकी न लोकसभा और न ही विधनसाभा,

कहीं पर भी एक सीट तक नहीं है, उस पार्टी में तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों ने विलय कर लिया है। इस कदम को दल-बदल विरोधी कानून से बचने के लिए अहम माना जा रहा है। विगत महीनों में गैरभाजपा दलों में विधायकों–सांसदों के विद्रोह की शुरूआत अरविन्द केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से हुई थी। आम आदमी पार्टी के सात राज्य सभा सांसदों ने भाजपा का दामन थाम लिया। इस फैसले के बाद उच्च सदन में आप की ताकत घटकर सिर्फ तीन सांसदों तक रह गई है। राज्यसभा में की ताकत बढ़कर 113 पहुंची वहीं, इस बदलाव से भाजपा को सीधा फायदा हुआ है और उसकी संख्या राज्यसभा में बढ़कर 113 पहुंच गई है। इसके साथ ही एनडीए का आंकड़ा 148 पहुंच गया। वहीं, जिन सात सांसदों का भाजपा में विलय हुआ है, उनमें राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, संदीप पाठक, विक्रमजीत साहनी, स्वाति मालीवाल और राजिंदर गुप्ता शामिल हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या विधायकों का एक गुट खुद विलय की घोषणा कर सकता है, या जिस राजनीतिक दल का वे प्रतिनिधित्व करते हैं, उसे सहमत होना जरूरी है? सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर अभी फैसला लेना है। भारत का दल-बदल विरोधी कानून संविधान की दसवीं अनुसूची के माध्यम से पेश किया गया था। यह 1985 में 52वें संवैधानिक संशोधन के जरिए लागू हुआ। यह ह्यआया राम, गया रामह्ल की राजनीति की घटना की प्रतिक्रिया थी, जिसमें सरकारें गिराने या खुद की उन्नति हासिल करने के लिए विधायक/सांसद मध्यावधि में दल बदल लेते हैं। बता दें कि दसवीं अनुसूची के तहत, कोई भी विधायक जो स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है या सदन में अपनी पार्टी के निर्देश के खिलाफ वोट करता है, उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के विधायकों के मामले में अपना निर्णय समाज विज्ञान के सम्मानित प्रोफेसर आंद्रे बेताई के इन शब्दों से शुरू किया था। कोर्ट ने लिखा, ह्यहमारे संविधान निमार्ताओं ने लोगों को सांविधानिक मूल्यों को बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन प्रश्न है कि हम अपने इस कर्तव्य को निभाने में कितने सफल हुए? लोकतंत्र और सांविधानिक जिम्मेदारियों को कितना निभा सके?ह्ल कोर्ट ने कहा, मतभेद और दलबदल ये दोनों अलग-अलग बातें हैं। इन्हें अलग साबित करके ही लोकतांत्रिक मूल्यों को अन्य लोकतांत्रिक विचारों के साथ संतुलित रखा जा सकता है। कोर्ट ने कहा था कि ह्यसंसदीय लोकतंत्र में सांविधानिक नैतिकता बरकरार रखने की जिम्मेदारी सरकार और विपक्ष दोनों पर बराबर होती है। भारत में राजनीतिक दल सत्ता में रहने पर अलग और सत्ता से बाहर होने पर अलग ढंग से इस जिम्मेदारी को देखते हैं। यही वजह है कि भारत में जनमानस मानने लगा है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था अनैतिक हो चुकी है। कोर्ट ने कहा, मतभेद और दलबदल ये दोनों अलग-अलग बातें हैं। इन्हें अलग साबित करके ही लोकतांत्रिक मूल्यों को अन्य लोकतांत्रिक विचारों के साथ संतुलित रखा जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ह्यकेवल संविधान की रक्षा और उसकी अक्षुण्णता की शपथ लेना काफी नहीं है। बल्कि सांविधानिक मूल्यों को रोजमर्रा के कामों में शामिल करने की अपेक्षा हमारे महान संविधान ने की है। आज दल-बदल अपवाद नहीं रहा, बल्कि एक सामान्यीकृत राजनीतिक व्यवहार बनता जा रहा है, जहाँ जनादेश, विचारधारा और नैतिकता–तीनों क्रमशः हाशिए पर खिसकते प्रतीत होते हैं। यह स्थिति हमें यह पुनर्विचार करने के लिए बाध्य करती है कि क्या राजनीति अब भी सिद्धांतों और मूल्यों से संचालित है?, या वह केवल सत्ता- समीकरणों का खेल बनकर रह गई है। इस संदर्भ में यह स्वीकार करना होगा कि कानून केवल आंशिक समाधान प्रदान कर सकता है; वास्तविक समाधान राजनीतिक संस्कृति और नैतिकता में निहित है। पार्टी विद डिफरेंस का जुमला गढ़ने वाली भाजपा भी लोकतंत्र को कमजोर करने वाले दल बदल के खेल में शामिल हो गई। दल बदलने वाले पहले भाजपा को और भाजपा इनको देशद्रोही, भ्रष्टाचारी, मुसलमान समर्थक या मुसलमान विरोधी और न जाने किस किस ढंग से कोसते रहें हैं। दल बदलने के बाद अचानक से दल बदलने वाले और इन्हें लेने वाले पवित्र गाय बन गए। दल बदल कराए बगैर जनाधार बढ़ाना काफी तकलीफदेह होता है। मतलब खुद के बलबूते पर पूर्ण सत्ता प्राप्त करने में बड़ा जोर आता है। इसके लिए जनता से वादे करने पड़ते हैं, उन्हें निभाने के लिए ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत होती है। ऐसे में यदि दूसरे का पकाया हुआ खाने को मिल जाए तो कौन पीछे रहना चाहेगा। सिद्धान्तों और नैतिकता, ये सब अब किताबी बातें रह गई हैं।

कानून का विलय या बीजेपी का ऑपरेशन लोटस? गोवा केस का फैसला बदलेगा दलबदल का पूरा खेल

बंगाल में ममता बनर्जी के हाथ से तृणमूल कांग्रेस (TMC) का कंट्रोल निकलना, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) के नौ में से छह सांसदों का एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होना, दिल्ली और पंजाब में आप के सात सांसदों का बीजेपी में जाना भारत के लगभग सभी इलाकों में एक साथ दल-बदल हो रहा है। दल-बदल विरोधी कानून से कौन बचता है, यह तय करने वाला सबसे अहम मामला गोवा का है, जो देश की सबसे बड़ी अदालत में पेंडिंग है। विपक्षी पार्टियों में हो रही इन उथल-पुथल और नेताओं के पाला बदलकर PM नरेंद्र मोदी की BJP के नेतृत्व वाले NDA में शामिल होने के साथ ही संवैधानिक कानून से जुड़ा एक ही सवाल उठता है। वह यह है कि संविधान की दसवीं अनुसूची में दिए गए दलबदल विरोधी कानून में क्या अपवाद हैं? अप्रैल में राघव चड्ढा के नेतृत्व में आप के दस में से सात राज्यसभा सांसदों ने BJP का दामन थाम लिया। मई में आए चुनाव नतीजों से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पहली सरकार बनी, और अब हारी हुई टीएमसी के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 ने BJP से बातचीत के बाद 'नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया' नाम की एक कम जानी-पहचानी पार्टी में विलय का ऐलान किया है। इसी दौरान, शिवसेना के नौ लोकसभा सांसदों में से छह ने पाला बदलकर शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने का फैसला किया है। भारत का दल-बदल विरोधी कानून 1985 में लाया गया था। यह कानून किसी भी ऐसे विधायक या सांसद को अयोग्य ठहराता है जो अपनी मजी से पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है या पार्टी के व्हिप (निर्देश) का पालन नहीं करता है। शुरूआत में इसमें दो तरह की छूट दी गई थीः विभाजन और "विलय" । विभाजन वाली छूट का बार-बार गलत इस्तेमाल होने के कारण 2003 में इसे हटा दिया गया। अब दसवीं अनुसूची के पैरा 4 के तहत सिर्फ. विलय की छूट बची है। इस पैरा के दो हिस्से हैं। (उप) पैरा 4(1) उस विधायक या सांसद को सुरक्षा देता है जहाँ मूल राजनीतिक पार्टी... किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी में विलय कर लेती है। (उप) पैरा 4(2) कहता है, इस पैरा के उप-पैरा (1) के मकसद से, सदन के किसी सदस्य की मूल राजनीतिक पार्टी का विलय तभी माना जाएगा, जब संबंधित लेजिस्लेचर पार्टी (विधायक दल) के कम से कम दो-तिहाई सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हों।

सनातन व नारी सम्मान पर बड़ी लकीर खींचते योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री योगी बेटियों की सुरक्षा के लिए संकल्पवान हैं। वह कई जनसभाओं मे अपना मंतव्य स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर किसी ने बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास किया तो अगले चैराहे पर उसका इंतजार यमराज कर रहा होगा। योगी जी के बयानों का असर धरातल पर भी दिखाई पड़ता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजनीति से ऊपर उठकर सनातन धर्म तथा स्त्री गरिमा तथा सम्मान के हित में बड़ी रेखाएं खींच रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव की बेटी के प्रति सोशल मीडिया के माध्यम से आपत्तिजनक बयानबाजी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने केआदेश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अपराधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गयी है। मुख्यमंत्री ने सख्ती के साथ कहा है कि किसी भी बेटी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए हर बेटी का सम्मान होना चाहिए। हम उन संस्कारों में पले -बढ़े हैं जहां गांव की बेटी-बहन को पूरे गांव की बेटी -बहन माना जाता है। मुख्यमंत्री योगी बेटियों की सुरक्षा के लिए संकल्पवान हैं। वह कई जनसभाओं मे अपना मंतव्य स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर किसी ने बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास किया तो अगले चैराहे पर उसका इंतजार यमराज कर रहा होगा। योगी जी के बयानों का असर धरातल पर भी दिखाई पड़ता है। बेटियों के साथ होने वाली अप्रिय घटनाओं पर त्वरित कार्यवाही हो रही है। आरोपियों का हाफ एनकाउंटर हो रहा है तथा आवश्यकता पड़ने पर बुलडोजर एक्शन भी हो रहे हैं। प्रदेश में नारी समाज को सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। नवरात्रि के अवसर पर मिशन शक्ति जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं। केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से नारी सशक्तीकरण का महाअभियान चलाया जा रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव की बेटी पर टिप्पणी करने वालों के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रवैया दिखाकर सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा बुने जा रहे चक्रव्यूह को एक ही झटके में ध्वस्त कर दिया है। सपा मुखिया अखिलेश की बेटी अदिति पर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी के बाद मुख्यमंत्री योगी ने जो एक्शन लिया है उसने इस दुखद घटना पर बनाए जा रहे सपा के राजनैतिक नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया है। जब सोशल मीडिया के माध्यम से यह विवाद बड़े राजनीतिक तूफान में बदल रहा था और सपा योगी जी व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह कहकर घेरने का प्रयास कर रही थी कि, ह्लजिनका खुद का परिवार नहीं वो परिवार का दर्द क्या समझेंगेह्ल तब योगी जी इस घटना के जिम्मेदार लोगों को ढूंढ रहे थे। योगी जी ने अपराधियों पर तुरंत एफआईआर कराने के निर्देश जारी करते हुए कहा कि वह किसी भी बेटी क्यों न हो बेटी पर अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं है। यूपी चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ ने अपने इस कदम से सिद्ध कर दिया है कि महिला सुरक्षा और सम्मान के मामले में उनकी सरकार बिना किसी भेदभाव के काम करती है।

व्यवस्था की चिता पर जलते सपने
आखिर कब रुकेगा मौत का कारोबार?

उपहार सिनेमा अग्निकांड को लगभग तीन दशक बीत चुके हैं। उस घटना में बंद निकास द्वारों के कारण 59 लोगों की मौत हुई थी। देश ने उस समय कड़े कानूनों और सख्त निगरानी की मांग की थी। लेकिन क्या वास्तव में कुछ बदला? यदि बदला होता तो मुंडका, अनाज मंडी, करोल बाग, मालवीय नगर और लखनऊ जैसी घटनाएं दोहराई नहीं जाती। लखनऊ के अलीगंज स्थित एक कोचिंग सेंटर में लगी आग में 15 छात्रों की दर्दनाक मौत उस व्यवस्था के चेहरे से नकाब हटाने वाली त्रासदी है, जो वर्षों से भ्रष्टाचार, लापरवाही और प्रशासनिक उदासीनता के सहारे चल रही है। जिन बच्चों को उनके माता-पिता बेहतर भविष्य के सपने लेकर कोचिंग भेजते हैं, वे यदि धुएं से भरे कमरों, बंद दरवाजों और अवैध निमार्णों के बीच दम तोड़ दें तो उसे केवल हादसा कहना सच्चाई से मुंह मोड़ना होगा। यह उन परिस्थितियों में हुई मौत है, जिसे रोका जा सकता था, टाला जा सकता था और जिसकी जिम्मेदारी तय की जा सकती है। इसलिए यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या यह वास्तव में हादसा था या फिर भ्रष्ट व्यवस्था द्वारा किया गया एक सुनियोजित प्रशासनिक हत्याकांड? घटना के विवरण किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को झकझोर देने के लिए पर्याप्त हैं। आग लगने के बाद छात्र जान बचाने के लिए इधर-उधर भागे। कुछ तीसरी मंजिल से नीचे कूद गए, कुछ बाथरूम में छिप गए, यह सोचकर कि शायद वहां धुएं से बच सकेंगे लेकिन दम घुटने से उनकी मौत हो गई। यह दृश्य किसी युद्ध या प्राकृतिक आपदा का नहीं बल्कि उस इमारत का दृश्य था, जिसे नियमों की अनदेखी कर व्यावसायिक लाभ कमाने के लिए तैयार किया गया था। जहां पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं थे, जहां फायर सेफ्टी मानकों का पालन नहीं हुआ और जहां छात्रों की सुरक्षा से अधिक महत्व मुनाफे को दिया गया। कुछ ही समय पहले दिल्ली के मालवीय नगर में भी भीषण आग ने 21 लोगों की जान ले ली थी। उससे पहले मुंडका, अनाज मंडी, करोल बाग, अलीपुर और उपहार सिनेमा जैसे अनेक अग्निकांड देश देख चुका है। हर बार जांच में लगभग एक जैसी बातें सामने आती हैं, अवैध निर्माण, बंद निकास मार्ग, फायर एनओसी का अभाव, क्षमता से अधिक लोगों की मौजूदगी, प्रशासनिक अनदेखी और भ्रष्टाचार। यदि हर बार कारण एक जैसे हैं तो फिर इन घटनाओं को दुर्घटना नहीं बल्कि व्यवस्था की विफलता का परिणाम माना जाना चाहिए। लखनऊ अग्निकांड की प्रारंभिक जांच ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जिस इमारत में कोचिंग सेंटर चल रहा था, वहां स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण किया गया था। सेटबैक क्षेत्र तक को कवर कर लिया गया था। नीचे पेट शॉप और गेमिंग जोन संचालित हो रहे थे जबकि ऊपर कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी चल रही थी। एक ही इमारत में अलग-अलग व्यावसायिक गतिविधियों का ऐसा मिश्रण सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत खतरनाक माना जाता है। सबसे गंभीर तथ्य यह सामने आया कि जिस रास्ते से छात्रों को बाहर निकलना था, वह प्रभावी रूप से बंद था। ऐसे में आग लगने के बाद उनके पास बचने का कोई विकल्प नहीं बचा। यह केवल तकनीकी गलती नहीं बल्कि मानव जीवन के प्रति घोर उपेक्षा का

उदाहरण है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि ऐसी इमारतें अस्तित्व में आती कैसे हैं? क्या नगर निगम, विकास प्राधिकरण, फायर विभाग, बिजली विभाग और स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं होती? कोई भी अवैध निर्माण रातों-रात खड़ा नहीं हो जाता। उसकी नींव पड़ती है, दीवारें खड़ी होती हैं, मंजिलें बनती हैं, बिजली-पानी के कनेक्शन दिए जाते हैं और फिर वहां व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में अनेक विभाग शामिल होते हैं। सच्चाई यही है कि भ्रष्टाचार और मिलीभगत की जड़ें इतनी गहरी हैं कि नियम केवल फाइलों में रह जाते हैं जबकि जमीन पर अवैधता का साम्राज्य खड़ा हो जाता है। देश का शहरी विकास मॉडल भी इस समस्या के लिए कम जिम्मेदार नहीं है। आज अधिकांश शहरों में अधिक से अधिक लाभ कमाने की होड़ लगी हुई है। बिल्डर अतिरिक्त मंजिलें जोड़ देते हैं, सेटबैक क्षेत्र को कवर कर लेते हैं, बेसमेंट का उपयोग अवैध व्यावसायिक गतिविधियों के लिए करते हैं और आपातकालीन निकास को स्टोर रूम में बदल देते हैं। बदले में कुछ अधिकारियों की जेबें गर्म हो जाती हैं और फाइलों में सब कुछ वैध दिखाई देने लगता है। नतीजा यह होता है कि एक पूरी इमारत धीरे-धीरे मौत के जाल में बदल जाती है और किसी दिन एक चिंगारी सैंकड़ों परिवारों की खुशियां छीन लेती है। उपहार सिनेमा अग्निकांड को लगभग तीन दशक बीत चुके हैं। उस घटना में बंद निकास द्वारों के कारण 59 लोगों की मौत हुई थी। देश ने उस समय कड़े कानूनों और सख्त निगरानी की मांग की थी। लेकिन क्या वास्तव में कुछ बदला? यदि बदला होता तो मुंडका, अनाज मंडी, करोल बाग, मालवीय नगर और लखनऊ जैसी घटनाएं दोहराई नहीं जाती। हर बड़े हादसे के बाद जांच समितियां बनती हैं, मुआवजे घोषित होते हैं, कुछ अधिकारियों को निलंबित कर दिया जाता है और मीडिया में कुछ दिनों तक बहस चलती है। फिर मामला धीरे-धीरे ठंडा पड़ जाता है और व्यवस्था अगले हादसे का इंतजार करने लगती है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि आज भी देश के लगभग हर शहर में हजारों ऐसी इमारतें मौजूद हैं, जो किसी भी समय अग्निकांड का केंद्र बन सकती हैं।

चिन्ताजनक है महंगी होती दवाइयां, महंगा होता इलाज

स्वास्थ्य और शिक्षा किसी भी सभ्य समाज की दो मूलभूत आवश्यकताएं हैं। दुर्भाग्य से भारत में इन दोनों क्षेत्रों में व्यवसायीकरण का प्रभाव लगातार बढ़ता गया है। निजी अस्पतालों की बढ़ती फीस, महंगे परीक्षण, अनावश्यक जांचें, चिकित्सा उपकरणों का भारी खर्च और अब दवाइयों की बढ़ती कीमतें मिलकर आम नागरिक को असहाय बना रही हैं। भारत आज विकसित राष्ट्र बनने के स्वप्न के साथ आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की परिकल्पना बार-बार दोहराई जा रही है। बड़े-बड़े बुनियादी ढांचे, डिजिटल क्रांति, अंतरिक्ष उपलब्धियां और आर्थिक विकास के दावों के बीच एक प्रश्न बार-बार सामने खड़ा हो जाता है-क्या ऐसा भारत वास्तव में विकसित कहलाएगा, जहां एक सामान्य नागरिक बीमारी के कारण कर्ज में डूबने को विवश हो जाए? जहां इलाज और दवाइयों की बढ़ती कीमतें जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी तय करने लगें? जहां स्वास्थ्य सेवा अधिकार नहीं, बल्कि आर्थिक सामर्थ्य का विषय बन जाए? ऐसे समय में जब महंगाई पहले ही आम आदमी की कमर तोड़ रही है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एन.पी.पी.ए.) द्वारा कुछ जीवनरक्षक दवाओं और टीकों की कीमतों में भारी वृद्धि की अनुमति देना गंभीर चिंता का विषय है। कैंसर की कुछ दवाओं, एंटी-टेटनस सीरम और बच्चों के आवश्यक टीकों की कीमतों में लगभग पचास प्रतिशत तक वृद्धि की स्वीकृति ने लाखों परिवारों के सामने नया संकट खड़ा कर दिया है। यह निर्णय केवल आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय, मानवीय संवेदना और जनकल्याणकारी शासन की अवधारणा से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति किसी से छिपी नहीं है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि देश में बड़ी संख्या में लोग आज भी अपने इलाज का खर्च अपनी जेब से वहन करते हैं। बीमारी केवल स्वास्थ्य संकट नहीं रह जाती, वह आर्थिक संकट में भी बदल जाती है। एक समय था जब कहा जाता था कि व्यक्ति अपनी बेटी की शादी के कारण कर्ज में डूबता है, लेकिन आज की स्थिति यह है कि किसी गंभीर बीमारी का इलाज पूरा परिवार आर्थिक रूप से बर्बाद कर सकता है। कैंसर, हृदय रोग, किडनी रोग या अन्य जटिल बीमारियों का उपचार लाखों रुपये की मांग करता है। ऐसे में यदि जीवनरक्षक दवाइयों की कीमतें भी लगातार बढ़ती रहें तो गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लिए स्वास्थ्य सेवा लगभग असंभव हो जाएगी। एन.पी.पी.ए. ने दवाओं की कीमत बढ़ाने के पीछे उत्पादन लागत में वृद्धि और बाजार में संभावित कमी का तर्क दिया है। उनका कहना है कि

यदि दवा कंपनियां लागत भी नहीं निकाल पाएंगी तो वे उत्पादन बंद कर सकती हैं, जिससे मरीजों को आवश्यक दवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। यह तर्क अपनी जगह सही हो सकता है। किसी भी उद्योग को जीवित रहने के लिए उचित लाभ आवश्यक है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या जीवनरक्षक दवाओं को सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं की तरह देखा जा सकता है? क्या स्वास्थ्य क्षेत्र में लाभ कमाने की सीमा और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन स्थापित नहीं किया जाना चाहिए? स्वास्थ्य और शिक्षा किसी भी सभ्य समाज की दो मूलभूत आवश्यकताएं हैं। दुर्भाग्य से भारत में इन दोनों क्षेत्रों में व्यवसायीकरण का प्रभाव लगातार बढ़ता गया है। निजी अस्पतालों की बढ़ती फीस, महंगे परीक्षण, अनावश्यक जांचें, चिकित्सा उपकरणों का भारी खर्च और अब दवाइयों की बढ़ती कीमतें मिलकर आम नागरिक को असहाय बना रही हैं। चिकित्सा सेवा धीरे-धीरे सेवा के बजाय उद्योग में परिवर्तित होती दिखाई दे रही है। अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र कम और कॉरपोरेट प्रतिष्ठान अधिक प्रतीत होने लगे हैं। रोगी अब मरीज नहीं, बल्कि ग्राहक की तरह देखा जाने लगा है। यह स्थिति केवल आर्थिक असमानता को ही नहीं बढ़ाती, बल्कि सामाजिक विभाजन को भी गहरा करती है। आज भी देश में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मुख्यतः उन्हीं लोगों को उपलब्ध हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है। गरीब व्यक्ति सरकारी अस्पतालों की लंबी कतारों, सीमित संसाधनों और अपर्याप्त सुविधाओं के भरोसे है। अमीर व्यक्ति अत्याधुनिक अस्पतालों और महंगे उपचारों का लाभ उठा सकता है। क्या यही सामाजिक न्याय है? क्या यही वह भारत है जिसकी कल्पना स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनेक जनहितकारी योजनाएं लागू हुई हैं। आयुष्मान भारत जैसी योजना ने लाखों लोगों को राहत भी प्रदान की है। जन औषधि केंद्रों की स्थापना ने सस्ती दवाइयों की उपलब्धता बढ़ाने का प्रयास किया है। लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य क्षेत्र में व्याप्त व्यापक विसंगतियां अभी भी बनी हुई हैं। यदि दवाओं की कीमतें लगातार बढ़ती रहें और निजी स्वास्थ्य सेवाएं अनियंत्रित होती जाएं, तो इन योजनाओं का प्रभाव सीमित हो जाएगा। वास्तविक चुनौती यह है कि स्वास्थ्य को बाजार की शक्तियों के हवाले छोड़ने के बजाय उसे जनकल्याण के केंद्र में रखा जाए। सरकार का दायित्व केवल योजनाओं की घोषणा करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रत्येक नागरिक को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। जीवनरक्षक दवाओं की कीमतों पर विशेष नियंत्रण होना चाहिए। सरकारी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। दवा खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। आवश्यक दवाओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार विशेष सहायता और सब्सिडी भी दे सकती है, ताकि लागत बढ़ने का पूरा बोझ मरीजों पर न पड़े। इसके साथ ही स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का दायरा और व्यापक होना चाहिए। अनेक गरीब और निम्न मध्यमवर्गीय परिवार ऐसे हैं जो किसी भी बीमा सुरक्षा से वंचित हैं। गंभीर बीमारी की स्थिति में वे अपनी जीवनभर की जमा पूंजी गंवा देते हैं। स्वास्थ्य बीमा केवल अस्पताल में भर्ती होने तक सीमित न रहे, बल्कि आवश्यक दवाओं और दीर्घकालिक उपचार को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि सरकार समय-समय पर दवा कंपनियों की लागत संरचना और मूल्य निर्धारण की स्वतंत्र समीक्षा कराए। यदि वास्तव में लागत बढ़ी है तो उसका प्रमाण सार्वजनिक होना चाहिए। पारदर्शिता से जनता का विश्वास भी बढ़ेगा और अनावश्यक मूल्यवृद्धि पर भी रोक लगेगी। स्वास्थ्य नीति का मूल उद्देश्य कंपनियों के लाभ और नागरिकों के अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करना होना चाहिए। वर्ष 2047 का विकसित भारत केवल ऊंची इमारतों, तेज रफ्तार सड़कों और बढ़ती जीडीपी से नहीं बनेगा। उसका वास्तविक मूल्यांकन इस आधार पर होगा कि वहां का सबसे गरीब नागरिक कितना सुरक्षित, शिक्षित और स्वस्थ है। यदि एक किसान, मजदूर, कर्मचारी या निम्न आय वर्ग का व्यक्ति बीमारी के समय सम्मानपूर्वक इलाज प्राप्त नहीं कर सकता, तो विकास के दावे अधूरे रह जाएंगे। आज आवश्यकता केवल दवाइयों की कीमतों पर बहस करने की नहीं, बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था की समग्र समीक्षा करने की है। यह स्वीकार करना होगा कि स्वास्थ्य कोई विलासिता नहीं, बल्कि मौलिक मानवीय अधिकार है। जिस राष्ट्र में नागरिकों को स्वस्थ जीवन का अवसर नहीं मिलता, वहां विकास की चमक भी फीकी पड़ जाती है। समय आ गया है कि सरकार, नीति-निमार्ता, चिकित्सा जगत और समाज मिलकर यह सुनिश्चित करें कि स्वास्थ्य सेवा लाभ कमाने का माध्यम नहीं, बल्कि जनसेवा का सशक्त उपकरण बने। अन्यथा विकसित भारत का सपना केवल आंकड़ों में चमकेगा, जबकि आम आदमी बीमारी, कर्ज और असहायता के अंधकार में संघर्ष करता रहेगा। स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष की ओर बढ़ते भारत के सामने यही सबसे बड़ी नैतिक और मानवीय चुनौती है, जिसका समाधान आज ही तलाशना होगा।

युवा की आवाज

हर युवा असुरक्षित, ये भविष्य की चोरी है

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने एक आधिकारिक बयान में बताया कि भिवंडी में पुलिस जांच के दौरान कथित तौर पर प्रश्नपत्र लीक होने की बात सामने आने के बाद, पूरे राज्य में 28 जून को होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 को शनिवार को टाल दिया गया, क्योंकि कथित तौर पर प्रश्न पत्र के कुछ हिस्से लीक हो गए थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को दावा किया कि देश की शिक्षा और परीक्षा प्रणाली को ह्लवसूली का तंत्रह्व बना दिया गया है। यह परीक्षा रविवार को होनी थी। एक और पेपर लीक। एक और परीक्षा रद्द। कांग्रेस सांसद ने एक्स पर कहा देश के शिक्षा और परीक्षा सिस्टम को उगाही का जरिया बना दिया गया है, जिससे देश का हर युवा असुरक्षित महसूस कर रहा है। यह सिर्फ.पेपर लीक नहीं है, बल्कि युवाओं के भविष्य की चोरी है। इससे पहले, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने एक आधिकारिक बयान में बताया कि भिवंडी में पुलिस जांच के दौरान कथित तौर पर प्रश्नपत्र लीक होने की बात सामने आने के बाद, पूरे राज्य में 28 जून को होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। यह परीक्षा पूरे महाराष्ट्र में 1,028 केंद्रों पर आयोजित की जानी थी। सार्वजनिक सूचना में कहा कि NXEET 2026 परीक्षा के दौरान सामने आई गड़बड़ियों को देखते हुए उसने सुरक्षा के सभी जरूरी इंतजाम किए थे, लेकिन शनिवार की सुबह मिली गोपनीय जानकारी से पता चला कि भिवंडी में कुछ लोगों के पास TET प्रश्न-पत्र से जुड़ी जानकारी थी। काउंसिल ने बताया कि भिवंडी पुलिस ने उस जगह पर छापा मारा और जांच के दौरान पाया कि अनधिकृत प्रश्न-पत्र के कई सवाल असली TET परीक्षा के प्रश्न-पत्र से मेल खाते थे। बयान के अनुसार, भिवंडी पुलिस ने इसमें शामिल लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। काउंसिल ने कहा, हालात को देखते हुए, 28 जून 2026 को होने वाली टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को टाल दिया गया है। इस मामले की विस्तृत जांच के आदेश भी दिए गए हैं। साथ ही यह भी बताया गया कि परीक्षा से जुड़ी नई जानकारी काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी।

यह सिर्फ.पेपर लीक नहीं है, बल्कि युवाओं के भविष्य की चोरी है। इससे पहले, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने एक आधिकारिक बयान में बताया कि भिवंडी में पुलिस जांच के दौरान कथित तौर पर प्रश्नपत्र लीक होने की बात सामने आने के बाद

बलिदान दिवस पर सीएम सम्राट चौधरी का ऐलान
अगले साल डॉ. मुखर्जी को समर्पित भव्य होगा पार्क

पटना में बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देते हुए अगले वर्ष उनके नाम पर भव्य नया पार्क बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने मुखर्जी जी के राष्ट्रहित और अखंड भारत के प्रति समर्पण को याद करते हुए उन्हें चाणक्य के बाद देश को एक करने वाला नेता बताया, साथ ही भाजपा के सिद्धांतों और धारा 370 हटाने में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला। पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक, प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक एवं महान शिक्षाविद् डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि (बलिदान दिवस) के अवसर पर अटल सभागार, भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए तथा उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरूआत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुये मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी का राष्ट्रहित, अखंड भारत और सांस्कृतिक स्वाभिमान के प्रति समर्पित जीवन हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत है। उनकी राष्ट्रसेवा और बलिदान को देश सदैव स्मरण रखेगा। उन्होंने कहा कि पंडित चाणक्य के बाद यदि देश को एक करने वाले कोई नेता थे तो वे डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जिन्होंने अखंड भारत के सपने को साकार किया। भारतीय जनता पार्टी की कई पीढ़ियों से यह नारा चला आ रहा था कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे, यह नारा भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिया था। उन्होंने कहा कि जब इस देश में लोकतंत्र खतरे में था तो जनसंघ के लोगों ने देश को बचाने के लिए पार्टी को विलीन कर दिया। इसके बाद 1980 में भाजपा का उदय हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकतंत्र को व्यवस्थित किया। वर्ष 2019 में भारत की जनता ने श्री नरेन्द्र मोदी जी को इतनी ताकत दी कि उन्होंने कश्मीर से धारा 370 को उखाड़ फेंका। उन्होंने कहा कि हमलोगों के लिए देश पहले है फिर व्यक्ति और उसके बाद पार्टी। उन्होंने कहा कि पहले 1984 में जहां भाजपा के केवल 2 सांसद थे वहीं वर्ष 2014 में 282 सांसद निर्वाचित हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले साल इसी दिन हमलोग डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर एक भव्य नया पार्क लोगों को समर्पित करेंगे। उन्होंने कहा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में लगभग 27-28 पार्टियों का गठबंधन बना था और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भी लगभग 27-28 पार्टियों के गठबंधन की सरकार है। श्री नरेंद्र मोदी जी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको नमन करता हूं। आज पूरा भारत उनके साथ खड़ा है।

पीएम सूर्य घर योजना

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज लोक सेवक आवास स्थित ह्यसंकल्प सभागारह्ल में युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की समीक्षा की। बैठक में युवा, रोजगार एवं कौशल विभाग के सचिव श्री कौशल किशोर ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विभाग की विभिन्न योजनाओं, कौशल विकास मिशन के अंतर्गत संचालित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा भावी कार्य योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी।

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 25 लाख युवाओं को कुशल बनाये जाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि पीएम सूर्य घर योजना के बेहतर क्रियान्वयन के के लिये जीविका दीदियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग 5 लाख लोगों को जल्द रोजगार एवं 50 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तेजी से काम करें। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के विस्तार के लिए समुचित कार्य योजना तैयार करें तथा विभिन्न क्षेत्रों में रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाए। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 25 लाख युवाओं को कुशल बनायें।

बिहार को मिलेगी नई पहचान, पटना का जेपी गंगा पथ बनेगा विश्वस्तरीय पर्यटन केंद्र

राजधानी पटना के गंगा तट पर विकसित की जा रही जेपी गंगा पथ समग्र उद्यान परियोजना बिहार के शहरी विकास, पर्यटन संवर्धन, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल के रूप में उभर रही है। राज्य सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना गंगा के विस्तृत नदी तट को विश्वस्तरीय सार्वजनिक स्थल के रूप में विकसित करते हुए पाटलिपुत्र की गौरवशाली विरासत को आधुनिक स्वरूप प्रदान करेगी। बिहार को प्राप्त गंगा का विशाल एवं प्राकृतिक नदी तट इस पहल को विशिष्ट बनाता है। देश में विरले ही ऐसे शहर हैं जहाँ नदी, इतिहास, संस्कृति और शहरी विस्तार की इतनी व्यापक संभावनाएँ एक साथ उपलब्ध हों। इसी विशेषता को आधार बनाकर एक ऐसा हरित एवं सांस्कृतिक रिवरफ्रंट विकसित किया जा रहा है, जो प्रकृति, विरासत, पर्यटन और आधुनिक नागरिक सुविधाओं का संतुलित समागम प्रस्तुत करेगा। विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह ने कहा कि यह पहल बिहार की विशिष्ट पहचान को सशक्त करने के साथ-साथ राज्य को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर नई ऊँचाई प्रदान करेगी। प्रथम चरण में लगभग 6 किलोमीटर लंबे ग्रीन-पार्क कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है।

आपातकाल की बरसी पर लोकतंत्र सेनानियों के लिए बड़ी घोषणा,

पेंशन बढ़कर हुई 25 हजार रुपये

राजस्थान सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन 20 हजार से 25 हजार कर दिया है. साथ में इनके लिए चिकित्सा सहायता 4 हजार से 5 हजार कर दी गई है. सरकार का मानना है कि बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को देखते हुए यह फैसला राहत देने वाला साबित होगा. जयपुर कार्यक्रम में भजनलाल शर्मा ने युवाओं से संघर्ष से सीखने की अपील की है. आपातकाल की बरसी के मौके पर राजस्थान सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों के लिए एक अहम घोषणा की है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकतंत्र सेनानियों की मासिक पेंशन और चिकित्सा सहायता राशि बढ़ाने का ऐलान किया है. सरकार के इस फैसले से प्रदेश के उन लोगों को सीधा लाभ मिलेगा, जिन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष किया था और आपातकाल के दौरान कठिन परिस्थितियों का सामना किया था. जयपुर के दुगार्पुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान और उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की भावना को सुरक्षित रखना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज का साझा दायित्व है. कार्यक्रम में मौजूद लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान भी किया गया और उनके योगदान को याद किया गया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा करते हुए कहा कि लोकतंत्र सेनानियों को दी जाने वाली मासिक पेंशन अब 20 हजार रुपये की जगह 25 हजार रुपये मिलेगी. इसके साथ ही मासिक चिकित्सा सहायता भी बढ़ाने का फैसला लिया गया है. अब तक लोकतंत्र सेनानियों को हर महीने 4 हजार रुपये चिकित्सा सहायता के रूप में दिए जाते थे. सरकार ने इसमें एक हजार रुपये की बढ़ोतरी करते हुए इसे 5 हजार रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की है. सरकार का मानना है कि बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को देखते हुए यह फैसला राहत देने वाला साबित होगा.

दिल्ली-जयपुर में सब्जी बेचने पर ट्रक भाड़ा सरकार देगी

राजस्थान के झुंझुनूं जिले में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए राहत और लाभकारी योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यदि किसान अपनी सब्जियां स्थानीय बाजार में उचित दाम पर नहीं बेच पा रहे हैं, तो वे उन्हें दिल्ली या जयपुर भेज सकते हैं, और इसका ट्रक भाड़ा मोदी सरकार चुकाएगी। यह घोषणा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 35 लाख से अधिक किसानों के खातों में 3,900 करोड़ की बीमा दावा राशि हस्तांतरित करने के राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद थे और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक वितरित किए गए। कार्यक्रम में अपने संबोधन में शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को भरोसा दिलाया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उनकी फसल खरीद सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि चिंता मत करो किसान भाइयों, खूब फसल पैदा करो, अच्छी फसल करो, और खरीदने का काम मोदी जी की और राजस्थान की सरकार मिलकर करेगी। कृषि मंत्री ने बताया कि कई बार टमाटर, प्याज या आलू जैसी फसलें स्थानीय स्तर पर कम कीमत पर बिकती हैं। ऐसे में किसान उन्हें दिल्ली या जयपुर में बेच सकते हैं। उन्होंने कहा, ह्लअगर यहां कीमत कम है, और दिल्ली या जयपुर में कीमत ज्यादा है, तो ट्रक का भाड़ा आप नहीं चुकाएंगे, मोदी जी की सरकार चुकाएगी।ह्व शिवराज सिंह चौहान ने नकली कृषि उत्पादों पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाने की बात कही। उन्होंने बताया कि खेती में उपयोग होने वाली 30 हजार दवाओं पर वैज्ञानिक परीक्षण न होने के कारण प्रतिबंध लगाया गया है। ह्लजब तक कोई कृषि विश्वविद्यालय या क्कअफ प्रमाणित नहीं करेगा कि इनसे फायदा होता है, तब तक इन्हें नहीं बेचा जाएगा। कृषि मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि नकली खाद, नकली बीज और नकली कीटनाशक बेचने वालों को जेल भेजा जाएगा। किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।ह्व उन्होंने कहा कि संसद में इस संबंध में एक सख्त कानून लाने की तैयारी चल रही है।

दिल्ली में 50% कर्मचारियों के लिए WFH लागू करने का ऐलान

पार्किंग फीस बढ़ेगी दोगुनी

दिल्ली की रेखा गुप्ता की सरकार ने सर्दियों के मौसम में प्रदूषण से निपटने के लिए मास्टर प्लान की घोषणा की है. इसमें कड़े उपाय किए गए हैं. दिल्ली सरकार ने सर्दियों में प्रदूषण से निपटने के लिए मास्टर प्लान की घोषणा की है. इसके तहत 1 नवंबर से 28 फरवरी तक स्थायी नियम लागू रहेंगे. दिल्ली ने सर्दियों में प्रदूषण से निपटने के लिए स्थायी नीति अपनाई है. इसके तहत 1 नवंबर से 31 जनवरी तक तोड़-फोड़ और सिविल निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी. 1 नवंबर से ऑफिसों में 50 फीसदी कर्मचारियों के लिए ह्यवर्क फ्रॉम होमह्ल और पार्किंग शुल्क दोगुना करने का नियम लागू होगा. दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यलाय ने कहा कि दिल्ली सरकार ने सर्दियों में प्रदूषण रोकने के उपाय कड़े किए हैं. वैध (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र) न होने पर वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा और यह नियम साल भर लागू रहेगा. दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसकी जानकारी दी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए सभी की भागीदारी जरूरी है. दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सर्दियों को मौसम में एयर क्वालिटी बिगड़ जाती है. पिछले कई सालों के आंकड़ों से पता चलता है कि नवंबर और फरवरी के बीच प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की परमानेंट सॉल्यूशन निकाला है. अब हर साल अलग से ऑर्डर निकालने की जरूरत नहीं होगी. उन्होंने कहा कि ये नोटिफिकेशन डिटेल स्टडी और एयर क्वालिटी डेटा के आधार पर निकाला गया है. 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में 1 नवंबर से 15 फरवरी के दौरान दिल्ली में औसत अदक312 से 342 दर्ज की गई. इस दौरान अधिकतम अदक461 से 494 के बीच रिकॉर्ड की गई. सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए उन्हीं गाड़ियों को पेट्रोल, डीजल और सीएनजी मिलेगी जिनके पास वैध ढवउ प्रमाण पत्र होगा. उन्होंने कहा कि जिन गाड़ियों के पास वैध ढवउ सर्टिफिकेट नहीं होगा और वो ईंधन लेने पहुंचे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

दिल्ली में बनेगी 6 लेन वाली सुरंग, जाम का काम होगा तमाम!

केंद्र सरकार ने दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे से वसंत कुंज तक 6 लेन टनल कॉरिडोर को मंजूरी दी है. 8.1 किमी लंबे इस प्रोजेक्ट से ट्रैफिक जाम कम होगा और सफर तेज व आसान बनेगा. दिल्ली में लगातार बढ़ते ट्रैफिक जाम से लोगों को राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने राष्ट्रीय राजमार्ग-148अए पर

6 लेन की सुरंग सड़क बनाने को मंजूरी दे दी है. यह नया कॉरिडोर द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज के नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ेगा. करीब 8.1 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट पर 6,969.67 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. सरकार का कहना है कि इससे दिल्ली में सफर पहले से ज्यादा आसान और तेज हो जाएगा. इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद पश्चिमी और दक्षिणी दिल्ली के बीच यात्रा का समय कम होने की उम्मीद है. द्वारका, गुरुग्राम, आईजीआई एयरपोर्ट और पश्चिमी दिल्ली से वसंत कुंज, छतरपुर और दक्षिणी दिल्ली आने-जाने वाले लोगों को ट्रैफिक जाम से काफी राहत मिलेगी. यह नया कॉरिडोर अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 और द्वारका एक्सप्रेसवे को भी सीधे जोड़ेगा, जिससे पूरे इलाके की कनेक्टिविटी बेहतर होगी. इस परियोजना के तहत ट्विन ट्यूब टनल बनाई जाएगी. सुरंग का निर्माण आधुनिक टनल बोरिंग मशीन की मदद से होगा. इसका करीब 1.98 किलोमीटर हिस्सा रंगपुरी के पास दक्षिणी दिल्ली रिज के नीचे से निकलेगा. इससे रिज फॉरेस्ट और पर्यावरण पर कम से कम असर पड़ेगा. टनल शिवमूर्ति इंटरचेंज से शुरू होकर नेल्सन मंडेला मार्ग और महिपालपुर-छतरपुर रोड के जंक्शन से पहले खत्म होगी.

पंजाब के सरकारी स्कूलों में शुरू होगी एआई की पढ़ाई, शिक्षा मंत्री ने किया बड़ा ऐलान

पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि अगले महीने से राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में कृत्रिम मेधा का पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। बैंस ने यहां ह्यब्राइट माइंड्स पंजाब 2026ह्ल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार पिछले एक वर्ष से एआई पहल पर काम कर रही थी और अब इसे सरकारी विद्यालयों में लागू करने के लिए तैयार है। इस कार्यक्रम में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, शिक्षा सचिव सोनाली गिरि, कई शिक्षक और छात्र उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान बोर्ड परीक्षाओं में 95 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 12वीं कक्षा के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। बैंस ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि छात्र पंजाब व देश के उज्ज्वल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें विश्वास है कि इनमें से कई छात्र आगे चलकर सिविल सेवक, चिकित्सक, वकील और अन्य पेशेवरों के रूप में देश की सेवा करेंगे। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव ने परीक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों पर विद्यार्थियों से सुझाव लेने के लिए उनसे सीधे संवाद किया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्राप्त सुझावों पर भविष्य की शिक्षा नीतियां तैयार करते समय विचार किया जाएगा। बैंस ने यह भी दावा किया कि पंजाब ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और देश के शिक्षा सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय शिक्षकों, विद्यार्थियों और सरकार के प्रयासों को दिया। सिसोदिया ने कहा कि किसी भी देश की प्रगति उसके शिक्षा तंत्र की गुणवत्ता पर निर्भर करती है और हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि एआई नए रोजगार के अवसर सृजित करेगी, साथ ही पारंपरिक नौकरियों के स्वरूप में भी बदलाव लाएगी, इसलिए विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकी कौशल हासिल करना आवश्यक है। सिसोदिया ने मूल्यांकन प्रणाली में सुधार, नकल पर रोक लगाने और वैज्ञानिक शिक्षण पद्धतियों को अपनाने की भी वकालत की।

पंजाब कांग्रेस में सब ठीक है! राजा वारिंग बोले- चन्नी के साथ मिलकर लड़ेंगे

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वडिंग ने चरणजीत चन्नी के साथ मतभेदों की अटकलों को खारिज करते हुए पार्टी की एकजुटता का दावा किया है। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनावों में मिलकर लड़ने पर जोर दिया और अनुशासनहीनता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी, जो नेतृत्व परिवर्तन की आंतरिक मांगों के बीच एक स्पष्ट संदेश है। पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के साथ मतभेद की खबरों का खंडन किया है और कहा है कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों में पंजाब के लिए मिलकर लड़ने के लिए एकजुट रहेगी। कई नेताओं की ओर से चन्नी को राज्य इकाई का अध्यक्ष बनाने की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए वारिंग ने कहा कि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आप हम सभी को एक साथ, एक ही मंच पर देखेंगे। हम मिलकर पंजाब के लिए लड़ेंगे। उन्होंने पार्टी के भीतर मतभेदों को कम करके आंका और कहा कि सीनियर लीडरशिप पार्टी की दिशा के साथ बनी हुई है। लीडरशिप बदलने की मांगों का ज़िक्र करते हुए वारिंग ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि चन्नी साहब या किसी सीनियर लीडर ने ऐसा कुछ कहा है। वारिंग ने असंतोष के सार्वजनिक प्रदर्शनों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया, जिसमें चन्नी के आवास पर हाल ही में हुई बैठकें भी शामिल हैं, जहाँ कई विधायकों ने नेतृत्व में बदलाव का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि सख़्त कदम उठाए जाएँगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि जो भी व्यक्ति ऐसी बातें करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन किसी को भी अनुशासनहीनता करने का अधिकार नहीं है। चंडीगढ़ में मीडिया से बात करते हुए, वारिंग ने भारतीय जनता पार्टी (इखढ) पर कड़ा हमला बोला और पंजाब में उसकी संभावनाओं को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें (इखढ को) एक-दो दिन खुश रहने दें। उन्होंने अपनी पार्टी के दबदबे पर जोर देते हुए कहा, ह्लकांग्रेस पार्टी इखढ को पंजाब में कदम भी नहीं रखने देगी। इस बीच, मोरिंडा में चन्नी के समर्थकों की बैठक के बाद पंजाब कांग्रेस में मतभेद के संकेतों के बीच, कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने जोर देकर कहा कि पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से काम करती है और एक साझा मकसद को बनाए रखते हुए अलग-अलग विचारों को भी जगह देती है। हम एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं। हम किसी की आवाज नहीं दबाते। मैं मानता हूँ कि अनुशासन जरूरी है। लोगों को अपनी सीमाएँ पता होनी चाहिए। लेकिन हम यह नहीं कहते कि ह्यसिर्फ.यही करो, सिर्फ.यही कहोह्ल। हम चीजें समझाते हैं।

सवाल नैतिकता और जवाबदेही का भी है

दिल्ली में जंतर-मंतर पर, और देश में कई अन्य शहरों में भी, परीक्षाओं में हुई धांधली के आरोप में विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। हो सकता है भाजपा-विरोधी दल स्थिति का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हों। पर इससे स्थिति की गंभीरता और भयावहता कम नहीं हो जाती। यह सही है कि ह्यकॉकरोच पार्टीह्न द्वारा चलाये जा रहे देश के शिक्षामंत्री-विरोधी अभियान में दिल्ली के जंतर-मंतर में उतने युवा इकट्ठा नहीं हो रहे, जितनों की आयोजकों को आशा थी, पर सही यह भी है कि देश के युवाओं के संदर्भ में इस अभियान को पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सकता। युवा देश के शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। उनका कहना है कि ह्यनीटह्न और ह्यसीबीएससीह्न जैसी परीक्षाओं में हो रही धांधली शिक्षामंत्री की असफलता का प्रतीक है। ह्यनीटह्न की परीक्षा के संदर्भ में देश के पंद्रह से अधिक युवाओं द्वारा की गई आत्महत्याएं निश्चित रूप से एक गंभीर मसला है और इस बारे में सरकार की लगभग चुप्पी पर सवाल उठने ही चाहिए। सवाल उठ भी रहे हैं, पर जिन्हें जवाब देने हैं वे बचाव के रास्ते खोज रहे हैं।ऐसा ही एक रास्ता शिक्षामंत्री ने खोजा है। जून 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने विपक्ष द्वारा चलाये जा रहे आंदोलन से बचाव के लिए देश में आपातकाल लागू करने का रास्ता खोजा था। बावजूद इसके कि कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने यह दावा किया था कि उसका यह कदम देश के संविधान द्वारा दिये गये अधिकार के अनुकूल था, आपातकाल लागू करने की यह कार्रवाई देश के नागरिकों के अधिकारों का हनन करने वाली थी। देश के शानदार जनतांत्रिक इतिहास का एक काला अध्याय था यह। तत्कालीन सरकार द्वारा अपने उठाये गये इस कदम के बचाव में बहुत कुछ कहा गया था, पर इसका औचित्य सिद्ध करने का कोई प्रयास सफल नहीं हुआ। हो भी नहीं सकता था। स्वयं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी अपनी गलती का अहसास हो गया था। आपातकाल लागू करने के इक्कीस महीने बाद, मार्च 1977 में उन्होंने अपना उठाया गया कदम वापस ले लिया। उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी भी थी। कांग्रेस के अब के नेता, राहुल गांधी ने भी उस घटना के लगभग पचास साल बाद, 2021 में, आपातकाल लागू करने को ह्यगलतीह्न मानकर खेद व्यक्त किया था। लेकिन इस स्वीकारोक्ति के बाद भी यह कलंक तो कांग्रेस के माथे पर लगा ही रहा कि उसने आपातकाल लागू करके एक जनतंत्र-विरोधी कार्रवाई की थी। कांग्रेस के विरोधी दल, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी, अक्सर कांग्रेस के इस ह्यकाले कारनामेह्न का राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास करते रहे हैं। अपने बचाव में कांग्रेस इस ह्यगलतीह्न को भुला देने की बात कहती रही है। पर कांग्रेस-विरोधी इसे एक हथियार की तरह काम में लेते रहे हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्री ने आपातकाल की बरसी के अवसर पर, इस हथियार को अपने बचाव का साधन बनाने की कोशिश की है। अपने खिलाफ चल रहे ह्यशिक्षा मंत्री इस्तीफा दोह्न आंदोलन की आलोचना करते हुए उन्होंने कांग्रेस को ह्यजनतंत्र-विरोधीह्न बताकर अपना बचाव किया है। इसी संदर्भ में ह्यएनसीईआरटीह्न की किताबों में आपातकाल के बारे में जोड़े गये अध्याय का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को, और भावी पीढ़ियों को, आपातकाल की जानकारी देना जरूरी है। अब पहली बार कक्षा नौ की सामाजिक विज्ञान की किताब में इसे ह्यभारतीय लोकतंत्र के लिए प्रमुख चुनौतियोंह्न के रूप में शामिल किया गया

है। हालांकि 12वीं की किताब में पहले ही यह विषय जोड़ा जा चुका था, और जब यह जोड़ा गया तब सत्ता में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी। ऐसे में इस विषय को उठाकर शिक्षामंत्री आखिर क्या पाना चाहते हैं? शायद ह्यनीटह्न की परीक्षा में हुई धांधली को लेकर हो रही अपनी आलोचना से ध्यान बंटाने की एक कोशिश हो यह। शायद उन्हें लग रहा हो कि इस तरह ध्यान बंटा कर वे अपना कुछ बचाव करने में सफल हो सकते हैं! ह्यएनसीईआरटीह्न की नौवीं कक्षा की किताबों में भी आपातकाल का अध्याय जोड़ने का बचाव करते हुए शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां यह जान और समझ सकें कि ऐसा कोई काला अध्याय कभी लिखा गया था। भविष्य में ऐसा कुछ न हो इसके लिए आज के विद्यार्थियों को यह पढ़ाया जाना जरूरी है। निश्चित रूप से भावी पीढ़ियों को ऐसी बातों का पता होना चाहिए। ह्यएनसीईआरटीह्न की किताब में ऐसे अध्याय का होना कतई गलत नहीं है। गलत यह है कि ध्यान बंटाने के साधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ह्यनीटह्न और ह्यसीबीएससीह्न की परीक्षाओं में हो रही धांधली की जांच की दुहाई दी जा रही है। दोषियों को बख्शा नहीं जायेगा, इसका आश्वासन दिया जा रहा है। लेकिन सवाल किसी के ज़िम्मेदारी लेने का भी है। सवाल नैतिकता का भी है। नैतिकता का तकाजा है कि पर्चों की गड़बड़ी के चलते हुई आत्महत्याओं की ज़िम्मेदारी कोई तो ले। सन■ 2021 से लेकर 2026 के बीच इस संदर्भ में 93 छात्रों की आत्महत्याओं के मामले सामने आये हैं। इसी वर्ष, यानी 2026 में, कम से कम चौदह छात्रों ने अपनी जान गंवाई है। आखिर कोई तो ज़िम्मेदार होगा इन घटनाओं के लिए। दिल्ली में जंतर-मंतर पर, और देश में कई अन्य शहरों में भी, परीक्षाओं में हुई धांधली के आरोप में विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। हो सकता है भाजपा-विरोधी दल स्थिति का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हों। पर इससे स्थिति की गंभीरता और भयावहता कम नहीं हो जाती। चूंकि मामला शिक्षा से जुड़ा हुआ है इसलिए स्वाभाविक है शिक्षा मंत्री से जवाब मांगा जाये। पर, दुर्भाग्य से, शिक्षामंत्री मौन साधे बैठे हैं।

मेक इन इंडिया का अगला चरण अब सेमीकंडक्टर क्रांति, विकसित भारत का रोडमैप

प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के साणंद में CG सेमी OSAT सुविधा का उद्घाटन करते हुए भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया। उन्होंने इसे ह्यमेक इन इंडियाह्ल के तहत एक दशक पुरानी इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला रणनीतिक चरण बताया, जिसका लक्ष्य देश में संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन विकसित करना है। यह पहल भारत को वैश्विक चिप उत्पादन हब बनाएगी और 2014 से इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन व निर्यात में हुई उल्लेखनीय वृद्धि को नई गति प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई को गुजरात के साणंद में उन्नसेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट (OSAT) सुविधा का उद्घाटन किया। यह सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में भारत की बढ़ती प्रगति और ग्लोबल चिप प्रोडक्शन हब बनने की उसकी महत्वाकांक्षा को दशार्ता है। इस कार्यक्रम में बोलते हुए, प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि यह सुविधा जल्द ही अपने प्रोडक्शन का लक्ष्य हासिल कर लेगी।

मोदी ने कहा कि मुझे बताया गया है कि अब से यहां हर साल 20 करोड़ (200 मिलियन) चिप्स का प्रोडक्शन होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसे जल्द ही हासिल कर लेंगे। यह भरोसा इस बात से भी आता है कि ह्यसेमीकॉन इंडियाह्ल प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ रहा है। कदम-दर-कदम, ईंट-दर-ईंट और अब चिप-दर-चिप। हमने हर साल 50 करोड़ (500 मिलियन) चिप्स बनाने का लक्ष्य रखा है। मुझे यकीन है कि आप बहुत जल्द यह लक्ष्य हासिल कर लेंगे। मैं CG Semi की पूरी टीम को दिल से बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल बनाने और एक्सपोर्ट करने वाले देश के तौर पर भारत की स्थिति पर जोर दिया और बताया कि 2014 से इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में कितनी बड़ी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल बनाने वाला और दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल एक्सपोर्ट करने वाला देश है। आज भारत का कुल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन 2014 के मुकाबले लगभग 7 गुना बढ़ गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट लगभग 11 गुना बढ़ गया है। प्रधानमंत्री ने भारत में सेमीकंडक्टर की ग्रोथ को एक दशक से चल रही इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का हिस्सा बताया। यह सफर तैयार प्रोडक्ट्स से शुरू होकर कंपोनेंट्स और अब सेमीकंडक्टर तक पहुँचा है, जिसका मकसद देश में ही पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन को विकसित करना है। उन्होंने इस नजरिए को विकसित भारत के रोडमैप और ह्यमेक इन इंडियाह्ल पहल के अगले चरण का अहम हिस्सा बताया। पीएम मोदी ने समझाया कि भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का विस्तार अचानक नहीं हुआ। यह उस इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है जो पिछले एक दशक में भारत में आई है। पहले प्रोडक्ट, फिर कंपोनेंट्स और अब सेमीकंडक्टर। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी ह्यवैल्यू चेनह्ल भारत में होगी। यही विकसित भारत का रोडमैप है। यही ह्यमेक इन इंडियाह्ल का अगला चरण है।

गुजरात में पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 20% आरक्षण

गुजरात सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए पुलिस, वन एवं जेल विभाग की विभिन्न भर्तियों में 20 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। यह लाभ पुलिस विभाग में पुलिस उपनिरीक्षक, पुलिस कांस्टेबल तथा राज्य रिजर्व पुलिस (एसआरपी) के प्लाटून कमांडर पदों की भर्ती में मिलेगा। इसके अलावा जेल विभाग में जेलर ग्रुप-2 और जेल सिपाही तथा वन एवं पर्यावरण विभाग में वनरक्षक वर्ग-3 और वनपाल वर्ग-3 के पदों पर सीधी भर्ती में भी पूर्व अग्निवीर आरक्षण और अन्य सुविधाओं के पात्र होंगे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोमवार को इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार पूर्व अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार के निर्णय के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों को राज्य के विभिन्न विभागों में वर्ग-3 संवर्ग की सीधी भर्तियों में 20 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी उन्हें छूट दी जाएगी। उम्मीदवारों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष तक की छूट प्रदान की जाएगी, जबकि अग्निवीर योजना की पहली बैच के युवाओं को पांच वर्ष तक की आयु छूट मिलेगी। राज्य सरकार का मानना है कि सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त युवा अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और कार्यकुशलता के कारण प्रशासनिक सेवाओं में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। यह कदम उनके पुनर्वास और रोजगार सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की थी। इसके तहत 17.5 से 21 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को सेना, नौसेना और वायु सेना में चार वर्ष के लिए भर्ती किया जाता है। इस अवधि में उन्हें सैन्य प्रशिक्षण के साथ सक्रिय सेवा का अनुभव भी प्राप्त होता है।

रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द खुलने वाला है पोर्टल, महतारी वंदन योजना को लेकर बड़ा अपडेट

महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। बीजापुर को बाल विवाह मुक्त जिला बनाना है। छत्तीसगढ़ की विवाहित महिलों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जिन महिलाओं का नाम महतारी वंदन योजना के पहले फेज में नहीं जुड़ पाया था। उन महिलाओं के लिए फिर से पोर्टल खोला जाएगा। इस बात की जानकारी प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने अपने बीजापुर दौरे में दी है। मंत्री ने यहां महिला एवं बाल विकास विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक लेकर विभागीय योजनाओं के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे पात्र हितग्राही तक पहुंचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभाग की सर्वोच्च जिम्मेदारी यही है। अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा नक्सल प्रभावित रहे और अब विक- ास की नई दिशा में आगे बढ़ रहे बीजापुर जिले में शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए समन्वित प्रयास किए जाएं। बैठक में महतारी वंदन योजना की भी विस्तृत समीक्षा की गई। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जानकारी दी कि योजना का पोर्टल शीघ्र ही प्रारंभ होने वाला है। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने अधिकारियों को सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी करने तथा पात्र महिलाओं का पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र महिला योजना के लाभ से वंचित नहीं रहनी चाहिए और पंजीयन प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता एवं सरलता के साथ संपन्न हो। मंत्री राजवाड़े ने कहा कि विभागीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए नियमित मॉनिटरिंग, मैदानी स्तर पर सक्रियता तथा सुनियोजित कार्ययोजना आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं के संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और प्रत्येक अधिकारी अपने दायित्व का पूरी जवाबदेही के साथ निर्वहन करें।

महतारी वंदन योजना के लिए फिर से खुलेगा पोर्टल

बीजापुर में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने दिए निर्देश

कहा- कोई पात्र महिला योजना से वंचित नहीं हो

बीजापुर दौरे पर पहुंचीं थी मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े

बैठक में कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान की विस्तार से समीक्षा की गई। मंत्री ने इसे विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि कुपोषण के खिलाफ केवल सरकारी प्रयास ही पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि जनभागीदारी भी उतनी ही आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक घर और प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में मुनगा (सहजन) का पौधा अनिवार्य रूप से लगाया जाए। उन्होंने कहा कि मुनगा पोषक तत्वों से भरपूर होता है और इसके नियमित सेवन से बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा किशोरियों के स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार संभव है। इसके साथ ही, उन्होंने सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को प्रतिदिन एक केला वितरित करने के निर्देश दिए ताकि बच्चों के पोषण स्तर और वजन में वृद्धि सुनिश्चित की जा सके।

छत्तीसगढ़ पुलिस अब होगी हाईटेक, अमित शाह ने दी 400 डायल-112 की संख्या

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में छत्तीसगढ़ की उन्नत सीजी डायल-112 आपातकालीन सेवा और 32 मोबाइल फोरेंसिक वैन का शुभारंभ किया, जिसक- ा उद्देश्य आधुनिक तकनीक से आपातकालीन प्रतिक्रिया को तेज करना और त्वरित न्याय के लिए साक्ष्य-आधारित जांच को मजबूत करना है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 18 मई, 2026 को रायपुर के माना पुलिस परेड ग्राउंड में छत्तीसगढ़ पुलिस की उन्नत सीजी डायल-112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा और मोबाइल फोरेंसिक वैन के बेड़े का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साई और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह की उपस्थिति में, श्री शाह ने राज्य भर में आपातकालीन सेवाओं और फोरेंसिक जांच को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 400 उन्नत डायल-112 आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहनों और 32 मोबाइल फोरेंसिक वैन का उद्घाटन किया। ह्लएककके नंबर, सब्बो बारह्व थीम के तहत शुरू की गई यह नई आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली, संकट के समय त्वरित सहायता सुनिश्चित करने के लिए पुलिस, अग्निशमन और चिकित्सा आपात स्थितियों को एक ही मंच पर एकीकृत करती है। नए तैनात किए गए 400 वाहन स्मार्टफोन, जीपीएस सिस्टम, वायरलेस रेडियो, पीटीजेड कैमरे, डैश कैमरे, मोबाइल एनवीआर सिस्टम और सौर बैकअप सुविधाओं से लैस हैं, जो आपातकालीन अभियानों के दौरान लाइव निगरानी, वास्तविक समय ट्रैकिंग और त्वरित संचार को सक्षम बनाते हैं। यह सेवा जीआईएस आधारित निगरानी, उन्नत वाहन ट्रैकिंग, एसआईपी ट्रंक तकनीक और स्वचालित कॉलर लोकेशन पहचान का उपयोग करके निरंतर संचालित होगी। सभी 33 जिला समन्वय केंद्र नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। नागरिक वॉइस कॉल, एसएमएस, ईमेल, वेब पोर्टल, व्हाट्सएप, चैटबॉट सेवाओं और एसओएस-112 इंडिया मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ह्लसाइंस ऑन व्हील्स - टुवर्ड्स फास्टर जस्टिसह्व थीम के तहत शुरू की गई 32 मोबाइल फोरेंसिक वैन का उद्देश्य राज्य भर में साक्ष्य-आधारित जांच को मजबूत करना है।

महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में स्टिंग एनर्जी ड्रिंक बेचने पर लगाएं रोक

महाराष्ट्र में अब स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में स्टिंग एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह निर्णय विधायक विक्रम पचपुते द्वारा उठाए गए। महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की कि राज्य भर में स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में स्टिंग एनर्जी ड्रिंक और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। यह कदम पेय पदार्थ में मौजूद कुछ ऐसे तत्वों को लेकर उठाई गई चिंताओं के बाद उठाया गया है, जिन्हें बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। विधानसभा सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी के विधायक विक्रम पचपुते द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब देते हुए, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री नरहरि झिरवाल ने इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य पर इन एनर्जी ड्रिंक्स के पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, एनर्जी ड्रिंक्स में आमतौर पर कैफीन और चीनी की मात्रा बहुत अधिक होती है। मंत्री ने बताया कि इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही, स्कूलों से भी कहा गया है कि वे छात्रों को एनर्जी ड्रिंक पीने से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी नुकसानों के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाएं। मंत्री नरहरि झिरवाल ने चेतावनी देते हुए कहा स्कूल परिसरों के आसपास स्टिंग एनर्जी ड्रिंक की बिक्री के संबंध में माननीय सदस्य द्वारा जताई गई चिंताएं काफी हद तक सही हैं। अगर किसी भी स्कूल परिसर के 500 मीटर के दायरे में ऐसे एनर्जी ड्रिंक या किसी भी अन्य नशीले पदार्थ की बिक्री होती पाई गई, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की जाएगी। चर्चा के दौरान, विधायक विक्रम पचपुते ने सरकार से यह भी पूछा कि क्या वह 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को एनर्जी

ड्रिंक बेचने पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई नया नियम पेश करेगी। इसके अलावा, विधायक राहुल कुल और वरुण सरदेसाई ने भी सरकार से अपील की कि बच्चों तक ऐसे पेय पदार्थों की आसान पहुंच को रोकने के लिए और अधिक सख्त कदम उठाए जाएं। विधायकों की चिंताओं का जवाब देते हुए मंत्री झिरवाल ने आश्वासन दिया कि सरकार प्रस्तावित प्रतिबंधों को प्रभावी ढंग से लागू करने के साथ-साथ स्कूली स्तर पर जागरूकता अभियानों को और अधिक मजबूत करेगी, ताकि बच्चों को इसके नुकसान के बारे में सही जानकारी मिल सके।

अन्ना के आंदोलन की चेतावनी का असर या कुछ और?

भूख हड़ताल की चेतावनी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने नए RTI नियम, 2026 पर फिलहाल रोक लगा दी है। इन नियमों में आवेदन शुल्क बढ़ाने, पहचान पत्र अनिवार्य करने, एक आवेदन में केवल एक विषय रखने और अपील पर शुल्क लगाने जैसे कई प्रावधान शामिल थे। हजारे ने इन्हें RTI कानून की मूल भावना के खिलाफ बताते हुए वापस लेने की मांग की थी। महाराष्ट्र सरकार ने सूचना का अधिकार (RTI) नियम, 2026 पर फिलहाल रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश के बाद यह फैसला लिया गया। सूत्रों के मुताबिक, नए नियमों में RTI आवेदन शुल्क बढ़ाने, पहचान पत्र अनिवार्य करने और आवेदन को एक ही विषय तक सीमित रखने जैसे कई बदलाव किए गए थे। इनका सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कड़ा विरोध किया था और 5 जुलाई से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी थी। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्य सूचना आयुक्त को हाल ही में अधिसूचित RTI नियमों पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। ये नियम सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए थे और 12 जून को सरकारी गजट में प्रकाशित होने के साथ ही लागू हो गए थे। संशोधित नियमों के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जानकारी मांगने के लिए आवेदन शुल्क 30 रुपये निर्धारित किया गया था। सूचना उपलब्ध कराने के लिए शुल्क भी तय किया गया था। A4 आकार के प्रति पृष्ठ की कॉपी के लिए 5 रुपये, स्कैन या डिजिटल प्रति के लिए भी 5 रुपये देने का प्रावधान था। रिकॉर्ड का निरीक्षण पहले एक घंटे तक निःशुल्क रखा गया था, जबकि इसके बाद प्रत्येक घंटे के लिए 50 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया था। गरीबी रेखा (BPL) से नीचे रहने वाले आवेदकों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई थी, लेकिन 50 पृष्ठों से अधिक जानकारी लेने पर उन्हें भी निर्धारित शुल्क देना पड़ता। नियमों में यह भी प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक आवेदक को भारतीय नागरिकता साबित करने वाले किसी फोटो पहचान पत्र की स्व-सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी।

हरियाणा में जनगणना-2027 की तैयारी

हरियाणा सरकार ने जनगणना-2027 की तैयारियों के तहत राज्य में जनसंख्या गणना का प्री-टेस्ट शुरू कर दिया है। यह अभ्यास 6 से 18 जुलाई तक चयनित क्षेत्रों में फील्ड अभ्यास के रूप में होगा। भारत की जनगणना-2027 की तैयारियों के तहत हरियाणा सरकार ने राज्य में जनसंख्या गणना के प्री-टेस्ट (पूर्व परीक्षण) की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने इसके लिए चयनित क्षेत्रों को अधिसूचित कर दिया है, जहां छह से 18 जुलाई तक फील्ड अभ्यास कराया जाएगा। इससे पहले एक से पांच जुलाई तक पात्र नागरिकों को डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से स्वयं अपना विवरण दर्ज कराने (सेल्फ-एन्यूमरेशन) का अवसर दिया गया था। यह अभ्यास देशभर में होने वाली जनगणना-2027 की तैयारियों का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तायुक्त एवं हरियाणा जनगणना-2027 की नोडल अधिकारी डा. सुमिता मिश्रा ने बताया कि प्री-टेस्ट का उद्देश्य जनगणना की पूरी प्रक्रिया को अधिक सटीक, सुचारू और प्रभावी बनाना है। इस दौरान डिजिटल डाटा संग्रह प्रणाली, फील्ड संचालन, प्रगणकों की कार्यप्रणाली तथा तकनीकी व्यवस्थाओं की व्यवहारिक जांच की जाएगी, ताकि वास्तविक जनगणना से पहले संभावित चुनौतियों की पहचान कर उनका समाधान किया जा सके। उन्होंने बताया कि फील्ड अभ्यास पूरा होने के बाद 19 और 20 जुलाई को पुनरीक्षण (रिविजनल राउंड) आयोजित किया जाएगा। इसमें प्री-टेस्ट के दौरान एकत्रित आंकड़ों का सत्यापन, अद्यतन और अंतिम पुष्टि की जाएगी। मिश्रा ने चयनित क्षेत्रों के लोगों से इस अभ्यास में सक्रिय भागीदारी करने और प्रगणकों को पूरा सहयोग देने की अपील की।

हरियाणा सरकार नए सेक्टर बनाने के लिए 13 शहरों में खरीदेगी जमीन!

किसानों को मिलेगा मुंह मांगा पैसा

हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा सरकार ने रिहायशी, वाणिज्यिक और संस्थागत विकास के लिए दूसरे चरण में 13 शहरों में करीब 33 हजार एकड़ जमीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले चरण में 71 शहरों में करीब 1.67 लाख एकड़ जमीन खरीदने के लिए किसानों से आवेदन मांगे जा चुके हैं। अब नए सेक्टर और विकास परियोजनाओं के लिए इच्छुक किसानों और भूमि मालिकों से 31 अगस्त तक ई-भूमि पोर्टल पर आवेदन मांगे गए हैं।

इस चरण में हिसार, सोनीपत, कैथल, महम, फर्रुखनगर, रायपुररानी, नूंह , बरवाला, टोहाना, डबवाली, बेरी, ममलौडा और आरोग्य धाम बाढ़सा सहित विभिन्न क्षेत्रों में जमीन खरीदी जाएगी।

हिसार में 789 .91 एकड़,
सोनीपत में 18102 .11 एकड़,
महम में 1246 .52 एकड़
कैथल में 3961 .01 एकड़,
बरवाला में 672 .06 एकड़,
रायपुररानी में 437 .10 एकड़,
नूंह में 1197 .61 एकड़,
डबवाली में 380 .00 एकड़,
टोहाना में 1968 .90 एकड़,
आरोग्य धाम बाढ़सा में 2046 .82 एकड़
फर्रुखनगर में मुबारिकपुर, फर्रुखनगर और सुल्तानपुर में 1203 .52 एकड़, जमीन खरीदने का लक्ष्य रखा गया है।

सरकार से मोलभाव कर सकेगा किसान

भूमि विवादों को कम करने के लिए सरकार ने नीति में बदलाव किया है। अब जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, बल्कि किसानों की सहमति और उनकी ओर से प्रस्तावित कीमत के आधार पर जमीन खरीदी जाएगी। यदि सरकार और भू-स्वामी दोनों प्रस्तावित दर पर सहमत होते हैं तो खरीद की जाएगी। जरूरत पड़ने पर जमीन के मूल्य को लेकर मोलभाव भी किया जा सकेगा। किसानों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की गई है और ई-भूमि पोर्टल

एमपी में यूसीसी ड्राफ्ट की तैयारी तेज, सीएम यादव बोले- 90% से ज्यादा जनता पक्ष में

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की कि मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड (वउउ) के लिए जन परामर्श प्रक्रिया में 90% से अधिक नागरिकों ने समर्थन व्यक्त किया है, जिसमें अल्पसंख्यक समुदायों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इस व्यापक समर्थन के साथ, राज्य सरकार अब कानून का ड्राफ़्ट तैयार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है, जो पूरे प्रदेश में वउउ लागू करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि ह्यसमग्र पोर्टलह्ल पर रजिस्टर्ड लाभार्थियों को वउउ के बारे में सुझाव देने के लिए लगभग 3.49 करोड़ रटर भेजे गए थे। अब तक नौ लाख से ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं, जिनमें से 90 प्रतिशत से ज्यादा लोगों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया है। इस प्रस्ताव को अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों का भी काफी समर्थन मिला है। संबंधित समिति और विधि विभाग मिलकर इस कानून का ड्राफ़्ट तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा, मुख्यमंत्री यादव ने घोषणा की कि 15 से 29 जुलाई तक पूरे राज्य में ह्यगुरु पूर्णिमा पखवाड़ाह्ल मनाया जाएगा। इस दौरान स्कूल कई तरह की शैक्षणिक, सांस्कृतिक और जागरूकता गतिविधियां आयोजित करेंगे, जिनमें भाषण और निबंध प्रतियोगिताएं, संस्कृत श्लोक पाठ, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम, वृक्षारोपण अभियान और करियर मार्गदर्शन सत्र शामिल होंगे। पर्यटन क्षेत्र में उपलब्धियों का ज़िक्र करते हुए, मुख्यमंत्री ने बताया कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल के ह्यटूरिज्म सर्वे एंड अवार्ड्स 2026ह्ल में ह्यबेस्ट वाइल्डलाइफ डेस्टिनेशनह्ल का सम्मान मिला। यह पुरस्कार गोवा में केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदान किया। मुख्यमंत्री

यादव ने कहा कि बांधवगढ़ की समृद्ध जैव-विविधता, बाघों की अच्छी आबादी, प्राकृतिक सुंदरता और प्रभावी संरक्षण प्रबंधन ने इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है।

सिंधिया लाए अडानी ग्रुप की मिसाइल फैक्ट्री, मिलेंगे 5000 रोजगार

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी में अडानी डिफेंस के ₹2,500 करोड़ के मिसाइल एवं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया, जो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का उपक्रम होगा। यह परियोजना ह्यआत्मनिर्भर भारतह्ल को गति देगी, ग्वालियर-चंबल को रक्षा हब बनाएगी और लगभग 5,000 रोजगार सृजित करेगी। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की उपस्थिति में शिवपुरी जिले में अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस द्वारा स्थापित किए जा रहे दक्षिण एशिया के निजी क्षेत्र के सबसे बड़े मिसाइल एवं एडवांस्ड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग ईकोसिस्टम का शिलान्यास किया। लगभग ₹2,500 करोड़ के निवेश से विकसित होने वाली यह परियोजना भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के साथ-साथ ग्वालियर-चंबल अंचल को देश के अग्रणी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करेगी। सिंधिया ने इसे राष्ट्रनिर्माण, राष्ट्रसेवा और राष्ट्रसुरक्षा के इतिहास में एक नया अध्याय और नया सवेरा बताया। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत का समय आ चुका है। आज भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में ऐतिहासिक गति से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश औद्योगिक निवेश का प्रमुख केंद्र बन रहा है और यह परियोजना उसी दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के कोलारस क्षेत्र में स्थापित होने वाला यह डिफेंस कॉम्प्लेक्स कोटा कॉरिडोर एवं बॉम्बे-ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट स्थित होने के कारण देशभर के सैन्य प्रतिष्ठानों तक रक्षा उपकरणों की तेज और प्रभावी आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में आधुनिक मिसाइल प्रणालियों, प्रिसिजन-गाइडेड म्यूनिशन तथा अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों का निर्माण किया जाएगा। इससे भारत की स्वदेशी रक्षा उत्पादन क्षमता और निर्यात संभावनाओं को नई मजबूती मिलेगी तथा ह्यमेक इन इंडियाह्ल और ह्यआत्मनिर्भर भारतह्ल अभियान को बल मिलेगा।

तेलंगाना में बनेंगे 3 नए एयरपोर्ट !

तेलंगाना सरकार राज्य में हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए तीन नए एयरपोर्ट विकसित करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। फिलहाल राज्य में केवल हैदराबाद का राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ही प्रमुख एयरपोर्ट है, जिससे जिलों के लोगों को हवाई यात्रा के लिए राजधानी आना पड़ता है। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने वारंगल, आदिलाबाद और भद्राद्री कोठागुडेम में नए एयरपोर्ट की योजना पर काम तेज कर दिया है। वारंगल एयरपोर्ट का अगले महीने होगा शिलान्यास

सरकार ने घोषणा की है कि वारंगल के मामुनूर एयरपोर्ट परियोजना का शिलान्यास अगले महीने किया जाएगा। इससे उत्तर और पूर्वी तेलंगाना के लोगों को हवाई यात्रा की बेहतर सुविधा मिलेगी।

आदिलाबाद और कोठागुडेम परियोजनाओं पर काम जारी

आदिलाबाद एयरपोर्ट के लिए केंद्र सरकार पहले ही मंजूरी दे चुकी है। यहां पहले भारतीय वायुसेना (क्अत्र्) का रनवे मौजूद था। अब अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण कर इसे सैन्य और नागरिक–दोनों उद्देश्यों के लिए हाइब्रिड मॉडल पर विकसित किया जाएगा। वहीं भद्राद्री कोठागुडेम एयरपोर्ट के लिए राज्य सरकार लगातार केंद्र से बातचीत कर रही है। अधिकारियों को उम्मीद है कि जल्द ही इस परियोजना को भी अंतिम स्वीकृति मिल जाएगी।

एरोमार्ट 2026 में मंत्री का बड़ा बयान

हैदराबाद में आयोजित एरोमार्ट 2026 सम्मेलन में राज्य के मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि वारंगल एयरपोर्ट की आधारशिला अगले महीने रखी जाएगी और आदिलाबाद एयरपोर्ट की डीपीआर भी तैयार हो चुकी है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य में

1,500 से अधिक एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के लिए पुर्जे तैयार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले कई लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों में के पुर्जे लगाए जा रहे हैं, जो राज्य की औद्योगिक प्रगति का प्रमाण है।

टीआरएस नाम को लेकर फिर फंसा पेच, के कविता को ईसीआई का नोटिस

के. कविता की नई राजनीतिक पार्टी के नाम ह्यट-ीआरएसह्न (TRS) को लेकर चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है, जिससे नामकरण को लेकर गहरा विवाद खड़ा हो गया है। यह विवाद उनके पिता के. चंद्रशेखर राव द्वारा स्थापित मूल ह्यतेलंगाना राष्ट्र समितिह्न (TRS) से समानता के कारण उत्पन्न हुआ है, जिसके नाम पर कविता अपना राजनीतिक भविष्य तय करना चाहती हैं। इस राजनीतिक दल के नाम पर उठे सवाल तेलंगाना की राजनीति में एक नई बहस का केंद्र बन गए हैं। भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने के. कविता को उनकी प्रस्तावित पार्टी के नाम 'TRS' पर आपत्तियों के बाद नोटिस जारी किए हैं। यह कार्रवाई 4 जुलाई को तब की गई जब आयोग को 1,100 से ज्यादा शिकायतें मिलीं। इनमें से एक शिकायत कथित तौर पर भारत राष्ट्र समिति (BRS) ने कविता की प्रस्तावित पार्टी के नाम और इफ्र की पुरानी पहचान के बीच समानता को लेकर दर्ज कराई थी। कविता ने शुरू में अपनी नई राजनीतिक पार्टी का नाम ह्यतेलंगाना राष्ट्र सेनाह्न (TRS) रखने की घोषणा की थी। हालाँकि, चुनाव आयोग (ECI) ने उन्हें सलाह दी कि वे कोई दूस-रा नाम चुनें ताकि पुरानी ह्यतेलंगाना राष्ट्र समितिह्न (TRS) ऋ जिसका नाम बाद में बदलकर ह्यभारत राष्ट्र समितिह्न (BRS) कर दिया गया था ऋ के साथ कोई भ्रम न हो। चुनाव आयोग की सलाह मानते हुए, कविता ने पार्टी का नाम बदलकर ह्यतेलंगाना रक्षा सेनाह्न कर दिया। इसके बावजूद, पार्टी के लिए पहले प्रस्तावित नाम को लेकर मिली कई शिकायतों के कारण उन्हें नोटिस भेजे गए। सूत्रों के अनुसार, कविता चुनाव आयोग के रुख को मानने को तैयार नहीं हैं और आयोग की सलाह मानने के बजाय कानूनी रास्ता अपना सकती हैं। इस विवाद ने तेलंगाना में राजनीतिक बहस छेड़ दी है; विपक्षी पार्टियां इसे कविता के लिए शर्मिंदगी की बात बता रही हैं, जबकि उनके समर्थकों का कहना है कि यह मामला कानूनी तरीके से सुलझाया जाएगा। अप्रैल में, चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर कविता की नई राजनीतिक पार्टी को ह्यतेलंगाना रक्षा सेनाह्न (TRS) नाम दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञान कुमार ने इस मंजूरी की पुष्टि की। पार्टी के लॉन्च के समय, कविता ने प्रस्तावित नाम के तौर पर ह्यतेलंगाना राष्ट्र सेनाह्न की घोषणा की थी, लेकिन एउकने ह्यतेलंगाना रक्षा सेनाह्न को मंजूरी दी, जिससे ळफ्र शॉर्ट-फॉर्म (इनिशियल्स) बरकरार रहा। उनके पिता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री, के. चंद्रशेखर राव ने मूल रूप से ह्यतेलंगाना राष्ट्र समितिह्न (TRS) शुरू की थी, जिसका नाम बाद में बदलकर ह्यभारत राष्ट्र समितिह्न (BRS) कर दिया गया था।

आंध्र प्रदेश की गोल्ड माइन ने रचा इतिहास

2,000 साल बाद फिर शुरू हुआ सोने का सफर

आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के जोंनागिरी में देश की पहली निजी सोने की खदान में वाणिज्यिक परिचालन शुरू हो गया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किया। आंध्र प्रदेश के जोंनागिरी में देश की पहली निजी सोने की खदान चालू। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने परियोजना का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। यह खदान घरेलू सोने उत्पादन बढ़ाएगी, 700 लोगों को रोजगार देगी। भारतीय माइनिंग सेक्टर में देश में आजादी के बाद पहली बार किसी निजी कंपनी के स्वामित्व वाली सोने की खदान में कमर्शियल कामकाज पूरी तरह शुरू हो गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को राज्य के कुरनूल जिले के जोंनागिरी में इस महत्वाकांक्षी गोल्ड माइनिंग और प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट का औपचारिक उद्घाटन किया। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री ने न सिर्फ पहली यूनिट की शुरूआत की, बल्कि इस प्रोजेक्ट के दूसरे फेज की आधारशिला भी रखी। यह परियोजना भारत के घरेलू सोने के उत्पादन को मजबूत करने में गेम-चेंजर साबित होने वाली है। इस ऐतिहासिक गोल्ड माइन को फिर से जीवंत करने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी और निवेश किया गया है। कुल 405 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस प्रोजेक्ट को जियोमैसूर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड और त्रिवेणी अर्थमूवर्स की साझेदारी में चलाया जा रहा है। यह देश की इकलौती ऑपरेशनल प्राइवेट प्राइमरी गोल्ड माइन है। प्राइमरी गोल्ड माइन एक ऐसी हार्ड-रॉक माइनिंग प्रक्रिया होती है, जिसमें सोना सीधे जमीन के भीतर चट्टानों और क्वार्ट्ज नसों से निकाला जाता है। राज्य सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए कुल 1500 एकड़ जमीन आवंटित की है, जिसके पहले फेज में लगभग 600 एकड़ पर कामकाज शुरू हो चुका है। इसके अलावा, खदान के सुचारू संचालन के लिए ह्यहंड्री नीवा सुजला स्रवंतीह्न योजना के जरिए 18 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाकर पानी की सप्लाई भी सुनिश्चित की गई है। वर्तमान में भारत सालाना केवल 1.5 टन सोने का उत्पादन करता है, जो हमारी कुल घरेलू खपत का मुश्किल से 1% है। ऐसे में स्वर्णगिरी खदान भारत की विदेशी निर्भरता और विदेशी मुद्रा को बचाने में बड़ी भूमिका निभाएगी। इस खदान के चालू होने से

पड़ोसी राज्य कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित सरकारी स्वामित्व वाली हट्टी गोल्ड माइंस का एकाधिकार भी टूट गया है, जो अब तक भारत के स्थानीय सोने के उत्पादन का 99% हिस्सा पैदा करती थी। स्वर्णगिरी खदान से कमर्शियल ऑपरेशन के पहले साल में लगभग 400 किलोग्राम सोना निकालने का लक्ष्य रखा गया है, जो भारत के कुल घरेलू उत्पादन का करीब 20% होगा। दूसरे वर्ष में इस उत्पादन को बढ़ाकर 900 से 1000 किलोग्राम तक ले जाया जाएगा। वहीं, दूसरे फेज की प्रोसेसिंग यूनिट पूरी तरह चालू होने के बाद कंपनी की योजना तीन साल के भीतर सालाना कुल उत्पादन क्षमता को 2 टन तक पहुंचाने की है, जिससे घरेलू उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 50% से ज्यादा हो जाएगी।

स्थानीय लोगों को रोजगार का मौका

इस प्राइवेट गोल्ड माइन के शुरू होने से स्थानीय लोगों से लेकर राज्य सरकार तक सबको बड़ा आर्थिक फायदा होने वाला है। आंध्र प्रदेश सरकार को इस प्रोजेक्ट से उत्पादित सोने के कुल मूल्य पर 4% रॉयल्टी मिलेगी। शुरूआती 400 किलोग्राम के उत्पादन पर सरकार को सालाना करीब 57 करोड़ रुपये की कमाई होगी और जब उत्पादन बढ़कर 900 किलोग्राम पहुंचेगा, तो यह राजस्व 144 करोड़ रुपये प्रति वर्ष हो जाएगा। इसके साथ ही, इस माइनिंग प्रोजेक्ट के जरिए सीधे तौर पर लगभग 700 लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस कार्यबल का लगभग 80% हिस्सा स्थानीय समुदायों से ही लिया जाएगा। सोना खनन परियोजना के शुभारंभ के साथ ही मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यहां उत्पादित होने वाले सोने को आभूषण निर्माण के लिए कहीं बाहर भेजने के बजाय, सरकार खनन परियोजना के पास ही एक अत्याधुनिक गोल्ड ज्वैलरी मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित करेगी। इससे स्थानीय स्तर पर व्यापार और कौशल विकास के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार ने इस क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक अनुमतियों और सुरक्षा सहायता का भी पूर्ण आश्वासन दिया है। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि कुरनूल का यह प्रोजेक्ट महज एक शुरूआत है। यह पूरा क्षेत्र एक बड़े खनिज बेल्ट के अंतर्गत आता है, जहां सोने का भारी भंडार होने की उम्मीद है। स्वर्णगिरी के अलावा, अनंतपुर जिले के बोक्समपल्ली, रामागिरी और जवकूला जैसी कई अन्य साइट्स पर भी सोने की खोज जारी है।

इन प्राचीन भूवैज्ञानिक संरचनाओं की तुलना कर्नाटक की ऐतिहासिक कोलार और हुट्टी बेल्ट से की जा रही है, जो कभी दुनिया के सबसे अमीर गोल्ड फील्ड्स में गिने जाते थे।

पारंपरिक रूप से कीमती पत्थरों की भूमि रत्नालसीमा के रूप में विख्यात रायलसीमा क्षेत्र के लिए यह खदान आर्थिक पुनरुद्धार की एक नई सुबह लेकर आई है, जो राज्य को 2047 तक स्वर्णांध्र प्रदेश बनाने के दृष्टिकोण में एक बड़ा गेम-चेंजर साबित होगी।

सम्राट अशोक के काल से जुड़ा है नाता

यह खदान दुनिया की सबसे पुरानी सोने की खदानों में से एक है। माना जाता है कि तीसरी सदी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक के समय में यहां बड़े पैमाने पर सोना निकाला जाता था। पास के एरागुडी गांव में मिले मौर्य काल के शिलालेख इस क्षेत्र के ऐतिहासिक और आर्थिक महत्व को उजागर करते हैं। इस ऐतिहासिक शुरूआत को देखते हुए आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने उद्घाटन से ठीक पहले जोंनागिरी गांव का नाम बदलकर आधिकारिक तौर पर स्वर्णगिरी करने को मंजूरी दे दी है, क्योंकि प्राचीन काल में यह क्षेत्र अपने मूल नाम सुवर्णगिरी या सोने का पहाड़ के नाम से ही मशहूर था।

कर्नाटक में हिजाब, कलावा, पगड़ी पहनकर स्कूल जाने की अनुमति

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में धार्मिक प्रतीकों को पहनावे के रूप में शामिल करने संबंधी एक नया आदेश जारी किया. इस नए आदेश के तहत छात्रों को स्कूल-कॉलेज की यूनिफॉर्म के साथ ह्यसीमित पारंपरिक और प्रथा-आधारित प्रतीकह्ल पहनने की अनुमति दी गई है. इन पारंपरिक प्रतीकों में हिजाब, जनेऊ, पगड़ी, हाथ में पहने जाने वाले कलावा और रुद्राक्ष जैसी चीजें शामिल हैं. फरवरी 2022 में कर्नाटक की तत्कालीन बीजेपी सरकार ने मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनकर स्कूल-कॉलेज जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था. यह मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. राज्य सरकार का नया आदेश सरकारी स्कूलों और कॉलेजों, सहायता प्राप्त संस्थानों और राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले निजी शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होगा. हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि यूनिफॉर्म अब भी अनिवार्य रहेगी, लेकिन इन प्रतीकों को अतिरिक्त वस्तुओं के रूप में पहना जा सकेगा. आदेश के मुताबिक, किसी भी छात्र को इन प्रतीकों को धारण करने की वजह से प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा और न ही उसे ऐसे प्रतीक पहनने या हटाने के लिए मजबूर किया जाएगा. कर्नाटक सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने मीडिया को बताया कि ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जब छात्रों को धार्मिक प्रतीकों की वजह से उनकी पढ़ाई-लिखाई में बाधा पहुंची है. उनका कहना था, ह्लधार्मिक रीति-रिवाज छात्रों की शिक्षा और भविष्य के बीच बाधा नहीं बनने चाहिए. 24 अप्रैल की उस घटना से मुख्यमंत्री को बहुत दुख हुआ था जब बेंगलुरु में केसीईटी (कर्नाटक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट) परीक्षा में हिजाब और जनेऊ पहनकर आए छात्रों को परीक्षा में प्रवेश देने से रोक दिया गया था. इस तरह की बातें बच्चों की शिक्षा के रास्ते में नहीं आनी चाहिए. हमें यह फैसला बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था.ह्ल कर्नाटक में कांग्रेस के नेतृत्व में मई 2023 में सरकार बनी थी और सत्ता में आने के बाद ही दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री के सिद्धारमैया ने कहा था कि उन्होंने राज्य में हिजाब पर प्रतिबंध के आदेश को वापस लेने का निर्देश दिया है. उस वक्त उन्होंने कहा था कि पोशाक और भोजन का चुनाव व्यक्तिगत है और किसी को भी इसमें दखल नहीं देना चाहिए. कर्नाटक में पांच साल पहले हिजाब को लेकर विवाद उस वक्त सामने आया जब उडुपी जिले के एक सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज में हिजाब पहनकर आने वाली लड़कियों को कॉलेज में प्रवेश करने से रोक दिया गया. छात्राओं का कहना था कि हिजाब उनकी आस्था और पहचान का हिस्सा है, जबकि कॉलेज प्रशासन ने ड्रेस कोड का हवाला देते हुए उनके प्रवेश पर पाबंदी लगा दी. छात्राओं के हिजाब पहनने के जवाब में कॉलेज में हिंदू विद्यार्थी भगवा गमछा पहनकर आने लगे और धीरे-धीरे यह विवाद राज्य के अन्य हिस्सों में भी फैल गया. कई शिक्षण संस्थानों में इसकी वजह से सांप्रदायिक तनाव जैसी स्थिति आ गई. कर्नाटक में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली तत्कालीन बीजेपी सरकार ने स्कूल-कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया. सरकार ने अपने आदेश में कहा था कि ह्यसमानता, अखंडता और सार्वजनिक कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए.ह्ल सरकार के इस आदेश को कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी गई लेकिन तीन जजों की बेंच ने सरकार के आदेश को बरकरार रखा. बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां यह अभी भी लंबित है. सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की बेंच ने इस मामले को मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया था लेकिन दोनों न्यायाधीशों की राय इस पर बंटी हुई थी. जस्टिस हेमंत गुप्ता (अब सेवानिवृत्त) ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया था, जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने इसकी अनुमति दी थी. जस्टिस गुप्ता ने कहा था कि यह केवल एकरूपता को बढ़ावा देने और एक धर्मनिरपेक्ष वातावरण को प्रोत्साहित करने के लिए था लेकिन जस्टिस धूलिया ने राज्य और हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर कक्षाओं में हिजाब पहनने के अधिकार को ह्यपसंद का मामलाह्ल और ह्यमौलिक अधिकारह्ल बताया था. कर्नाटक में साल 2023 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ही मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पिछली सरकार का आदेश वापस लेने का ऐलान किया था लेकिन हाल की घोषणा के पीछे कुछ तात्कालिक वजहों और राजनीतिक कारणों को भी देखा जा रहा है.

कमजोर मानसून का विकास दर पर असर

आरबीआई द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पर जारी हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून के कमजोर रहने से देश की कृषि और विकास दर पर असर पड़ सकता है। इस समय जून माह में समय से पीछे चल रहे मानसून ने खरीफ फसलों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। अभी तक करीब 42 प्रतिशत बारिश कम होने से नकदी फसलें कपास और सोयाबीन बुवाई के आरंभिक दौर में पिछड़ गई हैं। ऐसे में कृषि तथा अर्थव्यवस्था के सामने अल-नीनो और कमजोर मानसून से सूखे की आशंका तथा महंगाई की चुनौतियां उभरकर दिखाई दे रही हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व मौसम विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वर्ष 2026 में भारत अल-नीनो से अत्यधिक प्रभावित होगा। कमजोर मानसून और सूखे की स्थिति कृषि, जल आपूर्ति और महंगाई के परिदृश्य पर चुनौतियां निर्मित करते हुए दिखाई देगी। इससे पहले वर्ष 2015 में भारत में अत्यधिक कम बारिश रिकॉर्ड की गई थी, उस समय मानसून सामान्य से लगभग 13 प्रतिशत कम था। इस वर्ष मानसून के दौरान अल-नीनो की स्थिति मजबूत होने की वजह से बारिश अत्यधिक कम होगी। इतना ही नहीं, जलाशयों के सूखने और खेती के लिए पानी की कमी की चिंता बढ़ गई है। यह परिदृश्य भारत द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान लक्षित विकास दर को बनाए रखने के लिए एक चुनौती दिखाई दे रहा है।

नीति आयोग के मुताबिक देश के कुल फसल रकबे का केवल 55 प्रतिशत सिंचित है और 45 प्रतिशत खेती मानसून पर निर्भर है। सीडब्ल्यूएमआई के अनुसार, लगभग 74 प्रतिशत गेहूं और 65 प्रतिशत चावल की खेती वाले क्षेत्र पहले से ही भारी जल-संकट का सामना कर रहे हैं। व्यावसायिक फसलों और औद्योगिकीकरण की ओर बढ़ते रुझान से भारत में मानसून की वर्षा पर निर्भरता बढ़ी हुई है। मौजूदा परिदृश्य देश के वर्तमान सुकूनदायक कृषि क्षेत्र के समक्ष एक चुनौती बनकर दिखाई दे रहा है। कम बारिश से जलाशयों में पानी का स्तर गिरने से सिंचाई और पीने के पानी की उपलब्धता प्रभावित होगी, ऐसे में अभी से जल संरक्षण के प्रयास शुरू होने चाहिए। भारत को फसल विविधीकरण और खेती में आधुनिक तकनीक के एकीकरण के साथ आगे बढ़ना होगा। कमजोर मानसून और अल-नीनो के खतरे के पूर्वानुमान के बीच खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए खाद्य भंडारण को मजबूत करना होगा। भारत में अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन एक ह्यसुरक्षा कवचह्ल की तरह है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि वर्ष 2008 की वैश्विक मंदी में भी भारत की अर्थव्यवस्था खाद्यान्न ताकत के कारण बहुत कम प्रभावित हुई। इतना ही नहीं, कोरोना से जंग में देश के खाद्यान्न भंडार देश के लिए हथियार बन गए थे। इसलिए गेहूं के आगामी किसी भी नए निर्यात आदेश की पूर्ति के लिए सजगता रखनी होगी। चूंकि इस साल खरीफ सीजन की बुवाई शुरू से ही कम रहने से देश के किसानों और नीति-निमार्ताओं की चिंताएं बढ़ गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार देश के कई हिस्सों में पिछले 10 सालों का सबसे खराब और सूखा मानसून देखने को मिल सकता है। अल-नीनो के बढ़ते असर को देखते हुए केंद्र सरकार ने 1 जून, 2026 से देशव्यापी ह्यखेत बचाओह्ल अभियान के तहत रणनीतिपूर्वक कदम बढ़ाए हैं। इसके तहत किसानों को उनके इलाके और फसल के हिसाब से खास सलाह दी जा रही है, ताकि वे मौसम के जोखिमों को समझकर सही निर्णय ले सकें। इसके साथ-साथ किसानों को उनके इलाके के मौसम, वहां की मिट्टी और बाजार की मांग के हिसाब से कृषि उत्पादन संबंधी व्यावहारिक मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है। सरकार ने एक व्यापक और सहयोगी ढांचा तैयार किया है। इस अभियान में स्थानीय पंचायतों, राज्य सरकारों, कृषि विज्ञान केंद्रों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों और स्थानीय कृषि विभागों को एक साथ जोड़ा गया है। कृषि मार्गदर्शन की पहुंच मजबूत करने के लिए 1,600 से ज्यादा विशेष टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें खेतों में जाकर किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड और पीएम-किसान जैसी योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद भी करेंगी। इसके साथ ही दालों और तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने, ऑयल पाम की खेती, कॉटन मिशन, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट और जल संरक्षण जैसे अभियानों को भी इसी अभियान से जोड़कर जागरूकता फैलाई जाएगी।

डिजिटल साक्ष्यों से अपराधियों पर कसती नकेल

क्राइम थ्रिलर फि ल्मों में अक्सर हम देखते थे कि अपराधी बड़ी चतुराई से सबूत मिटा देता था और अंत में ह्यपरफेक्ट मर्डरह्ल की गुत्थी अनसुलझी रह जाती थी। क्राइम थ्रिलर फि ल्मों में अक्सर हम देखते थे कि अपराधी बड़ी चतुराई से सबूत मिटा देता था और अंत में ह्यपरफेक्ट मर्डरह्ल की गुत्थी अनसुलझी रह जाती थी। तब पुलिस की सफलता उंगलियों के निशानों और चश्मदीद गवाहों पर टिकी होती थी। लेकिन आज,हर इंसान चलते-फिरते एक ह्यडिजिटल डेटा बैंकह्ल बन चुका है। डिजिटल युग में ह्यपरफेक्ट मर्डरह्ल की धारणा अब एक मिथक मात्र है, क्योंकि तकनीकी साक्ष्य मानवीय गवाहों से अधिक विश्वसनीय साबित हुए हैं। केतन मर्डर केस और श्रद्धा वालकर हत्याकांड जैसे हालिया हाई-प्रोफाइल मामलों ने यह सिद्ध कर दिया है कि अपराधी चाहे कितने भी भौतिक सबूत मिटा ले, उसका ह्यडिजिटल फुटप्रिंटह्ल - जैसे कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड , टावर लोकेशन, गूगल मैप्स हिस्ट्री और इंटरनेट सर्च क्वेरी - झूठ नहीं बोलते। यह डेटा ट्रैकिंग न केवल अभियुक्तों के ह्यअलबाईह्ल (घटनास्थल पर न होने का दावा) को खारिज करती है, बल्कि अपराध के इरादे और उसकी कड़ियों को जोड़ने में निर्णायक भूमिका निभाती है। आधुनिक न्यायिक प्रक्रिया में तकनीक ने अपराध जांच की दिशा पूरी तरह बदल दी है, जहां ह्यडेटा ही सबसे बड़ा गवाहह्ल बन गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (धारा 61 और 63) ने जांच की परिभाषा को पूरी तरह बदल दिया है। अब हत्या जैसे अपराधों की जांच केवल पोस्टमॉर्टम तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल साक्ष्य पर केंद्रित हो गई है। आज अपराधी चाहे कितनी भी चतुराई करे, वह अपने पीछे डेटा का एक ऐसा जाल छोड़ जाता है - जैसे कि मोबाइल लोकेशन, गूगल मैप्स, इंटरनेट सर्च हिस्ट्री, स्मार्ट वॉच का डेटा, व्हाट्सएप चैट्स, वाई-फाई सिग्नल, सीसीटीवी फुटेज और होम डिवाइस की वॉयस रिकॉर्डिंग, या ई-चालान में कैद कार की नंबर प्लेट - जो उसकी अपराध में संलिप्तता साबित करने के लिए पर्याप्त है। वर्तमान कानून के तहत, इन डिजिटल साक्ष्यों को अदालतों में ह्यप्राथमिक साक्ष्यह्ल के रूप में पूर्ण मान्यता प्राप्त है। भारतीय न्याय प्रणाली में डिजिटल साक्ष्यों की स्वीकार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अनवर पी.वी. (2014) और अर्जुन पंडितराव खोतकर (2020) जैसे ऐतिहासिक फैसलों के माध्यम से स्पष्ट किया है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की प्रमाणिकता हेतु धारा 65 बी के तहत प्रमाण पत्र अनिवार्य है। ये दोनों ही मामले ह्यइलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की ग्राह्यताह्ल से संबंधित हैं। भारतीय कानून ने तकनीक के युग में साक्ष्यों की सत्यता सुनिश्चित कर न्याय को सुदृढ़ तो किया है, लेकिन इसने निजता के अधिकार के समक्ष भी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। के.एस. पुट्टास्वामी (2017) का फैसला हमें आगाह करता है कि सुरक्षा के नाम पर राज्य की डिजिटल निगरानी असीमित नहीं हो सकती। कानून निमार्ताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती ह्यडिजिटल फॉरेंसिकह्ल के नाम पर नागरिकों की निजता और सुरक्षा के बीच एक सटीक संतुलन बनाए रखना है। आजकल अपराध और जांच का स्वरूप पूरी तरह डिजिटल हो गया है। अपराधी ह्यपरफेक्ट मर्डरह्ल के लिए सबूत मिटाने हेतु डेटा हैक या डिलीट करने का सहारा लेते हैं । हालांकि, वे यह भूल जाते हैं कि डिजिटल दुनिया में ह्यडिलीटह्ल किया गया डेटा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। ह्यडिजिटल फॉरेंसिकह्ल और ह्यरिकवरी टूल्सह्ल के जरिए पुलिस क्लाउड बैकअप, सर्वर लॉग्स और डिलीट की गई फाइलों को आसानी से पुनः प्राप्त कर सकती है। डिजिटल सर्वर पर हर गतिविधि का कोई न कोई प्रमाण हमेशा मौजूद रहता है। दरअसल, जैसे-जैसे कानून सख्त हो रहा है, अपराधी ह्यआर्टिफिशियल इंटेलिजेंसह्ल और ह्यडार्क वेबह्ल का इस्तेमाल करके खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पुलिस डिजिटल साक्ष्य के सहारे आगे बढ़ रही है, वहीं अपराधी डिजिटल साक्ष्य को ह्यमैनीपुलेटह्ल या ह्यफेक डिजिटल फुटप्रिंटह्ल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह साइबर-क्राइम और फोरेंसिक का एक नया युद्ध है। आज अपराधों को रोकने के लिए व्यवस्था को ह्यडिजिटल-रेडीह्ल बनाना अनिवार्य है। सबसे पहले पुलिस बल का आधुनिकीकरण करते

हुए हर स्तर पर अत्याधुनिक साइबर-फोरेंसिक लैब और विशेषज्ञों की एक बड़ी टीम तैयार करनी होगी। साथ ही, जजों और वकीलों को तकनीकी साक्ष्यों की बारीकियां समझने के लिए नियमित प्रशिक्षण देना जरूरी है। साक्ष्यों की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने हेतु ब्लॉकचेन जैसी तकनीक का उपयोग करना चाहिए और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सीसीटीवी नेटवर्क को और अधिक सुदृढ़ करना होगा। नागरिक जागरूकता को बढ़ावा देने के साथ-साथ निजी डेटा सुरक्षा और जांच के बीच एक सटीक संतुलन बनाना होगा, ताकि तकनीक का उपयोग अपराध को सुलझाने में एक मजबूत और पारदर्शी हथियार के रूप में किया जा सके। आज अपराधी चाहे जितनी चालाकी से सबूत मिटा ले, वह डिजिटल दुनिया में कोई न कोई ऐसी भूल कर देता है जो उसे सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। हालांकि, इस पूरी व्यवस्था में न्याय की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए तकनीक के साथ-साथ मानवीय समझ का संतुलन भी बेहद जरूरी है। कई बार चीजें ऐसी होती हैं कि जो शायद समझ कम आएं, लेकिन समझ आने का जतन करना जरूरी है। शायद तब समझदारी भी इसी में मानी जाती है कि यह ठीक है या यह गलत है। जैसे बात करें बजट की। भारत सरकार ने अलौकिक बजट पुनः जारी किया। इसकी अलौकिकता न्यारी है। आम आदमी की समझ पर यह भारी है। लौकिक ज्ञान से परे अलौकिक ज्ञान जरूरी है। अतः, इसे अच्छा या खराब मान लेना ही बुद्धिमत्ता है। साधारण-सी बात है। जो विपक्ष में है, वे इसे बेकार बजट बता रहे। जो पक्ष है, वे इसे साकार बजट बता रहे। इस पक्ष, विपक्ष में आम आदमी चक्कर खा रहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या समझे। वह पक्ष की सुने या विपक्ष की। पक्ष की बात के साथ रहे या विपक्ष की। अब देखिए, दीदी ने समझाया। यह दलित, महिला, ओबीसी, किसान, युवा विरोधी बजट है। तब खेलावन काका पूछ रहे। अरे, तब यह बजट सरकार ने अपने लिए लेकर आई है क्या? तब इसको लेकर मुनि नारद ने ज्ञान दिया। देखो वत्स, यह अलौकिक है। फिर भी इसमें सार तत्व को समझ कर इसकी विशालता और व्यापकता को समझा जा सकता है। जैसे इस उदाहरण से समझो। बजट में बच्चों को स्कूल में अब डिजिटल क्रिएटर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें अब बच्चे अपने स्कूल में मोबाइल से रील बनाना सीखेंगे। फिर देश तेजी से आगे बढ़ेगा। उतनी ही तेजी से जितनी तेजी से देश में बुलेट रेल चल रही। और उतनी ही तेजी से जितनी तेजी से देश में स्मार्ट शहर बन रहे। समझे कि नहीं। बात जब ऐसी चल रही थी तो काका कहां चुप रहने वाले। बोले, मुनिनाथ। हम लोग तो बच्चों को रील बनाने से रोकते हैं। इसे अच्छा नहीं मानते। यही तो लौकिक बातें हैं। पर समझो। तुम लोग बच्चों को क्यों पढ़ाते हो...? इसीलिए कि वह पढ़ लिख कर कमाई करे! अब इस बार चुनाव में सरकार ने प्रति वर्ष 2 करोड़ को नौकरी और रोजगार देने का वादा किया। यह वादा इसी से पूरा होगा। अभी सर्वाधिक कमाई का साधन मोबाइल है। रील बना कर लोग प्रति महीना लाखों कमा रहे हैं। इसमें कौशल की जरूरत है। हालांकि, महिलाओं के लिए कोई कौशल आवश्यक नहीं है

रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL)

रेल विकास निगम लिमिटेड
Rail Vikas Nigam Limited
गुणवत्ता, गति एवं पारदर्शिता
(A Government of India Enterprise)

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना | चुनौतीपूर्ण पर्वतीय भूभाग में सुगम पहुंच का निर्माण

रेल विकास निगम लिमिटेड गढ़वाल हिमालय के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र में एक ऐतिहासिक रेल कॉरिडोर का निर्माण कर रहा है, जो इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्व-मौसम कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा और भारत के सबसे चुनौतीपूर्ण पर्वतीय भूभागों में सुरक्षित व विश्वसनीय आवागमन को बढ़ावा देगा। जटिल सुरंग निर्माण, पुल कार्यों और सतत क्रियान्वयन के साथ, यह परियोजना भारत के पर्वतीय रेल अवसंरचना विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रमुख तथ्य

- 125 किमी लंबा रेल संरेखण
- 2019 से अब तक 17.5 करोड़ मानव-दिवस सृजित
- 83% संरेखण सुरंगों से होकर
- 7 घंटे से 2.5 घंटे यात्रा समय में कमी
- 16 मुख्य सुरंगें + 12 एस्केप सुरंगें
- 19 प्रमुख पुल + 38 छोटे पुल

शिव और शक्ति

उन्नत टीबीएम जटिल हिमालयी भूगर्भीय परिस्थितियों में सटीक सुरंग निर्माण को सक्षम बना रही हैं और इस परियोजना में मशीनीकृत पर्वतीय सुरंग निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम हैं।

परियोजना की प्रमुख विशेषताएं

- चार धाम क्षेत्र तक भविष्य में बेहतर पहुँच
- दुर्गम भूभाग में मजबूत सर्व-मौसम कनेक्टिविटी
- क्षेत्रीय आवागमन और विकास को समर्थन

जिम्मेदारी के साथ निर्माण

ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के 12 स्टेशनों का विकास ग्रीन बिल्डिंग नॉर्म्स के अनुसार किया जा रहा है, ताकि परियोजना का विकास टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से हो सके। इसके साथ ही, मलबे (मक) के जिम्मेदार निपटान, ढलानों की सुरक्षा, भूजल संरक्षण तथा जमीन की सतह पर कम से कम प्रभाव डालने जैसे उपायों के माध्यम से हिमालयी क्षेत्र में इस परियोजना का निर्माण सुरक्षित और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील तरीके से किया जा रहा है।

www.rvnl.org | RailVikas | railvikasindia | @RailVikasNigamLimited
@rvnl_official | @RailVikasNigamLimited | @RVNL Official

एक बार फिर भारतीय सर्व समाज महासंघ सामाजिक सेवा एवं जनकल्याण कार्यक्रम

आप सभी के सहयोग, स्नेह एवं शुभकामनाओं से भारतीय सर्व समाज महासंघ, नई दिल्ली द्वारा एक भव्य सामाजिक सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर समाज के सैकड़ों जरूरतमंद व्यक्तियों को उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उपयोगी सामग्री वितरित की जाएगी।

कार्यक्रम के अंतर्गत–

- बालिकाओं को शिक्षा हेतु टैबलेट
- निर्धन महिलाओं को आजीविका हेतु सिलाई मशीन
- विवाहित दंपतियों को गैस चूल्हा
- बुजुर्गों को बी.पी. मशीन
- जरूरतमंद परिवारों को पानी के फिल्टर

आदि सामग्री वितरित की जाएगी।

हमें पूर्ण विश्वास है कि इन आवश्यक वस्तुओं के माध्यम से लाभार्थियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा तथा वे आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।

इस गरिमामय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में

माननीय श्री रामदास अठावले जी

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री, भारत सरकार)

की उपस्थिति रहेगी।

कार्यक्रम की अध्यक्षता

श्री राम कुमार वालिया जी

(पूर्व राज्य मंत्री, उत्तराखंड)

अध्यक्ष झ भारतीय सर्व समाज महासंघ

व किसान उपभोक्ता बहु-राज्य सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली

द्वारा की जाएगी।

इस अवसर पर अनेक गणमान्य अतिथि, अधिकारीगण एवं समाजसेवी भी उपस्थित रहेंगे।

आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अपनी गरिमामयी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं तथा समाज सेवा के इस पुनीत कार्य में सहभागी बनें।

कोविड के बाद नए वायरस की दस्तक?
क्रूज शिप पर 3 ट्रेलर, जानें भारत के लिए क्या हैं संकेत

केप वर्डे के पास एक क्रूज शिप पर हंटावायरस का प्रकोप सामने आया है, जिसमें 7 संक्रमण और 3 मौतों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद हल्ड ने इंसान से इंसान में फैलने की दुर्लभ क्षमता वाले इस वायरस को लेकर चेतावनी जारी की है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह संक्रमण एक सीमित दायरे में है और फिलहाल वैश्विक महामारी का खतरा बेहद कम है। कोविड महामारी के जख्म अभी पूरी तरह भरे भी नहीं थे कि एक और वायरस ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हंटावायरस को लेकर अलर्ट जारी किया है। यह एक दुर्लभ वायरस है जो इंसान से इंसान में भी फैल सकता है। फिलहाल, यह केप वर्डे के तट के पास खड़ा एक क्रूज जहाज पर फैला है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि जोखिम काफी कम है और स्थिति कंट्रोल में है।

आखिर जहाज पर क्या हुआ?

147 लोगों को ले जा रहे इस क्रूज शिप पर अब तक हंटावायरस के 7 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने सुरक्षा के लिहाज से जहाज को किनारे से दूर खड़ा कर दिया है और लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। माना जा रहा है कि संक्रमण जहाज के अंदर से नहीं, बल्कि यात्रा के दौरान दक्षिण अमेरिका में किसी जगह से शुरू हुआ था।

कितना खतरनाक है हंटावायरस?

हंटावायरस सीधा फेफड़ों पर हमला करता है, जिससे सांस लेने में गंभीर समस्या हो सकती है। सबसे ज्यादा चिंता की बात इसका इंसान से इंसान में फैलना है, हालांकि ऐसा बहुत कम होता है। हल्ड के मुताबिक, यह वायरस आमतौर पर संक्रमित व्यक्ति के बहुत करीब रहने वाले लोगों को ही शिकार बनाता है। जहाज जैसी बंद जगह में तो इसका खतरा रहता है, लेकिन खुले में इसके बड़े पैमाने पर फैलने की उम्मीद कम है।

क्या दुनिया पर मंडरा रहा है खतरा?

राहत की बात यह है कि इसके दुनिया भर में फैलने की संभावना बहुत कम है। यह कोई साधारण फ्लू नहीं है जो हवा के जरिए तेजी से फैल जाए। ज्यादातर हंटावायरस चूहों या उनके मल-मूत्र के संपर्क में आने से फैलता है। फिलहाल जो मामले सामने आए हैं, वे एक छोटे ग्रुप तक ही सीमित हैं और जहाज के बाहर इसके फैलने का कोई सबूत नहीं मिला है।

हल्ड की चिंता की क्या है वजह?

भले ही यह वायरस दुर्लभ हो, लेकिन हल्ड इसे गंभीरता से ले रहा है। एक्सपर्ट्स को शक है कि यह हंटावायरस का एंडीज वैरिएंट हो सकता है, जिसमें पहले भी इंसान से इंसान में संक्रमण फैलाने की क्षमता देखी गई है। क्रूज जहाज जैसी बंद जगहें ऐसे वायरस के लिए हॉटस्पॉट बन सकती हैं, इसलिए सावधानी बरती जा रही है।

क्या भारत को है कोई डर?

भारत के लिए फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ इस वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है और इसके इंटरनेशनल लेवल पर फैलने के चांस भी न के बराबर हैं। डॉक्टरों का कहना है कि हमें बस जागरूक रहने की जरूरत है, पैनिक करने की बिल्कुल नहीं।

इन लक्षणों को न करें इग्नोर

हंटावायरस के शुरूआती लक्षण बिल्कुल फ्लू जैसे होते हैं, जैसे तेज बुखार, थकान, सिरदर्द और पेट में दर्द। अगर स्थिति बिगड़ती है, तो सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगती है। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया है, तो इन लक्षणों के दिखते ही तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।

भारतीय सर्व समाज महासंघ द्वारा एक बार फिर बड़ी संख्या में लोगों को बांटे जरूरत के सामान

भारतीय सर्व समाज महासंघ द्वारा अंबेडकर भवन शिमला कल देहरादून में एक विशाल आवश्यक वस्तु वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें सैकड़ो की संख्या में लोग उपस्थित रहे तथा उनका आवश्यकता का सामान वितरित किया गया इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से 20 बालिकाओं को टैबलेट फोन दिए गए जिससे उनको पढ़ाई करने में सुविधा 30 महिलाओं को गैस के चूल्हे भेंट किए गए 50 महिलाओं को सिलाई मशीन 49 महिला एवं पुरुषों को बीपी मशीन 150 लोगों को वाटर फिल्टर भेंट किए गए कल करीब 300 लोगों को संस्था की तरफ से आवश्यक सामान वितरित किया गया

CSR Initiative of
AIRPORT AUTHORITY OF INDIA
BHARTIYA SARV SAMAJ MAHASANGH (BSSM INDIA)

AIRPORT AUTHORITY OF INDIA
BHARTIYA SARV SAMAJ MAHASANGH (BSSM INDIA)

AIRPORT AUTHORITY OF INDIA
BHARTIYA SARV SAMAJ MAHASANGH (BSSM INDIA)

CSR Initiative of
AIRPORT AUTHORITY OF INDIA
BHARTIYA SARV SAMAJ MAHASANGH (BSSM INDIA)

CSR Initiative of
AIRPORT AUTHORITY OF INDIA
BHARTIYA SARV SAMAJ MAHASANGH (BSSM INDIA)

AIRPORT AUTHORITY OF INDIA
BHARTIYA SARV SAMAJ MAHASANGH (BSSM INDIA)

CSR Initiative of
AIRPORT AUTHORITY OF INDIA
BHARTIYA SARV SAMAJ MAHASANGH (BSSM INDIA)

BHARTIYA SARV SAMAJ MAHASANGH (BSSM INDIA)

AUTHORITY OF INDIA
BHARTIYA SARV SAMAJ MAHASANGH (BSSM INDIA)

BHARTIYA SARV SAMAJ MAHASANGH (BSSM INDIA)

AIRPORT AUTHORITY OF INDIA
BHARTIYA SARV SAMAJ MAHASANGH (BSSM INDIA)

CSR Initiative of
AIRPORT AUTHORITY OF INDIA
USHA

CSR Initiative of
AIRPORT AUTHORITY OF INDIA
USHA

USHA

CSR Initiative of
AIRPORT AUTHORITY OF INDIA
USHA
SURYA

CSR Initiative of
AIRPORT AUTHORITY OF INDIA
SURYA

SURYA

CSR Initiative of
AIRPORT AUTHORITY OF INDIA

CSR Initiative of
AIRPORT AUTHORITY OF INDIA

CSR Initiative of
AIRPORT AUTHORITY OF INDIA

CSR Initiative of
AIRPORT AUTHORITY OF INDIA

पीएफ क्लेम में डिडक्शन पर ऑफिसर की कटेगी सैलरी

लगेगा 12% का भारी जुमार्ना

ईपीएफओ के नए नियमों के तहत अब पीएफ, पेंशन और बीमा दावों का निपटारा 20 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा, अन्यथा देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारी पर 12% वार्षिक दंडात्मक ब्याज लगेगा जो उनके वेतन से काटा जाएगा। खासतौर पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता के जरिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तीन नई योजनाओं को अधिसूचित कर दिया है। बता दें कि, इसमें कर्मचारी भविष्य निधि योजना-2026, कर्मचारी पेंशन योजना-2026 और कर्मचारी जमा-लिंक्ड बीमा योजना-2026 शामिल है। इन नई योजनाओं को तहत डिजिटल व्यवस्था को मजबूत बनाने और भविष्य निधि (पीएफ), पेंशन और बीमा दावों का समय पर निपटा लें। नई व्यवस्था के मद्देनजर अगर भविष्य निधि, पेंशन या बीमा का दावा सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट के साथ पूरा होने के बाद 20 दिनों के अंदर ही निपटा लें। वरना इस मामले में आयुक्त पर 12 प्रतिशत वार्षिक दंडात्मक ब्याज लगेगा। आपको बताते चलें कि, यह रकम संबंधित अधिकारी के वेतन से काटी जाएगी। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि, इससे दावों के निपटारे में अनावश्यक देरी पर रोक लगेगी और कर्मचारियों को समय पर उनका पैसा मिलेगा। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पहले भी देरी होने पर ब्याज देने का प्रावधान था, लेकिन अब इसे स्पष्ट रुप से 12 प्रतिशत तय किया है। पहले अधिकारियों को पीएफ पर घोषित ब्याज दर के अनुसार भुगतान करना पड़ सकता है। दरअसल, नई योजनाएं लागू होने के बाद कर्मचारी भविष्य निधि योजना-1952, कर्मचारी परिवार पेंशन योजना-1971, कर्मचारी पेंशन योजना-1995 और कर्मचारी जमा-लिंक्ड बीमा योजना-1976 की जगह लेंगी। जबकि कर्मचारियों व नियोक्ताओं के अंशदान में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले की तरह कर्मचारी और नियोक्ताओं के कर्मचारी और नियोक्ता दोनों अपने मूल वेतन का 12-12 प्रतिशत योगदान देंगे। नियोक्ता के अंशदान में से 8.33 फीसदी राशि पेंशन योजना में मिलेगी, वहीं केंद्र सरकार पहले की तरह 1.16 प्रतिशत का योगदान देगी। हालांकि, जो नई योजनाएं बनी गई हैं, उनमें नियोक्ताओं और ईपीएफओ दोनों के लिए डिजिटल अनुपालन को अनिवार्य बनाया गया है, जिससे सदस्य निकासी, पेंशन, बीमा और अन्य सेवाओं का लाभ कंप्लीट ऑनलाइन और बिना देरी के लिया जा सकता है।

Under the dynamic leadership of
Prem Singh Tamang
Chief Minister of Sikkim

ADVANCING SIKKIM, EMPOWERING PEOPLE TOGETHER FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND SHARED PROSPERITY

SIKKIM
A STATE ON THE RISE

"The true measure of progress is the well-being of our people. Every initiative is dedicated to improving lives."
-Prem Singh Tamang
Chief Minister of Sikkim

INCLUSIVE DEVELOPMENT | SOCIAL WELFARE | SUSTAINABLE FUTURE | TRANSPARENT GOVERNANCE

ORGANIC FARMING
for a healthier Sikkim

- Encouraging eco-friendly farming practices across the State
- A model for sustainable agriculture and green development
- Growing green, growing prosperity

Healthy Soil, Healthy Food, Healthy Sikkim

MILK INCENTIVE
encouraging our dairy farmers

- Milk Production Incentive Scheme providing dairy farmers with a direct subsidy of Rs.8 per liter of milk produced
- Incentivising milk production to support dairy farmers
- Encouraging quality dairy farming practices

Strong Farmer, Strong Sikkim

VATSALYA SCHEME
fulfilling the dream of parenthood through assisted reproductive care

- Financial assistance of up to Rs. 3 lakh for infertility treatment through IVF
- Enhancing maternal health and family welfare initiative

Every child matters, every child counts

AAMA SAHYOG YOJANA
Supporting Mothers, Strengthening Families

- Free LPG refills annually for eligible rural mothers
- Reducing financial burden of household cooking fuel expenses

Empowered Women, Strong family, Strong Sikkim

SIKKIM URBAN GARIB AWAS YOJANA
Affordable Housing for Dignified Living

- Providing safe, secure and permanent housing for economically weaker urban households
- Ensuring dignified shelter for urban houseless families.

A Home, A Hope, A Better Tomorrow

MERO RUKH MERO SANTATI
nurturing nature, preserving our legacy

- Fostering a sense of responsibility towards nature and ecological stewardship
- Encouraging every family to nurture trees as a living legacy for future generations

108 tree
saplings planted for every newborn child born in Sikkim

Sikkim
Nurturing Lives, Strengthening Communities
A New Era of Progress for Sikkim

1 जुलाई 2026 से पासपोर्ट नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, जानिए नई फीस दर और आवेदन का तरीका

केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों से मिली अद्यतन जानकारी के मुताबिक, 1 जुलाई 2026 से ही देशभर के विभिन्न विभागों में कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की सेवाओं पर पड़ेगा, जबकि कुछेक चीजें मुफ्त भी होंगी। इनमें से कुछ बदलाव 1 जुलाई से सीधे प्रभावी हैं। भारत सरकार ने पासपोर्ट नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जो 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा। दरअसल, विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में संशोधन किया है। नया संशोधित शुल्क ताजा आवेदन, पासपोर्ट रिन्यूअल (Re-issue), तत्काल सेवा और खोए/क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के मामलों पर लागू होगा। बताया गया है कि यदि आप 1 जुलाई 2026 के बाद पासपोर्ट आवेदन करेंगे तो आपको नई शुल्क दरों के अनुसार ही भुगतान करना होगा। प्राप्त विभागीय जानकारी के मुताबिक, नई फीस की मुख्य श्रेणियां इस प्रकार हैं, जो क्रमशः सेवा, पुरानी फीस और नई फीस को अभिव्यक्त करती हैं। कहने का आशय यह कि 36 पेज का सामान्य पासपोर्ट अब ₹1,500 के बजाए ₹2,500 में बनेगा, जो ₹1000 अधिक है। इसी प्रकार 36 पेज वाला तत्काल (Tatkal) पासपोर्ट के लिए अब ₹3,500 के बजाए ₹5,000 देने होंगे, जो ₹1500 ज्यादा है। इसी प्रकार से 60 पेज का सामान्य पासपोर्ट अब ₹2,000 की जगह ₹3,500 में बनेगा, यानी इस सेवा के लिए भी ₹1500 अधिक भुगतान करना पड़ेगा। वहीं, 60 पेज के तत्काल (Tatkal) पासपोर्ट के लिए अब ₹4,000 की जगह ₹6,000 देने होंगे, यानी कि इस कोटि में भी 2000 की बढ़ोतरी की गई है, जो सबसे ज्यादा है। इसके अलावा, खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट, नाबालिगों के पासपोर्ट तथा अन्य पासपोर्ट सेवाओं की फीस में भी बढ़ोतरी की गई है। हालांकि, कुछ श्रेणियों, जैसे पात्र वरिष्ठ नागरिकों और छोटे बच्चों के लिए निर्धारित रियायतें जारी हैं। सवाल है कि आप अपना पासपोर्ट आवेदन कैसे करें? तो जवाब होगा कि पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर पंजीकरण करें। फिर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें। उसके बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। पुनः निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें। ततपश्चात नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र/पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र में अपॉइंटमेंट बुक करें। साथ ही दस्तावेज सत्यापन और बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी करें। यह सबकुछ होने के बाद आपके आवेदनों व अद्यतन जानकारियों का पुलिस सत्यापन किया जाएगा, जिसमें सबकुछ सही मिलने और प्रशासनिक विवेक की संतुष्टि के बाद पासपोर्ट जारी किया जाएगा। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों से मिली अद्यतन जानकारी के मुताबिक, 1 जुलाई 2026 से ही देशभर के विभिन्न विभागों में कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की सेवाओं पर पड़ेगा, जबकि कुछे क चीजें मुफ्त भी होंगी। इनमें से कुछ बदलाव 1 जुलाई से सीधे प्रभावी हैं, जबकि कुछ जुलाई महीने के दौरान लागू होने वाली समय-सीमाएँ या नियामकीय परिवर्तन हैं। प्रमुख बदलाव इस प्रकार हैं–

एक, आधार में ईमेल अपडेट मुफ्तः 1 जुलाई से निर्धारित अवधि के लिए आधार में ईमेल आईडी अपडेट कराने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।

दूसरा, क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलावः कुछ State Bank of India द्वारा निर्गत क्रेडिट कार्डों के रिवॉर्ड पॉइंट नियम बदलेंगे। जहां कुछ कार्डों के रिवॉर्ड पॉइंट और लाभों में बदलाव होगा, वहीं कुछ खर्चों पर मिलने वाले रिवॉर्ड कम या समाप्त किए गए हैं। जबकि HDFC Bank के कुछ कार्डों पर एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की नई शर्तें लागू होंगी, क्योंकि इसके नियम बदले गए हैं और लाउंज सुविधा के लिए न्यूनतम खर्च जैसी नई शर्तें लागू की गई हैं। तीसरा, बैंकों की मिस-सेलिंग पर RBI के नए नियमः यदि बैंक ग्राहक को गलत तरीके से वित्तीय उत्पाद बेचते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई और ग्राहक संरक्षण के नए प्रावधान लागू होंगे।

चौथा, आयकर रिटर्न (ITR): ITR-1 और ITR-2 दाखिल करने की अंतिम

तिथि 31 जुलाई 2026 है। जुलाई में समय पर रिटर्न दाखिल करने पर विशेष ध्यान देना होगा। पांचवां, रेलवे नियमों में कुछ बदलाव होंगेः रेलवे की कुछ परिचालन और यात्री सुविधाओं से जुड़े नियमों में संशोधन लागू होंगे।

छठा, एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी कीमतेंः हर महीने की तरह 1 जुलाई को इनकी कीमतों की समीक्षा होगी, इसलिए नई दरें घोषित हो सकती हैं।

सातवां, रेलवे के कुछ टिकटिंग और परिचालन नियमों में संशोधन लागू होंगे, जिसके दृष्टिगत यात्रियों को नए दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। खासकर घरेलू और वाणिज्यिक सिलेंडरों की दरों में बदलाव संभव है।

आठवां, EPFO 3.0ः कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से जुड़ी नई डिजिटल सेवाओं का विस्तार शुरू होने की संभावना है।

नौवां, कारों की कीमतेंः कुछ वाहन कंपनियाँ 1 जुलाई से कीमतों में वृद्धि लागू कर सकती हैं।

दसवां, पेट्रोल और डीजलः सरकार ने वाणिज्यिक खरीदारों पर लगाए गए अस्थायी बिक्री प्रतिबंध 1 जुलाई से हटाने का निर्णय लिया है। इससे सामान्य आपूर्ति व्यवस्था बहाल होगी।

समझिए, आम नागरिक पर सबसे अधिक असर किन बदलावों का पड़ेगा?

पासपोर्ट बनवाने वालों पर, आयकर रिटर्न भरने वालों पर, SBI और HDFC क्रेडिट कार्ड उपयोगकताओं पर, बैंक ग्राहकों पर (RBI के नए नियम), LPG/CNG/PNG उपभोक्ताओं पर और रेल यात्रियों पर। स्वाभाविक है कि इससे महंगाई भी बढ़ेगी।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी)

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का उपक्रम)

एनटीएससी, तीसरी मंजिल, ई-ब्लॉक, एनएसआईसी,

ओखला औद्योगिक एस्टेट-III, नई दिल्ली-110020

टेलीफोन नंबर- +011-26382476, 26382477,26382478 फैक्स- 011-26382479

आईएसओ 9001:2015 ई-मेल: nskfdc-msje@nic.in वेबसाइट: http://www.nskfdc.nic.in

कॉर्पोरेट पहचान संख्या :U74899DL1997NPL084652 पैन नंबर AAGCN7818N जीएसटी नंबर 07AAGCN7818N1ZU

पृष्ठभूमि:

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व वाला उपक्रम है, जिसकी स्थापना 24 जनवरी 1997 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत एक "गैर-लाभकारी" कंपनी के रूप में की गई थी। यह अक्टूबर, 1997 से देश भर में सफाई कर्मचारियों (कचरा बीनने वालों सहित), मैनुअल स्कैवेंजरों और उनके आश्रितों के सर्वांगीण सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए अपनी विभिन्न ऋण और गैर-ऋण आधारित योजनाओं के माध्यम से एक शीर्ष निगम के रूप में कार्यरत है। ऋण योजनाओं को राज्य सरकारों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी)/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा नामित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है, जिनके साथ एनएसकेएफडीसी ने इस संबंध में समझौता ज्ञापन निष्पादित किया है।

ऋण योजनाएं:

एनएसकेएफडीसी अपने लक्षित समूह के लिए विभिन्न ऋण योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है, जिसके अंतर्गत रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसका विवरण निम्नलिखित है: -

क्र सं	योजना का नाम	अधिकतम सीमा	ब्याज दर		पुनर्भुगतान
			माध्यम अभकरणों हेतु	लाभार्थी हेतु	
1	मियादी ऋण योजना	रु.10.00लाख तक	4% प्रतिवर्ष	8% प्रतिवर्ष	10 वर्ष*
		रु.10.00 लाख से अधिक रु. 15.00 लाख तक	4.5% प्रतिवर्ष	9% प्रतिवर्ष	
2	महिला अधिकारिता योजना (मई)	रु. 2.00 लाख	3% प्रतिवर्ष	7% प्रतिवर्ष	5 वर्ष *
3	महिला समृद्धि योजना	रु. 1.00 लाख	2% प्रतिवर्ष	6% प्रतिवर्ष	3 वर्ष*
4	लघु ऋण योजना	रु. 1.00 लाख	3% प्रतिवर्ष	7% प्रतिवर्ष	3 वर्ष*
5	शिक्षा ऋण भारत के अध्ययन के लिए विदेश मे अध्ययन के लिए (जिन परिवारों की वार्षिक आय रु. 4.50 लाख तक है उन्हे शिक्षा मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत शिक्षा ऋण पर ब्याज की प्रतिपूर्ति की जाएगी)	रु.10.00 लाख (भारत मे अध्ययन के लिए)	2% प्रतिवर्ष	6% प्रतिवर्ष (0.5% प्रतिशत की छूट महिलाओं के लिए)	पाठ्यक्रम व एक वर्ष की अधिस्थगन अवधि की समाप्ती के बाद 5 साल तक।
		रु.20.00 लाख (विदेश मे अध्ययन के लिए)	3% प्रतिवर्ष	7% प्रतिवर्ष (0.5% प्रतिशत की छूट महिलाओं के लिए)	
6	सैनिटरी मार्ट योजना	रु.15.00 लाख	3% प्रतिवर्ष	7% प्रतिवर्ष @	10 वर्ष*
7	हरित व्यवसाय योजना	रु. 7.50 लाख	3% प्रतिवर्ष	6% प्रतिवर्ष	10 वर्ष***
		रु.7.50 लाख से अधिक एवं रु. 15.00 लाख तक	4% प्रतिवर्ष	7% प्रतिवर्ष	
		रु.15.00 लाख से अधिक एवं रु. 30.00 लाख तक	4% प्रतिवर्ष	8% प्रतिवर्ष	
8	भुगतान एवं उपयोग पर आधारित	रु.25.00 लाख	4% प्रतिवर्ष	8% प्रतिवर्ष. @	10 वर्ष**

1

	समुदाए शौचालयों के लिए योजना				
9	**स्वच्छता उद्यमी योजना - "स्वच्छता से सम्पन्नता की ओर" (स्वच्छता संबंधी वाहनों की खरीद हेतु योजना)**				
क	व्यक्ति/स्वय सहायता समूह/संयुक्त सहायता समूह/स्वच्छता कर्मियों के लिए सहकारी समूह	रु. 15.00 लाख (व्यक्ति) रु. 50.00 लाख (स्वंय सहायता समूह/संयुक्त सहायता समूह/सहकारी)	3% प्रतिवर्ष	6% प्रतिवर्ष @	7 वर्ष *
ख	'नगर निगम/ जल बोर्ड/ पी.एच.ई.डी/ केन्टोमेंट बोर्ड/ रेलवे द्वारा नियुक्त निजी एजेंसियां/ ठेकेदार।		4% प्रतिवर्ष	8% प्रतिवर्ष (समय पर पुर्नभुगतान करने पर 1 प्रतिशत की छूट)	
	स्वच्छता उद्यमी योजना (यूएनबी को रियायती ऋण)				
ख	नगर निगम/नगरपालिका/जल बोर्ड/सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग/छावनी बोर्ड/रेलवे आदि	विभिन्न स्वच्छता गतिविधियों जैसे नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, भुगतान एवं उपयोग सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, अपशिष्ट से खाद बनाने वाली इकाइयां, अपशिष्ट संग्रहण एवं पृथक्करण इकाइयों के लिए रियायती ऋण के रूप में अंतर निधि, जिनकी लागत अधिकतम 50 लाख रुपये प्रति इकाई तक होगी।	NA	7% प्रतिवर्ष (समय पर पुर्नभुगतान करने पर 1 प्रतिशत की छूट)	7 वर्ष *
		स्वच्छता संबंधी उपकरण/वाहनों की खरीद के लिए, जिनकी लागत अधिकतम 75 लाख रुपये प्रति इकाई तक होगी।	NA	7% प्रतिवर्ष (समय पर पुर्नभुगतान करने पर 1 प्रतिशत की छूट	

*120 दिन की क्रियान्वयन अवधि एवं 180 दिन की स्थगन अवधि के उपरांत।

** 180 दिन की क्रियान्वयन अवधि एवं 180 दिन की स्थगन अवधि के उपरांत।

*** 180 दिन की स्थगन अवधि सहित।

#90 दिन की क्रियान्वयन अवधि एवं 90 दिन की स्थगन अवधि के उपरांत।

@ महिला लाभार्थियों को 1 प्रतिशत की ब्याज में छूट एवं समय पर भुगतान करने पर 0.5 प्रतिशत की ब्याज में छूट।

2

और अब खेल के मैदान में भी उतरेगा भारतीय सर्व समाज महासंघ

खिलाड़ी युवा युवतियों को देगा प्रोत्साहन भेंट करेगा खेल संबंधित सामग्री/किट

भारत के सर्व समाज का विकास एवं उत्थान करने वाली एक एकमात्र महा संस्था भारतीय सर्व समाज महासंघ द्वारा लोगों को आवश्यकता का सामान वितरित करने के साथ-साथ अब खेलों का आयोजन भी करने जा रही है इसी कड़ी में शीघ्र ही संस्था द्वारा ग्राम तिसंग जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में शीघ्र ही एक उरफप्रोजेक्ट के अंतर्गत खेलों का टूनार्मेंट कर रही है जिसके अंतर्गत सैकड़ो युवाओं को क्रिकेट की खेलने की किट वॉलीबॉल खेलने की किट तथा कबड्डी जैसे खेल को बढ़ावा देते हुए उसके जूते एवं मोजे आदि भी खिलाड़ियों को संस्था की ओर से भेंट किए जाएंगे संस्था के अध्यक्ष रामकुमार वालिया ने बताया कि भारतीय सर्व समाज महासंघ अलग-अलग समय पर अलग-अलग प्रकार के आयोजन करती है इसी कड़ी में संस्था द्वारा अब उरफकार्यों के अंतर्गत खेलों के आयोजन कर रही है जिसमें जहां खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा विजेता खिलाड़ियों को मेडल दिए जाएंगे वही उनको खेलो में उपयोग किए जाने वाली कीट आदि भी भेंट की जाएगी साथ ही ऐसे खेलों को भी संस्था द्वारा आयोजित किया जाएगा जो विलुप्त होते जा रहे हैं जैसे कबड्डी का खेल है पहले जमाने में यह खेल खेला जाता था इससे युवाओं में शक्ति का संचार होता था उनका स्वास्थ्य अच्छा होता था लेकिन अब यह खेल विलुप्त होता जा रहा है संस्था द्वारा पुनः कबड्डी के आयोजन किए जाएंगे इसी के साथ-साथ क्रिकेट टूनार्मेंट आयोजित कराए जाएंगे जिसमें खिलाड़ियों को क्रिकेट किट भेंट की जाएगी इसी के साथ-साथ वॉलीबॉल का भी आयोजन कराया जाएगा जिसमें वॉलीबॉल से संबंधित खेलने के समान युवाओं को भेंट के जाएंगे श्री वालिया ने बताया कि आज भारतीय सर्व समाज महासंघ भारत का सबसे बड़ा सामाजिक संस्था बन चुका है जिसमें पूरे देश में 5 लाख से अधिक सदस्य हैं तथा संस्था द्वारा विगत 5 वर्षों में किसी न किसी रूप से 10 लाख से अधिक लोगों को आवश्यकता का सामान बैठ किया गया है जो निरंतर जारी है

सिक्किम-बंगाल के रिश्तों को नई रफ्तार? शुभेंदु से मिले प्रेम तमांग, तीस्ता ड्रेजिंग व इन मुद्दों पर बनी सहमति

सिक्किम और पश्चिम बंगाल के बीच हुई उच्चस्तरीय बैठक में सिलीगुड़ी में सुस्वास्थ्य भवन निर्माण, सिक्किम की टैक्सियों के परमिट दोगुने करने और तीस्ता नदी में गाद प्रबंधन पर सहमति बनी। दोनों राज्यों ने बुनियादी ढांचे, परिवहन और आपदा प्रबंधन में सहयोग बढ़ाने का संकल्प भी दोहराया। सिक्किम और पश्चिम बंगाल के बीच बुनियादी ढांचे, परिवहन और आपदा प्रबंधन से जुड़े कई अहम मुद्दों पर गुरुवार को महत्वपूर्ण प्रगति हुई। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कोलकाता स्थित नवान्न (सचिवालय में) पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। बैठक में सिलीगुड़ी में प्रस्तावित ह्यसुस्वास्थ्य भवनह्ल के निर्माण, सिक्किम-पंजीकृत टैक्सियों के लिए परमिट बढ़ाने तथा 2023 की ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ) के बाद तीस्ता नदी में बढ़े गाद के वैज्ञानिक प्रबंधन जैसे मुद्दों पर सहमति बनी। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी और उनके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं। दोनों नेताओं ने अंतरराज्यीय सहयोग को और मजबूत बनाने पर भी चर्चा की। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले ने बैठक की जानकारी अपने सोशल मीडिया में साझा किया। सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में सिलीगुड़ी के एसएनटी कॉम्प्लेक्स में प्रस्तावित ह्यसुस्वास्थ्य भवन, सिक्किमह्ल के निर्माण को मंजूरी देना शामिल है। यह परियोजना उत्तर बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में इलाज कराने आने वाले सिक्किम के मरीजों और उनके परिजनों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने संबंधित विभाग को आवश्यक अनुमति जारी करने का निर्देश भी दिया है। बैठक में दोनों राज्यों के बीच पारस्परिक परिवहन समझौते की भी समीक्षा की गई। लंबे समय से लंबित मांग को स्वीकार करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने सिक्किम-पंजीकृत टैक्सियों के लिए काउंटर सिग्नेचर परमिट की संख्या 3,000 से बढ़ाकर 6,000 करने का निर्णय लिया। इस फैसले से अधिक संख्या में सिक्किम की टैक्सियां सिलीगुड़ी सहित पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में परिचालन कर सकेंगी। इससे टैक्सी चालकों को सीधा लाभ मिलने के साथ दोनों राज्यों के बीच यातायात और व्यापारिक संपर्क भी मजबूत होगा। बैठक में वर्ष 2023 की ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के बाद तीस्ता नदी के तल में बढ़ी गाद और उसके कारण राष्ट्रीय राजमार्ग-10 को हुए नुकसान पर भी विस्तार से चर्चा हुई। दोनों राज्यों ने वैज्ञानिक तरीके से तीस्ता नदी की ड्रेजिंग कर तलछट प्रबंधन को संयुक्त रूप से आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। माना जा रहा है कि इससे राष्ट्रीय राजमार्ग-10 की सुरक्षा और सिक्किम की सड़क संपर्क व्यवस्था को दीर्घकालिक मजबूती मिलेगी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने पश्चिम बंगाल सरकार की त्वरित और सकारात्मक पहल के लिए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन फैसलों से दोनों राज्यों के बीच सहयोग का नया अध्याय शुरू होगा और आम लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

बेहद खूबसूरत है सिक्किम के ये पर्यटन स्थल, बजट में करें दोस्तों या परिवार संग सैर

सिक्किम एक छोटा लेकिन खूबसूरत राज्य है, जो देश के पूर्वी हिमालय में स्थित है। सिक्किम एक बेहद ही सुंदर और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर राज्य है और दोस्तों या परिवार संग घूमने के लिए एक अच्छा स्थल माना जाता है। यह राज्य प्राकृतिक सौंदर्य, बायोडायवर्सिटी, दर्शनीयता और आदिवासी संस्कृति के लिए जाना जा सकता है। इसके अलावा सिक्किम में कई प्रमुख बौद्धिक और हिन्दू धार्मिक स्थल हैं, जिनके यात्रा के दौरान दर्शन किए जा सकते हैं। गंगटोक शहर पेमायांग्त्से गोंपा और युक्सोम जैसे दर्शनीय स्थल हैं जो पहाड़ों की चोटियों, झीलों, और घने वनस्पति के बीच स्थित हैं। सिक्किम के बाघों का संरक्षण भी महत्वपूर्ण है और पेमायांग्त्से गोंपा में अद्वितीय धार्मिक अनुभव मिलता है। यहाँ की आदिवासी संस्कृति और परंपरा भी आकर्षक है। सिक्किम वनस्पति और जीवजंतु बियोडाइवर्सिटी के लिए भी प्रसिद्ध है। अगर सिक्किम की यात्रा करना चाहते हैं तो यहां के सुंदर पर्यटन स्थलों के बारे में जानिए, साथ ही कब व कैसे

सिक्किम की यात्रा कर सकते हैं।

सिक्किम घूमने का सही समय

सिक्किम को प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जा सकता है। अक्टूबर से मार्च के बीच सिक्किम घूमने के लिए बेहतर समय होता है। इन महीनों में यहां का मौसम शुष्क और सुहावना होता है और यहाँ के पहाड़ों के दर्शन का आनंद लिया जा सकता है।

कैसे पहुंचे सिक्किम

दिल्ली से सिक्किम 1627 किमी दूर है। सिक्किम जाने के लिए हवाई मार्ग, ट्रेन और बस तीनों का विकल्प मिलता है। रेल मार्ग के जरिए सिक्किम पहुंच सकते हैं। सिक्किम का प्रचलित रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी है, यहां आपको कई जगहों से ट्रेन मिल जाएगी। इसके अलावा हवाई जहाज से सिक्किम जाएं तो गंगटोक हवाई अड्डा सबसे करीब है। बागडोगरा व गुवाहाटी भी फ्लाइट से जा सकते हैं। बागडोगरा हवाई अड्डे से आपको देश के अलग अलग जगहों के लिए हवाई सेवा मिल सकती है। गंगटोक या सिक्किम के अन्य शहरों में पहुंचने के बाद आगे की यात्रा स्थानीय परिवहन, टैक्सी आदि से की जा सकती है। सड़क मार्ग से सिक्किम जाना चाहते हैं तो सिलीगुड़ी से बस सुविधा मिल जाएगी। दिल्ली, कोलकाता की बसें भी यहीं पहुंचती है।

सिक्किम के सबसे सुंदर पर्यटन स्थल

गंगटोक

गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। यहाँ पर घूमने के लिए कांचांजुंगा नेशनल पार्क, गंगटोक महाकाली मंदिर, एनची गोंपा, और अच्छे खाने के स्थल हैं। गंगटोक से आप खांचेंजूँगा और हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं।

पेमायंग्त्से गोंपा और पेलिंग

यह गोंपा सिक्किम का सबसे प्रसिद्ध गोंपा है और यहाँ के विचारणीय दर्शन हैं। गोंपा की स्थिति हिमालय की चोटी पर है, और यहाँ से आपको अद्वितीय पर्वतीय दृश्यमान होता है। सिक्किम के पश्चिम जिले में खूबसूरत शहर पेलिंग बसा है जो गंगटोक के बाद दूसरा बड़ा टूरिस्ट प्लेस है। यहां आप ट्रेकिंग, माउंटेन बाइकिंग, रॉक क्लाइम्बिंग जैसी एक्टिविटीज का लुत्फ उठा सकते हैं।

लाचेन

लाचेन यहाँ का एक छोटा सा गाँव है और यह पेमायंग्त्से गोंपा के बगीचे की ओर से जाने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पास में हिमालय की चोटी पर एक सुंदर झील है, जिसका नाम गुरूडोंगमर है।

युक्सोम

हर-भरे पहाड़ों से ढका युक्सोम सिक्किम का एक अन्य प्राकृतिक सौंदर्य स्थल है जो खासतौर पर सिक्किम की बाघों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप भारतीय बाघों को देख सकते हैं। यहां कई ऐतिहासिक स्मारक, प्राचीन मठ, झरने और झीलें मौजूद हैं। यहां घूमने के लिए गर्मी का मौसम सबसे बेहतर है।

बिना बोले Huma Qureshi ने आँखों से लिखा अभिनय का नया व्याकरण, चंकी पांडे का खौफनाक ट्रांसफॉर्मेशन

पारंपरिक मसाला फिल्मों और घिसी-पिटे थ्रिलर फॉर्मूलों से अलग जब कोई सिनेमा अपनी एक नई राह चुनने का जोखिम उठाता है, तो सिनेप्रेमियों का ध्यान उसकी तरफ खिंचा चला आता है। इस शुक्रवार बड़े पर्दे पर रिलीज हुई निर्देशक नचिकेत सामंत की फिल्म 'बेबी डू डाई डू' (Baby Do Die Do) हिंदी सिनेमा के इसी ढर्रे को तोड़ने का एक साहसिक प्रयास है। फिल्म का शीर्षक पहली बार सुनने में थोड़ा अजीब या उलझा हुआ लग सकता है, लेकिन कहानी की गहराई में उतरते ही इसका गणित साफ हो जाता है। दरअसल, यह नाम मुख्य किरदार 'बेबी करमरकर' के उपनाम से निकला है—'कर-मर-कर' (Kar-Mar-Kar) यानी 'डू, डाई, डू' (Do, Die, Do)। 2 घंटे 5 मिनट की यह 'A' सर्टिफाइड एक्शन-क्राइम-थ्रिलर पल्प फिक्शन और डार्क ह्यूमर की एक ऐसी अनोखी दुनिया रचती है, जहां खामोशी की गूंज हथियारों की आवाज से कहीं ज्यादा तेज है। फ़िल्में फिल्म की शुरुआत किसी शोर-शराबे से नहीं, बल्कि एक डरावनी खामोशी से होती है। मुख्य किरदार 'बेबी' (हुमा कुरैशी) न तो बोल सकती है और न ही सुन सकती है। बचपन में एक अनजाने सफर के दौरान बेबी अपनी जुड़वां बहन के साथ एक खाली आलीशान फाइव-स्टार होटल में दाखिल हो जाती है, जहां दोनों बहनें अनजाने में एक खौफनाक मर्डर की चश्मदीद बन जाती हैं। बेरहम कातिल बेबी की जुड़वां बहन का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार देता है, जबकि बेबी किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकलती है। एक शराबी पिता के साये में पली-बढ़ी बेबी के सीने में उस रात बदले की जो चिंगारी सुलगती है, वह उसे एक सामान्य जीवन से बहुत दूर ले जाती है। बड़ी होने पर बेबी का सामना पीएम जैन (चंकी पांडे) से होता है, जो उसे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग (सुपारी लेकर हत्या करने) के स्याह और बेरहम अंडरवर्ल्ड में ले आता है। अपनी शारीरिक अक्षमता को कमजोरी बनाने के बजाय बेबी उसे अपनी सबसे बड़ी ढाल बना लेती है और इस अपराध जगत की सबसे अचूक 'हिटवुमन' बनकर उभरती है। कातिलाना अंदाज: बेबी का मर्डर करने का तरीका बेहद जुदा है। वह किसी पारंपरिक गन या चाकू के बजाय एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए 'छाते' (Umbrella) का इस्तेमाल करती है, जो देखने में जितना साधारण है, एक्शन में उतना ही जानलेवा। शहर में एक के बाद एक होने वाली हाई-प्रोफाइल हत्याएं पुलिस महकमे को हिलाकर रख देती हैं। हालांकि, बेबी का असली मकसद सिर्फ एक पेशेवर कातिल बने रहना नहीं है; वह तो उस बड़े कॉर्पोरेट और क्रिमिनल नेक्सस को भेदकर अपनी बहन के असली कातिल तक पहुंचना चाहती है। इसी बीच उसकी जिंदगी में प्यार की दस्तक होती है, और कहानी प्रतिशोध से आगे बढ़कर पहचान, जज्बात और मुक्ति के मुहाने पर जा खड़ी होती है। हुमा कुरैशी (बेबी): यह फिल्म पूरी तरह से हुमा के कंधों पर टिकी है और यह उनके करियर की सबसे परिपक्व परफॉर्मेंस है। बिना एक भी शब्द बोले, सिर्फ अपनी आंखों के उतार-चढ़ाव, चेहरे की सूक्ष्म रेखाओं और सधी हुई बॉडी लैंग्वेज से उन्होंने बेबी के दर्द और आक्रोश को जीवंत कर दिया है। पर्दे पर बिना किसी लाउड मेकअप के खुद को पेश करने का उनका फैसला किरदार को बेहद वास्तविक (Raw) बनाता है। वह एक पल में क्रूर शूटर तो दूसरे ही पल एक संवेदनशील प्रेमी के रूप में ढल जाती हैं। चंकी पांडे (पीएम जैन): चंकी पांडे इस फिल्म के सबसे बड़े 'सरप्राइज पैकेज' हैं। अपनी पुरानी कॉमिक छवि को पूरी तरह ध्वस्त करते हुए उन्होंने अंडरवर्ल्ड के एक शांत, गंभीर और बेहद क्रूर गैंग लीडर के रूप में स्क्रीन पर खौफ पैदा किया है। सिकंदर खेर (ज़फ़र): एक चालाक और लालची बिल्डर के निगेटिव रोल में सिकंदर खेर ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है, जो कहानी के तनाव को और गहरा करती है।

GIVE THEIR DREAMS THE WINGS THEY DESERVE.

IDBI Bank's Education Loans make sure that
when opportunity comes knocking, finances never come in the way.

Hassle-free loans

Quick processing

Flexible collaterals

Loans provided for a wide range of courses both in India and abroad

*T & C Apply

Toll Free Numbers: 1800-209-4324 / 1800-22-1070
Non-Toll Free Number : 022-67719100
Visit us : www.idbi.bank.in

IDBI BANK
Bank Aisa Dost Jaisa

मेश

मेष राशि के जातकों के लिए साल के सातवें महीने यानि जुलाई महीने की शुरूआत थोड़ी उतार-चढ़ाव लिए रहने वाली है। इस दौरान मेष राशि के जातकों को अपने करियर और कारोबार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान आपकी एक छोटी सी गलती जी का जंजाल साबित हो सकती है। छात्र वर्ग का मन इस दौरान पढ़ाई से उचट सकता है।

कर्क

नौकरीपेशा लोगों की उच्च अधिकारियों के साथ अच्छी ट्यूनिंग देखने को मिलेगी। माह के मध्य से उत्तरार्ध तक के समय में आपको अपनी वाणी और व्यवहार में विनम्रता रखनी होगी। इस दौरान समस्याओं को सुलझाते समय अपनी बुद्धि और विवेक का पूरा इस्तेमाल करना होगा अन्यथा चीजें बनने की बजाय और बिगड़ सकती हैं।

तुला

ऐसे में तुला राशि के जातकों को अपने महत्वपूर्ण कार्य जुलाई महीने की शुरूआत में निबटाने का प्रयास करना चाहिए। चूंकि माह के पूर्वार्ध में आपको सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा, इसलिए इस दौरान आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरा जोर लगा दें। माह के पहले सप्ताह में रोजी-रोजगार के सिलसिले में की गई यात्रा सार्थक साबित होगी।

मकर

नौकरीपेशा लोगों को जुलाई महीने के दूसरे सप्ताह में कार्यक्षेत्र में अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। हालांकि इस दौरान आपके सीनियर आप पर पूरी तरह से मेहरबान रहेंगे, जिससे आप सभी चुनौतियों को पार करते हुए अपने आप को बेस्ट साबित करने में अंततः कामयाब हो जाएंगे। व्यवसाय से जुड़े लोग इस दौरान कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं।

वृष

इस दौरान संतान पक्ष से जुड़ी किसी बड़ी चिंता दूर होने पर आप सुकून महसूस करेंगे। भूमि-भवन, वाहन आदि क्रय विक्रय करने का योग बनेगा। रिश्ते-नाते की दृष्टि से पूरा महीना सामान्य रहने वाला है। परिजनों के साथ प्रेम और समन्वय बना रहेगा। खट्टी-मीठी तकरार के साथ प्रेम संबंध सामान्य बना रहेगा। माह के उत्तरार्ध में वाहन सावधानीपूर्वक चलाएं

सिंह

इस दौरान आपके मान-सम्मान और धन लाभ में वृद्धि होगी। व्यवसाय को आगे बढ़ाने के प्रयास सार्थक साबित होंगे। ाह के मध्य में आपको अपने काम को थोड़ा सावधानी के साथ करना होगा। इस दौरान लोगों के साथ वाद-विवाद से बचते हुए अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से फोकस करना उचित रहेगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को माह के उत्तरार्ध लाभ कमाने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे।

वृश्चिक

करियर कारोबार के सिलसिले में कई यात्राएं सुखद एवं लाभप्रद रहेंगी। हालांकि इस समय आपको सेहत से जुड़ी समस्या झेलनी पड़ सकती है। मौसमी बीमारी अथवा कोई पुराना रोग उभरने से शारीरिक कष्ट मिल सकता है। माह के उत्तरार्ध में आपको लोगों के साथ वाद-विवाद करने से बचना होगा। किसी को ऐसे शब्द न कहें जिससे वर्षों से बने संबंध बिगड़ जाएं।

कुम्भ

इस महीने आपको सोचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास करने होंगे। छोटे-छोटे कार्यों को भी पूरा करने के लिए अधिक भागदौड़ करना पड़ सकता है। बेवजह की चीजों पर धन खर्च होने पर जहां वित्तीय स्थिति गड़बड़ाएगी वहीं आय के माध्यम में अड़चन आने से मन खिन्न रहेगा। माह की शुरूआत में घरेलू समस्याएं हावी रहेंगी। घर की मरम्मत अथवा किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर बड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ सकती है।

मिथुन

इस दौरान आपको लोगों के सामने अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखना होगा अन्यथा लोग अर्थ का अनर्थ करके लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखना होगा। कारोबार की दृष्टि से माह के मध्य से लेकर उत्तरार्ध तक का समय चुनौती भरा रहेगा। इस दौरान धन से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें।

कन्या

महीने की शुरूआत थोड़ी खचीर्ली रहने वाली है। इस दौरान आप अपनी जरूरतों और सुख सुविधा से जुड़ी चीजों पर बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं। कन्या राशि के जातकों को माह के पहले सप्ताह में करियर-कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करना पड़ सकता है। यात्रा थकान भरी लेकिन उम्मीद के मुताबिक सफल और लाभप्रद होगी।

धनु

यह महीना सेहत, संबंध और करियर कारोबार की दृष्टि से काफी उतार-चढ़ाव लिए रहने वाला है। माह की शुरूआत में आपको कामकाज के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है जो आपके लिए काफी हितकर साबित होगी। इस दौरान आपके संबंध सत्ता-सरकार से जुड़े प्रभावी लोगों के साथ होंगे।

मीन

इस दौरान भूमि-भवन आदि से जुड़े विवाद किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से सुलझ सकते हैं। रिश्तों पैदा हुई खटास भी गलतफहमियों के दूर होने पर भी कम होगी। लव लाइफ हो या फिर मैरीड लाइफ इसे बेहतर बनाने के लिए आपको अपने पार्टनर से विनम्रता से पेश आना होगा और उसकी आवश्यकताओं को समझना होगा। माह के उत्तरार्ध का समय करियर-कारोबार की दृष्टि से राहतकारी कहा जाएगा। सकती है।

INDSMART
इंडियन बैंक Indian Bank
अपने धन का निवेश करें और सुनिश्चित प्रतिलाभ पाएं
इंड ग्रीन 500
मीयादी जमा
500 दिनों के लिए निवेश करें और पाएं 7.15%* तक प्रतिवर्ष
सामान्य नागरिक
6.40% प्रतिवर्ष
वरिष्ठ नागरिक
6.90% प्रतिवर्ष
अति वरिष्ठ नागरिक
7.15% प्रतिवर्ष
7.15%* प्रतिवर्ष
500 दिन मीयादी जमा
*नियम और शर्तें लागू
1800-1700 | www.indianbank.bank.in | हमें फॉलो करें: | साइबर अपराध हेल्पलाइन : 1930

जय जवान ! जय किसान !

किसान एकता
जिंदाबाद !

किसान हमारी
शान !

किसान उपभोक्ता बहु-राज्य सहकारी समिति लिमिटेड
— सहकारिता द्वारा समृद्धि —

उर्वरक | बीज | भंडारण | विपणन | सहकारिता

किसान उपभोक्ता बहु-राज्य सहकारी समिति लिमिटेड

सहकारिता द्वारा समृद्धि

— किसानों के हित में, किसानों के साथ —

किसानों की एकता
हमारी ताकत
किसानों का सम्मान
हमारा संकल्प

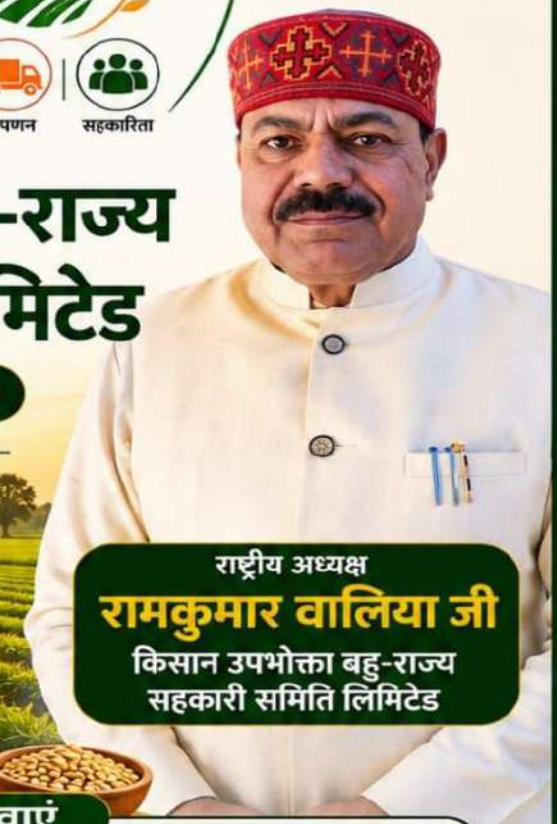

राष्ट्रीय अध्यक्ष
रामकुमार वालिया जी
किसान उपभोक्ता बहु-राज्य
सहकारी समिति लिमिटेड

हमारी प्रमुख सेवाएं

उर्वरक
उत्तम गुणवत्ता वाले उर्वरक उचित दर पर उपलब्ध।

बीज
उत्तम मूल्य के प्रमाणित बीज समय पर उपलब्ध।

भंडारण सुविधा
धान, गेहूँ एवं अन्य फसलों का सुरक्षित भंडारण।

विपणन सुविधा
फसलों के लिए आसान शर्तों पर विपणन की सुविधा।

सहकारिता
किसान हित सर्वोपरि किसानों के अधिकार, सम्मान और कल्याण के लिए समर्पित।

★ Regd. No.: MSCS/CR/1665/2026 ★
भारत सरकार, सहकारिता मंत्रालय के अधीन पंजीकृत
(Multi State Cooperative Societies Act, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत)

Head Office: 8, Krishna Nagar, Near Bada Gurudwara,
Safdarjung Enclave, New Delhi – 110029

+91-8527156473 | 011-26197882 | 9868347267
9760639920 | fmcsl343267@gmail.com